

₹ 20

www.kewalsach.com

निर्भीकता हमारी पहचान

जनवरी 2022

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

जाको राखे साईयां

मार सके न कोय

RNINO-BIHIN/2006/18181, DAVP NO.-129888, POSTAL REG. NO. P-JE-35



प्रधानमंत्री सुरक्षा

जन-जन की आवाज है केवल सच

विश्व का पहला
केवल सच
हिन्दी मासिक पत्रिका

Kewalachlive.in
वेब पोर्टल न्यूज
24 घंटे आपके साथ



आत्म-निर्भर बनने वाले युवाओं को सपोर्ट करें

आपका छोटा सहयोग, हमें मजबूती प्रदान करेगा



www.kewalsach.com

www.kewalsachlive.in

-: सम्पर्क करें :-

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान संख्या-28/14,

कंकड़बाग, पटना (बिहार)-800020, मो०:-9431073769, 9308815605



जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ



सत्येन्द्र नाथ बोस
01 जनवरी 1894



नाना पाटेकर
01 जनवरी 1951



विद्या बालन
01 जनवरी 1978



ममता बनर्जी
05 जनवरी 1955



दीपिका पादुकोण
05 जनवरी 1986



विपाशा वसु
07 जनवरी 1979



ए.आर. रहमान
08 जनवरी 1966



फराह खान
09 जनवरी 1965



हतीक रौशन
10 जनवरी 1974



राहुल द्रविड
11 जनवरी 1973



स्वामी विवेकानन्द
12 जनवरी 1863



प्रियंका गांधी
12 जनवरी 1972



राकेश शर्मा
13 जनवरी 1963



मायावती
15 जनवरी 1956



जावेद अख्तर
17 जनवरी 1945



सुभाष चन्द्र बोस
23 जनवरी 1897



बाल ठाकरे
23 जनवरी 1926



बाँबी दिओल
27 जनवरी 1967



लाला लाजपत राय
28 जनवरी 1865



प्रिति जिंटा
31 जनवरी 1975

निर्भीकता हमारी पहचान

www.kewalsach.com

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

Regd. Office :-
East Ashok, Nagar, House
No.-28/14, Road No.-14,
kankarbagh, Patna- 8000 20
(Bihar) Mob.-09431073769,
E-mail :- kewalsach@gmail.com

Corporate Office:-
Riya Plaza, Flat No.-303,
Kokar Chowk, Ranchi-834001
(Jharkhand)
Mob.- 09955077308,
E-mail:-
editor.kstimes@rediffmail.com

Delhi Office :-
Sanjay Kumar Sinha
A-68, 1st Floor, Nageshwar talla,
Shastri Nagar, New Delhi-110052
Mob.- 09868700991,
09955077308
kewalsach_times@rediffmail.com

Kolkata Office :-
Ajeet Kumar Dube,
131 Chitranjan Avenue,
Near- md. Ali Park,
Kolkata- 700073
(West Bengal)
Mob.- 09433567880,
09339740757

ADVERTISEMENT RATES PER ISSUE

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE	Qr. PAGE
Cover Page	5,00,000/-	N/A	N/A
Back Page	1,60,000/-	N/A	N/A
Back Inside	1, 00000/-	60,000/-	35000
Back Inner	90,000/-	50,000/-	30000
Middle	1,50,000/-	N/A	N/A
Front Inside	1, 00000/-	60,000/-	40000
Front Inner	90,000/-	50,000/-	30000

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
Inner Page	60,000/-	35,000/-

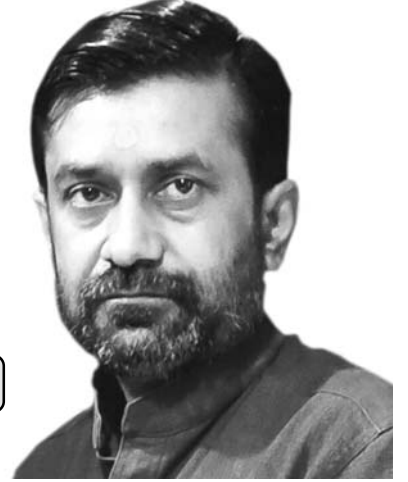
1. एक साल के नियमित विज्ञापन पर पत्रिका के वेबसाइट www.kewalsach.com के फ्रंट पर भी विज्ञापन निःशुल्क तथा आपका वेबसाइट से सीधा लिंक हो सकता है।
2. एक साल के नियमित विज्ञापन पर 10 प्रतिशत की रियायत।
3. आपके प्रोडक्ट या संगठन के प्रचार-प्रसार हेतु आलेख को उचित स्थान।
4. पत्रिका द्वारा सामाजिक कार्य में आपके संगठन/प्रोडक्ट का बैनर/फ्लैक्स को उचित स्थान देकर आपके संगठन का व्यापक प्रचार-प्रसार।
5. विज्ञापन का भुगतान चेक या आर.टी.जी.एस. से ही मान्य होगा।

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

हमला

चुनावी या राजनीति

अपनी प्रतिक्रिया हमारे ई-मेल पर दें:- editor.kstimes@rediffmail.com

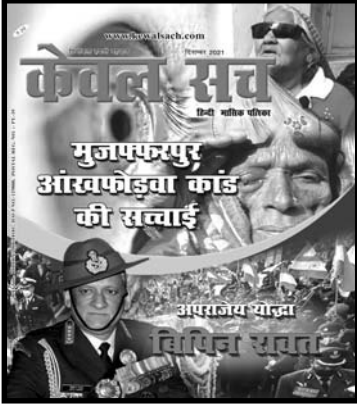


रा

जस्थान के चुरू में देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी ने खुले मंच से दहाड़ते हुए कहा था कि “देश नहीं मिटने दूंगा और देश नहीं झुकने दूंगा” और देश की जनता का मिजाज अपने पक्ष में करने में कामयाब भी हो गये, वहीं विपक्ष इस स्लोगन को राजनीतिक बयान साबित करने में लगा है और कहता है की देश को बर्बाद कर दिया है। हमला हो जाने के बाद हमले की समीक्षा के बजाय उसपर राजनीति करने की प्रथा का जन्म भारत के लोकतंत्र में ले लिया है। हाल में ही सेना के सीडीएस विपिन रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गयी और यह पहले सीडीएस बने और शहीद भी हो गये। विपक्ष और आमजनता भी इस दुर्घटना को राजनीतिक चश्मों से देख रही है। आखिरकार इस दुर्घटना के पीछे के रहस्य से पर्दा कब उठेगा की किन कारणों की वजह से यह हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई? वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के पहले पुलवामा की घटना में 45 जवान शहीद हो गये और देश के पक्ष - विपक्ष ने शहादत से कहीं ज्यादा इसको राजनीतिक हमले के रूप में स्वीकार किया और सभाओं में जमकर चर्चा होती रही परन्तु इस हमले के पीछे के कई महत्वपूर्ण तथ्य आज भी अनसुलझे हैं। पिछले वर्ष 2021 में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी हमले हुए और जमकर मीडियाबाजी हुई लेकिन ममता बनर्जी ने स्पष्ट बहुमत से जीतकर इस हमले को राजनीतिक मोड़ दिया गया। आजकल राजनीति में बने रहने के लिए सहानुभूति वोट हासिल करने के प्रयास में इस प्रकार के हमले खुद भी करवाये जाते हैं तथा कभी-कभार लगातार सत्ता से बाहर रहने की वजह से विपक्ष भी इस प्रकार की धिनीनी राजनीति को अंजाम देने की कोशिश करते हैं जो बाद में दल-बदल करने वाले राजनेताओं के बयान से समझा जा सकता है। परमाणु पनडुब्बी के एटोमिक पावर प्लांट पर कार्य रहे के० के० जोशी एवं आसीम की मौत भी आज तक सच्चाई का खुलासा नहीं हो सका, क्यों? तथा इसरो के वरीष्ठ वैज्ञानिक तपन मिश्रा की मौत खाने में जहर की वजह से हुई थी, आखिर यह हमले राजनीतिक हैं या वास्तविक? आखिर यह सुरक्षा चुक है या फिर राजनीतिक षडयंत्र? पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गाँधी की हत्या हो फिर संजय गाँधी की मौत को राजनीति से जोड़कर देखा जाना और तो और कांग्रेस पार्टी के वरीष्ठ राजनेता राजेश पायलट की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गयी उसकी आज तक समीक्षा का ही विषय बनकर रह गया लेकिन उसकी वास्तविक पड़ताल सामने नहीं आयी। क्या ऐसी घटनाओं की सच्चाई सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए? सुरक्षा एजेंसी फेल है या फिर वह भी प्रोटोकॉल से मजबूर हैं? देश की राजनीति एवं राजनेताओं का गिरता स्तर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश के लाल किला पर हमले करके झंडे के साथ खिलवाड़ करने वाले पर क्या कार्रवाई हुई? और क्या इसके लिए सिर्फ हमलावर ही जिम्मेवार हैं? पुलिस और राष्ट्रीय सुरक्षा में लगी एजेंसी जिम्मेवार नहीं है? पाकिस्तान और चीन तो देश की सीमा पर आतंकवाद का परिचय दे रहा है जिसका मुंहतोड़ जवाब सेना के जवान दे रहे हैं लेकिन देश के भीतर राजनीतिक आतंकवाद से कौन लड़ेगा और देश कैसे बचेगा? देश की सुरक्षा में शामिल सुरक्षा एजेंसी और मीडिया को सक्रिय रूप पर भी ग्रहण लग चुका है जिसकी वजह से देश की वास्तविक सच्चाई आवाम तक नहीं पहुंच पा रहा है और यही महत्वपूर्ण कारण है की राजनीतिक हमले करके देश की सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या, बेरोजगारी, गरीबी, शिक्षा, चिकित्सा और कृषि के साथ-साथ आपदा का विषय गौण कर दिया जाता है और चुनाव के वक्त विकास के सारे दावे फेल हो जाते हैं और मूल संघर्ष जाति एवं धर्म पर ही ठहर जाती है। कभी सर्जिकल स्ट्राइक तो कभी पुलवामा की घटना को राजनीतिक चश्मों से देखने के पीछे कारण क्या है? देश का सुरक्षा में कहीं न कहीं बड़ी चुक है और इसको स्वीकारने के बजाय इसपर गंदी राजनीति करना देश को फिर से गुलामी की ओर ढुकलने जैसा है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव के वक्त शाहिन बाग की घटना को सिर्फ राजनीतिक चश्मों से देखने के कारण ही आप पार्टी की सरकार बन गयी और चुनाव सम्पन्न होते ही शाहिन बाग की खुंखार घटना को लोग भूल गये या यूँ कहें की राजनेताओं ने शाहिन बाग से ध्यान हटाकर कोरोना संक्रमण पर जा टिका है। हमला हो और उसकी वास्तविक सच्चाई सामने लाने के बजाय उसको राजनीति रंग देने की कोशिश के कारण ही देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में है और इससे निजात दिलाने के बजाय उसपर हो रही राजनीति कहीं न कहीं युवाओं को संकुचित विचार करने पर मजबूर करती है। देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी प्राथमिकता में शामिल ही नहीं करना होगा बल्कि इसको कारगर बनाना ही राष्ट्रहित है।

2014 के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेन्द्र दामोदर दास मोदी के गाँधी मैदान के कार्यक्रम में हुए बम हमले की सच्चाई सार्वजनिक हो चुकी है और भाजपा की गठबंधन वाली सरकार भी बिहार में नियमित रूप से हो रहा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के यात्रा के वक्त भी कई हमले हुए और राजनीति हुई और विपक्ष को हार का मुंह देखा पड़ा। चुनाव के वक्त पीएम और सीएम के काफिले पर हमले को राजनीतिक रूप देकर अपराध को बढ़ावा देने की कोशिश करना और उसपर राजनीतिक बयानबाजी करने की कूटनीति को आमजनता अब समझने लगी है कि आखिरकार चुनाव के वक्त ही हमले क्यों होते हैं? जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनाव के वक्त भी पुलवामा की घटना में शहीद हुए जवानों की प्रति संवेदना से कहीं ज्यादा राजनीति की गई और 2021 में पश्चिम बंगाल के चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी हमले हुए और हमलावर को जेल भेजने के बजाय पक्ष - विपक्ष सिर्फ राजनीति करते रह गये और जनता धर्मसंकेत में अपना फैसला सुना दिया जिसकी कल्पना भाजपा ने नहीं किया था। 05 जनवरी 2022 को पंजाब में प्रधानमंत्री के काफिले पर हमले को लेकर चल रही राजनीति एवं प्रशासनिक कार्रवाई को जनता सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों दृष्टिकोण से खेल चल रहा है। अब सच में भी हमला हो तो जनता उसको राजनीति का ही अंश मानती है और वातावरण ऐसा बना दिया जाता है की लोग मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। राजनीति के गिरते स्तर के कारण लोकतंत्र भी अपाहिज होता जा रहा है और जनता को धर्म एवं जाति के नाम पर आपस में लड़वाकर सत्ता के सिंहासन पर काबिज होने का खेल बदस्तूर जारी है और इसका परिणाम राष्ट्रहित में नुकसानदायक है और युवा सोच को संक्रमित करता

करता



दिसम्बर 2021



हमारा ई-मेल

आपको केवल सच पत्रिका कैसी लगी तथा इसमें कौन-कौन सी खामियाँ हैं, अपने सुझाव के साथ हमारा मार्गदर्शन करें। आपका पत्र ही हमारा बल है। हम आपके सलाह को संजीवनी बूटी समझेगे।

केवल सच

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

द्वारा:- ब्रजेश मिश्र

पूर्वी अशोक नगर, रोड़ नं.- 14, मकान संख्या- 14/28

कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)

फोन:- 9431073769 / 8340360961/ 9955077308

kewalsach@gmail.com, editor.kstimes@rediffmail.com

kewalsach_times@rediffmail.com

अंखफोड़वा कांड

संपादक जी,

केवल सच, पत्रिका निर्भिक एवं बेबाकी से खबर लिखती है जिसकी वजह से मैं प्रत्येक माह की पत्रिका को पढ़ता हूँ। मुजफ्फरपुर में हुए अंखफोड़वा कांड को पत्रकार शशि रंजन सिंह एवं राजीव शुक्ला ने बिना लाग लपेट के सरकार, विभाग एवं डॉक्टरों की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। नीतीश कुमार एवं मंगल पाण्डेय ने नैतिकता खो दिया है, यही सच्चाई है क्योंकि जिस राज्य में चिकित्सा एवं शिक्षा का मजाक बना दिया हो वहां अंखफोड़वा कांड होना ही है। बहुत बेहतर आलेख और दिलेरी से लिखने के लिए बधाई।

✦ पंकज झा, छोटी कल्याणी, मुजफ्फरपुर

भूख की लड़ाई

मिश्रा जी,

दिसम्बर 2021 अंक में मिथिलेश कुमार ने "सौदागरों के देश में भूखे पेट कैसे लड़ें भूखें की लड़ाई" आलेख में आपके शब्दों का चयन वास्तव में दिल का झकझोरता हुआ चिंतन करने पर विवश करता है। जीवन एवं वर्तमान समय में भूख की लड़ाई बहुत कठिन है और राजनेता इसकी भी राजनीति करने से नहीं चूकते। इस खबर ने हकीकत में दर्द को बयां किया है। पत्रकार अजय कुमार की खबर "बीजेपी सत्ता विरोधी लहर और वोट बंटने के खतरे से हलकान" पठनीय है। पत्रिका सिर्फ रंगीन पृष्ठों में प्रकाशित होने लगे तो इसका प्रभाव बढ़ेगा।

✦ कमलेश राय, सेक्टर-04, बोकारो

एक से बढ़कर एक

संपादक जी,

मैं केवल सच, पत्रिका का नियमित पाठक हूँ। दिसम्बर अंक में शशि रंजन सिंह एवं राजीव शुक्ला की कई खबर पढ़ा जिसमें "विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा राजनीति या हठधर्मिता के शिकार" में भी आपने पूरी सच्चाई को पाठकों के समक्ष रखा है। दूसरी खबर "नर्सिंग शिक्षा में माफिया राज" में भी तकनीकी शिक्षा में हो रहे भ्रष्टाचार पर भी सटीक खबर लिखा है जो पठनीय है। "मुजफ्फरपुर अंखफोड़वा कांड की सच्चाई" खबर में भी आपकी पत्रिका ने पत्रकारिता धर्म का निर्वहन किया है। इस प्रकार की खबर से पत्रकारिता पर विश्वास जगता है।

✦ अतुल सक्सेना, करोलबाग, नई दिल्ली

सदन में बवाल

ब्रजेश जी,

आपका संपादकीय पढ़ने के बाद बार-बार पढ़ने को मन करता है क्योंकि इतने स्पष्ट शब्दों में बेबाकी से कोई भी बात लिखा जाता है जिसको कोई भी आसानी से समझ सकता है। दिसम्बर 2021 अंक में आपका संपादकीय "सदन में बोलत पर बवाल" पर पक्ष एवं विपक्ष के साथ सदन को भी घेरा है की आखिरकार कौन है। डीजीपी कूडेदान में बोलत ढूँढ़ रहा है और राजनेता आनंद उठा रहे हैं। भगवान आपकी रक्षा करें क्योंकि जिस प्रकार की खबर केवल सच लिख रहा है उससे चिंता बढ़ी रहती है।

✦ योगेन्द्र सिंह, राजा बाजार, जहानाबाद

बिपिन रावत

मिश्रा जी,

दिसम्बर 2021 अंक पढ़कर मन मर्माहत हुआ क्योंकि देश के सीडीएस बिपिन रावत सहित कई जवान हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहिद हो गये। ललन कुमार प्रसाद ने अपनी खबर में सेना का मनोबल सहित घटना की सटीक जानकारी के साथ समीक्षा किया है। इस दुर्घटना के साथ बिपिन रावत के कार्य एवं ईच्छाशक्ति को बड़ी गंभीरता के साथ लिखा गया है और दूसरे सीडीएस मनोज मुकुंद नरवणे की जानकारी भी दी गयी है। सभी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि और पत्रिका के लेखक को भी बहुत बधाई। इस अंक की सभी खबरें पठनीय है।

✦ संजय मुंडा, ओरमांझी, राँची

मकड़जाल

संपादक जी,

दिसम्बर 2021 अंक में शशि रंजन सिंह एवं राजीव शुक्ला ने बिहार सरकार एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के मकड़जाल पर सटीक प्रहार किया है और यह बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार बिहार सरकार पदाधिकारियों के चंगुल में हैं। इस खेल में बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी पीस रहे हैं और उनको सुनने वाला कोई नहीं है। आपने वास्तविक सच्चाई से पाठकों को रूबरू कराया है और आईएएस किस प्रकार बीपीएस का शोषण कर रहे हैं। जानकारी एवं चिंताजनक खबर है लेकिन सच्चाई है।

✦ मनोज सिंह, आनन्दपुरी, पटना

अन्दर के पन्नों में

16



RNI No.- BIHHIN/2006/18181,

DAVP No.- 129888

समृद्ध भारत

खुशहाल भारत



केवल सच

निर्भक्ता हमारी पहचान

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका



वर्ष:- 16,

अंक:- 188,

माह:- जनवरी 2022,

मूल्य:- 20/- रू

फाउंडर

गोपाल मिश्र

संपादक

ब्रजेश मिश्र

9431073769

8340360961

editor.kstimes@rediffmail.com

kewalsach@gmail.com

प्रधान संपादक

सच्चिदानन्द मिश्र

9431878843

ललन कुमार प्रसाद

9334107607

संपादकीय सलाहकार

अमिताभ रंजन मिश्र

9430888060, 8873004350

अमोद कुमार

9431075402

महाप्रबंधक

त्रिलोकी नाथ प्रसाद

9308815605, 9122003000

triloki.kewalsach@gmail.com

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

पूनम जयसवाल

9430000482, 9798874154

रीता सिंह

7004100454, 9308729879

मनीष कुमार कमलिया

9934964551, 8809888819

उपसंपादक

अरविन्द मिश्रा

9934227532, 9576438501

ललन कुमार

9430243587, 9334813587

अजित कुमार त्रिपाठी

9430826676, 9294942868

आलोक कुमार सिंह

8409746883

संयुक्त संपादक

अमित कुमार 'गुड्डू'

9905244479, 7979075212

amit.kewalsach@gmail.com

राजीव कुमार शुक्ला

9430049782, 7488290565

कृष्ण कुमार सिंह

6209194719, 7909077239

काशीनाथ गिरी

9905048751, 9431644829

प्रदीप कुमार सिन्हा

9472589853, 6204674225

सहायक संपादक

शशि रंजन सिंह

8210772610, 9431253179

मिथिलेश कुमार

9934021022, 9431410833

संजीव रंजन तिवारी

9430915909

संदीप स्नेह

9971679857, 9667977987

नवेन्दु कुमार मिश्र

9570029800, 9199732994

रामपाल प्रसाद वर्मा

9939086809, 7079501106

समाचार प्रबंधक

सुधीर कुमार मिश्र

9608010907

ब्यूरो-इन-चीफ

संकेत कुमार झा

9386901616, 7762089203

बिनय भूषण झा

9473035808, 8229070426

विधि सलाहकार

शिवानन्द गिरि

9308454485

रवि कुमार पाण्डेय

9507712014

चीफ क्राइम ब्यूरो

आनन्द प्रकाश

9508451204, 8409462970

कुमार सौरभ

7004381748, 9102366629

गगन कुमार मिर

8210810032, 9835585560

साज-सज्जा प्रबंधक

अमित कुमार

9905244479

कार्यालय संवाददाता

सोनू यादव

8002647553, 9060359115

प्रसार प्रतिनिधि

कुणाल कुमार

9905203164

बिहार प्रदेश जिला ब्यूरो

पटना (श०):-	श्रीधर पाण्डेय	09470709185
(म०):-		
(ग्रा०):-		
भोजपुर :-	गुड्डू कुमार सिंह	8789291547
बक्सर :-	बिन्ध्याचल सिंह	8935909034
कैमूर :-		
रोहतास :-	अशोक कुमार सिंह	7739706506
गया (श०) :-	सुमित कुमार मिश्र	7667482916
(ग्रा०) :-		
औरंगाबाद :-	अनिल कुमार मिश्र	9852315231
जहानाबाद :-	नवीन कुमार रौशन	9934039939
अरवल :-	संतोष कुमार मिश्रा	9934248543
नालन्दा :-		
नवादा :-	अमित कुमार	9934706928
मुंगेर :-		
लखीसराय :-		
शेखपुरा :-		
बेगूसराय :-	निलेश कुमार	9113384406
खगड़िया :-		
समस्तीपुर :-		
जमुई :-	अजय कुमार	09430030594
वैशाली :-		
छपरा :-		
सिवान :-		
गोपालगंज :-		
मुजफ्फरपुर :-	अविनाश कुमार	9470659050
सीतामढ़ी :-		
शिवहर :-		
बेतिया :-		
बगहा :-		
मोतिहारी :-		
दरभंगा :-		
मधुबनी :-	सुरेश प्रसाद गुप्ता	9939817141
सहरसा :-		
मधेपुरा :-		
सुपौल :-		
किशनगंज :-		
अररिया :-	अब्दुल कय्यूम	9934276870
पूर्णिया :-		
कटिहार :-		
भागलपुर, (ग्रा०) :-	रवि पाण्डेय	
नवगछिया :-		
बांका :-		

दिल्ली कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- संजय कुमार सिन्हा
A-68, 1st Floor,
नागेश्वर तल्ला, शास्त्रीनगर, न्यू
दिल्ली-110052
संजय कुमार सिन्हा, स्टेट हेड
मो०- 9868700991, 9431073769

उत्तरप्रदेश कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
....., **स्टेट हेड**

सम्पर्क करें
9308815605

झारखण्ड स्टेट ब्यूरो

ब्रजेश कुमार मिश्रा 9431950636, 9631490205

उप संपादक**झारखण्ड सहायक संपादक**

ब्रजेश मिश्रा 7654122344, 7979769647

अभिजीत दीप 7004274675, 9430192929

संयुक्त संपादक**सहायक संपादक****झारखण्ड प्रदेश जिला ब्यूरो**

राँची :- अभिषेक मिश्रा 09431732481

साहेबगंज :- अनंत मोहन यादव 09546624444

खूँटी :-

जमशेदपुर :-

हजारीबाग :-

जामताड़ा :-

दुमका :-

देवघर :-

धनबाद :-

बोकारो :-

रामगढ़ :-

चाईबासा :-

कोडरमा :-

गिरीडीह :-

चतरा :-

लातेहार :- रविकांत पासवान 09801637947

गोड्डा :-

गुमला :-

पलामू :-

गढ़वा :-

पाकुड़ :-

सरायकेला :-

सिमडेगा :-

लोहरदगा :-

पश्चिम बंगाल कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- अजीत कुमार दुबे
131 चितरंजन एवेन्यू,
कोलकाता, पश्चिम बंगाल- 700073
अजीत कुमार दुबे, स्टेट हेड
मो०- 9433567880, 9308815605

मध्य प्रदेश कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
हाउस नं.-28, हरसद्धि कैम्पस
खुशीपुर, चांबड़
भोपाल, मध्य प्रदेश- 462010
अभिषेक कुमार पाठक, स्टेट हेड
मो०- 8109932505,

झारखंड कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
नियर- न्यू छोटानागपुर स्कूल
बरियातु रोड, राँची- 834001
....., **स्टेट हेड**
मो०- 6206889040, 9431073769

छत्तीसगढ़ कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
....., **स्टेट हेड**
सम्पर्क करें
8340360961

संपादकीय व प्रधान कार्यालय:-

- ☞ पूर्वी अशोक नगर, रोड नं:-14, मकान संख्या:- 28/14, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार) मो०- 9431073769, 9955077308
- ☞ e-mail:- kewalsach@gmail.com, ditor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com
- ☞ स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक ब्रजेश मिश्रा द्वारा सांध्य प्रवक्ता खबर वर्क्स, ए- 17, वाटिका विहार (आनन्द विहार), अम्बेडकर पथ, पटना 8000 14(बिहार) एवं पूर्वी अशोक नगर, रोड नं. 14, कंकड़बाग पटना-800020 से प्रकाशित, संपादक- ब्रजेश मिश्रा। RNI NO.-BIHHIN/2006/18181
- ☞ पत्रिका में प्रकाशित समाचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।
- ☞ सभी प्रकार के वाद-विवादों का निपटारा पटना न्यायालय के अधीन होगा।
- ☞ आलेख पर कोई आपत्ति हो तो एक महीने के भीतर खंडन करें।
- ☞ किसी भी लेख के लिए रचनाकार/लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- ☞ सभी पद अवैतनिक हैं।
- ☞ फोटो-समाचार साभार भी (माध्यम- इंटरनेट एवं अन्य स्रोत)
- ☞ कोई भी शिकायत हमारे पते पर लिखकर भेजें।
- ☞ **विज्ञापन का भुगतान चेक या ड्राफ्ट एवं RTGS से ही मान्य होगा।**
- ☞ भुगतान Kewal Sach को ही करें। प्रतिनिधियों को नगद न दें।
- ☞ A/C No. :- 0600050004768
- ☞ BANK :- Punjab National Bank
- ☞ IFSC Code :- PUNB0060020
- ☞ PAN No. :- AAJFK0065A



श्री चन्द्र प्रकाश सिंह

प्रधान संरक्षक सह प्रबंध संपादक
 'केवल सच' पत्रिका एवं 'केवल सच टाइम्स'
 राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटरक)
 पूर्व निदेशक सदस्य, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
 09431016951, 09334110654



श्री सज्जन कुमार सुरेका

मुख्य संरक्षक
 'केवल सच' पत्रिका एवं 'केवल सच टाइम्स'
 डी- 402 राजेन्द्र विहार, फॉरेस्ट पार्क
 भुवनेश्वर- 751009 मो-09437029875



सुधीर कुमार

मुख्य संरक्षक सह निदेशक "मगध इंटरनेशनल स्कूल" टेकारी
 "केवल सच" पत्रिका एवं "केवल सच टाइम्स"
 9060148110
 sudhir4s14@gmail.com

पत्रिका संरक्षक

श्री जय कुमार सिंह	:- पूर्व मंत्री, बिहार सरकार	9431821104
डॉ० उमाकान्त पाठक	:- जेनरल फिजिशियन, MBBS	9835291966
भगवान सिंह कुशवाहा	:- पूर्व मंत्री, बिहार सरकार	9431821525
श्री ललन पासवान	:- विधायक, चेनारी, जदयू	9431483540
डॉ० ए० के० सिंह	:- शिशु रोग विशेषज्ञ MBBS	9431258927
श्रीमती अरूणा सिंह	:- सदस्य, जिला पार्षद, बिक्रमगंज	9931610437



श्री आर के झा

मुख्य संरक्षक
 'केवल सच' पत्रिका एवं 'केवल सच टाइम्स'
 EX. CGM, (Engg.) N.B.C.C
 08877663300



देवब्रत कुमार गणेश

मुख्य संरक्षक सह भावी प्रत्याशी, 53 ठाकुरगंज विधानसभा
 "केवल सच" पत्रिका एवं "केवल सच टाइम्स"
 8986196502/9304877184
 devbartkumar15@gmail.com

बिहार राज्य प्रमंडल ब्यूरो

पटना		
मगध		
सारण		
तिरहुत		
पूर्णिया	धर्मोन्द्र सिंह	9430230000 7004119966
भागलपुर		
मुंगेर		
दरभंगा		
कोशी		

विशेष प्रतिनिधि

आशुतोष कुमार	9430202335, 9304441800
सुमित राज यादव	9472110940, 8987123161
बेंकटेश कुमार	8521308428, 9572796847
रामउदय यादव	8862858305, 9709409232
राजीव नयन	9973120511, 9430255401
लक्ष्मी नारायण सिंह	9204090774
मणिभूषण तिवारी	9693498852
राजीव रंजन	9431657626
दीपनारायण सिंह	9934292882
आनन्द प्रकाश पाण्डेय	9931202352, 7808496247
अनु कुमारी	9471715038, 7542026482
रामजीवन साहू	9430279411, 7250065417
रंजीत कुमार सिन्हा	9931783240, 7033394824
अजय कुमार	8409103023, 6203723995
वंदना सिंह	7903669215
विनित कुमार	8210591866, 8969722700
कुणाल कुमार सिंह	9988447877, 9472213899

छायाकार

त्रिलोकी नाथ प्रसाद	9122003000, 9431096964
मुकेश कुमार	9835054762, 9304377779
जय प्रसाद	9386899670,
कृष्णा प्रसाद	9608084774, 9835829947

बिहार में चल रहा है माफिया राज

1990 से लेकर 2022 तक बिहार में विकास के नाम पर जितनी राजनीति हुई उसका 25 प्रतिशत भी विकास की पटकथा लिखी जाती तो शायद सभी प्रकार के संसाधनों से लैस बिहार के लोग आज रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में दर - दर की ठोकरे नहीं खाते। अपराध एवं भ्रष्टाचार के लिए खास पहचान रखने वाला बिहार आईपीएस को भी जबरन सेवानिवृत्त कर देता है की बातें सार्वजनिक हो चुकी हैं और 1994 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी अमिताभ कुमार दास इसका जिवंत उदाहरण हैं। 10 वर्षों के कानूनी युद्ध जितने के बाद अमिताभ कुमार दास को एसपी से सीधे आईजी रैंक में प्रमोशन दिया गया लेकिन ईमानदारी एवं सच्चाई को आवाम के सामने लाने की आदत की वजह से श्री दास को राजनीति का शिकार होना पड़ा और उनको वीआरएस जबरन दे दिया गया है की कानूनी लड़ाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है और श्री दास को यह भरोसा है की कानून उनके पक्ष में फैसला सुनायेगा क्योंकि कानून आज भी जिन्दा है। तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार एवं तत्कालीन रेल एसपी पटना अमिताभ कुमार दास के बीच उस समय से आपसी टकराव रेलवे के ठेके को लेकर चल रहा था जिसको आज राजनीति रंग दे दिया गया और आज श्री दास सेवा देने के बजाय पेंशन उठा रहे हैं। बिहार की नीतीश सरकार के कार्यों पर जमकर प्रहार कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि यह सरकार गलत नीतियों पर काम कर रही है और प्रदेश में माफिया एवं गुंडा राज नीतीश कुमार चला रहे हैं। अमिताभ कुमार दास की पहचान एक दिलेर पदाधिकारी के रूप में होती रही है और इन्होंने राजनीति के कई धुरंधरों को सलाखों के पीछे ढकेला था जिसकी वजह से यह राजनेताओं के टारगेट पर थे, इस वजह से विपक्ष सबकुछ जानने के बाद भी मौन रहकर सरकार के गलत नीतियों में साथ दे रहे हैं की भी बात श्री दास अपने साक्षात्कार में कहते हैं। कई ऐसे पत्राचार अमिताभ दास ने सरकार से किया है जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और नीतीश कुमार की सरकार की जगहसाई हो रहा है इसका जीता जागता उदाहरण 2020 में बनी नीतीश कुमार की सरकार में शामिल शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी का शपथ ग्रहण और इस्तीफा से समझा जा सकता है। कई बिन्दुओं पर केवल सच पत्रिका के संपादक **ब्रजेश मिश्र** ने 1994 बैच के आईपीएस रहे **अमिताभ कुमार दास** से बातचीत की उसके प्रमुख अंश:-



1994 बैच के IPS अमिताभ कुमार दास का साक्षात्कार करते पत्रिका संपादक ब्रजेश मिश्र

★ सर आपने वीआरएस क्यों लिया?

मैंने वीआरएस लिया नहीं, उन्होंने मुझे दिलाया है गैरकानूनी तरीके से और वह मुझ अभी कोर्ट में है, न्यायालय के विचाराधीन है और इसके पहले भी इन लोगों ने दस वर्षों तक मेरा प्रमोशन रोक रखा था, लेकिन बाद में ऑनरेबुल सुप्रीम कोर्ट ने मेरे पक्ष में फैसला सुनाया और फिर मेरी जीत हुई और मुझे एस.पी. के वेतनमान से आई.जी. का वेतनमान देना पड़ा। तो पहले भी दस साल तक कानूनी लड़ाई लड़के जीत चुका हूँ और दोबारा जितूंगा और सच की जीत होती है और अभी भी मैं डटा हुआ हूँ माफिया से और जैसा आपने कहा मैं लोहा ले रहा हूँ।

★ आजकल पुलिस सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रिय है, जितना वह सोशल मीडिया पर सक्रिय है, अपराध नियंत्रण में कारगर नहीं दिखता। इसका क्या कारण मानते हैं?

बिहार के संदर्भ में कहूँ या भारत के संदर्भ में कहूँ। एक तरफ पूरे देश में देखेंगे कि माफिया राज है। जो भारत का अभी गृह मंत्री हैं वह ताड़ीपार हैं, अमित शाह। जो गृह राज्य मंत्री हैं भारत का, अजय मिश्रा टेनी। आप जानते हैं कि वह उत्तर प्रदेश का खूंखार अपराधी है। उसका बेटा आशीष मिश्रा लखीमपुर खिरी काण्ड में जेल में बंद है और उसके पहले अजय मिश्रा टेनी का भी एक विडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह किसानों को धमकियाँ दे रहा था। तो ऐसे-ऐसे गुंडे-मवाली लोग भारत सरकार में बैठे हुए हैं। अब बिहार सरकार की जो स्थिति है प्रदेश में सरकार की, वहाँ भी यही स्थिति है। नीतीश कुमार एक माफिया राज चला रहा है और ईमानदार लोगों पर सर्जिकल स्ट्राइक किया जा रहा



है। अपराधी लोग मिनिस्टर बने बैठे हैं। बिहार सरकार की एक मंत्री हैं श्रीमती लेसी सिंह। वह पूरा का पूरा अपराधियों का गिरोह चलाती हैं। उनके जो पति थे बूटन सिंह, वह पूर्णिया का खूंखार अपराधी था। बाद में बूटन सिंह की हत्या हो गई गैंगवार में और उसके गिरोह की कमान श्रीमती लेसी सिंह के हाथों में आ गई और अभी एक-दो महीने पहले भी लेसी सिंह ने पूर्णिया में एक हत्या करवाई हैं रिंटू सिंह की। रिंटू सिंह की पत्नी ने बार-बार कहा है कि इस हत्या में लेसी सिंह का हाथ है, लेकिन राजनीतिक दबाव ऐसा है कि अब तक लेसी सिंह से पुलिस ने पूछताछ करने की हिम्मत नहीं जुटायी है। जब ऐसे हत्यारों और खूनी लोग बिहार सरकार में मिनिस्टर बनकर बैठेंगे तो आप क्या उम्मीद करेंगे लॉ एण्ड ऑर्डर सुधारने की। आपने कहा कि सोशल मीडिया पर ज्यादा जांबाजी दिखा रहे हैं, क्योंकि असली जांबाजी दिखाने की हिम्मत ज्यादातर आईपीएस अधिकारियों में नहीं रह गई है, बाकि पुलिस वालों में नहीं रह गई है। इसलिए अब वह फेसबुक पर ही जांबाजी दिखाते हैं, तो इसलिए ऐसी स्थिति हो गई है।

★ विपक्ष भी चुप है, जैसा कि आपने लेसी सिंह के बारे में कहा। विपक्ष क्यों चुप है? इस मामले को उठाना चाहिए था। विपक्ष में युवा तेजस्वी यादव हैं, मुख्यमंत्री बनने का चाहत रखते हैं और चुप क्यों हैं? इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है आपका?

अब यह सवाल तो आप उनसे पूछिए। क्योंकि कायदे से आपने सही कहा कि ये तो विपक्ष का भी काम है और जनतंत्र में विपक्ष को बात रखनी चाहिए। हाँ, एक बार की बात है नवम्बर 2020 की। जब मेवालाल चौधरी को इस्तीफा दिलवाया था। बिहार के शिक्षा मंत्री थे मेवालाल चौधरी और तब मैंने यह मामला उठाया था कि उसने अपनी पत्नी अनीता चौधरी की हत्या कर दी है और वह मामला फिर काफी तूल पकड़ लिया। उस समय विपक्ष ने उसको टेकअप किया था। मैंने तेजस्वी यादव से भी बात की और उसने अपने फेसबुक पर मेरे पत्र को शेयर किया था। तो उस वक्त मुझे विपक्ष का साथ मिला था और अंत में मेवालाल चौधरी को ढाई घंटे के भीतर इस्तीफा देना पड़ा था।

<p>अमिताभ कुमार दास (भापुरी-94-बिहार) चेयरमैन बिहार विप्लवी परिषद (सामानता-स्वातंत्रता-कृपण) मो: 7463924877</p>	<p>सत्यमेव जयते</p>	<p>AMITABH KUMAR DAS (IPS-94-BIHAR) CHAIRMAN THE BIHAR VIPLAVI PARISHAD (EQUALITY-LIBERTY-FRATERNITY) MOBILE: 7463924877</p>
--	---------------------	---


दिनांक: 5-1-2022

प्रेषित,
श्री फागू चौहान
महामहिम राज्यपाल
बिहार, पटना

विषय- "स्वाधीनता सेनानी घोषाला" ? नीतीश कुमार के पिता को स्वाधीनता सेनानी घोषित करने के संबंध में।

- ① बिहार कैबिनेट ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पिता कविराज राम लखन सिंह को "स्वाधीनता सेनानी" का दर्जा देते हुए 17 जनवरी 2022 को उनकी प्रतिमा पर राजकीय समारोह करने का फैसला किया है।
- ② मैं इतिहास का छात्र रहा हूँ। बरती से आजादी की लड़ाई में कविराज राम लखन सिंह का योगदान दूंद रहा हूँ, मगर कोई योगदान नहीं मिला। GOOGLE से भी मदद नहीं मिली।
- ③ मुझे बिहार कैबिनेट के फैसले से "स्वाधीनता सेनानी घोषाला" की बू आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री के पिता को जबरदस्ती स्वाधीनता सेनानी बनाया जा रहा है।
- ④ कृपया बिहार सरकार से आजादी की लड़ाई में कविराज राम लखन सिंह के योगदान का पूर्ण विवरण मांगा जाए।

आपका
अमिताभ
5-1-22

अमिताभ कुमार दास (पापुसे-94-बिहार) "नटशेल" द्वितीय तल पटना स्काइज़ रोड नंबर एक विवेकानंद पार्क, न्यू पारटिसिपुत्र कॉलोनी पटना-13, फोन : (0612)-2271234, मोबाईल: 9431682303		AMITABH KUMAR DAS (IPS-94-BIHAR) "NUTSHELL" Second Floor PATNA SKYZ Road Number One Vivekanand Park, New Participutra Colony Patna-13 Phone : (0612) 2271234 Mobile : 7463924877 94316 82303
पत्रांक / सेवा में,		दिनांक 9-2-2021
पुलिस महानिदेशक बिहार, पटना		
विषय : माननीय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह के ठिकानों पर AK-47 का जखीरा होने के संबंध में		
महोदय		
(1) श्रीमती लेसी सिंह ने नीतीश सरकार में मंत्री पद की शपथ ली है।		
(2) लेसी सिंह का पति बटन सिंह पूर्णिया जिले का खूंखार अपराधी था। "सीमांचल" का आतंक था। बटन सिंह पर हत्या, अपहरण, रंगदारी आदि के दर्जनों मामले दर्ज थे। अप्रैल 2000 में, बटन सिंह को गोशियों से छलनी कर दिया गया।		
(3) बटन सिंह, नीतीश कुमार का लंगोटिया यार था। मौत के समय, बटन सिंह समता पार्टी का पूर्णिया जिलाध्यक्ष था।		
(4) बटन सिंह की हत्या के बाद, उसके गिरोह की कमान लेसी सिंह के हाथों में आ गई। गिरोह के सारे हथियार भी लेसी सिंह के पास हैं। मुझे पक्की सूचना है कि लेसी सिंह के ठिकानों पर अद्वैत हथियारों (AK 47, AK 56 SLR) का जखीरा है। कृपया लेसी सिंह के ठिकानों पर, पुलिस छापेमारियां करा के, ये सारे हथियार बरामद किए जाएं। देर किए जाने पर, सारे हथियार नेपाल भेजे जा सकते हैं।		
आपका अमिताभ 9-2-21		

★ अभी आप देख रहे होंगे कि बालू माफिया हो, शिक्षा माफिया हो, स्वास्थ्य क्षेत्र में दवा माफिया हो, चारों तरफ माफियाओं का राज है, जैसा की आपने भी कहा और आप एक मुहिम भी चला रहे हैं। आप जब आईपीएस थे, तब कौन सी ऐसी समस्या आन पड़ी, जिसके कारण आप नीतीश सरकार के टारगेट पर आ गये?

नीतीश कुमार से तो मेरी लड़ाई उस समय की 2001 से 2003 की। मैं पटना का रेल एस.पी. हुआ करता था और नीतीश कुमार भारत के रेल मंत्री थे। पटना रेल जिला है वह काफी लंबा-चौड़ा जिला है। उसमें 11 जिले आते हैं। उस वक्त नीतीश कुमार ने क्या किया था कि रेलवे के ठेके आप जानते हैं कि अरबों रुपये के ठेके होते हैं। रेलवे बजट एक अलग बजट ही होता है। तो अरबों रुपये के जो रेलवे के ठेके थे, वह नीतीश कुमार ने माफिया सरगनाओं में बांट दिये थे। मैं रेल एस.पी. था, मैंने इसका पर्दाफाश किया। सोशल ब्लोअर का काम किया और तभी से मैं नीतीश कुमार के टारगेट पर हूँ। इसके बाद पहली बार नवम्बर 2005 में जब वह मुख्यमंत्री बने तो मुझपर बहुत सारे झूठे मामले में इन्कवायरी चला दी गई और उसके बाद मेरा प्रमोशन रोक दिया गया। 10 साल सुप्रीम कोर्ट में मुझे लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी प्रमोशन लेने के लिए। तो नीतीश कुमार से मेरा जो टकराव हुआ वह तो रेलवे ठेकों को लेकर हुआ।

★ अभी बिहार में कोरोना काल है। नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा में निकले हुए हैं। फिलहाल उन्होंने झॉफ कर दिया है कोरोना के लहर को देखते हुए। लेकिन क्या वास्तव में समाज सुधरा है बिहार का?

समाज अब क्या सुधरेगा। नीतीश कुमार के बारे में आपको बता दूँ कि उनकी जो पत्नी थी मंजू सिन्हा, उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या कर

ली थी और इसलिए आत्महत्या की थी कि उनको मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई थी और पूरी की पूरी पुलिस जो है बिहार की, उसने मंजू सिन्हा की आत्महत्या की लीपा-पोती कर दी। आज वही नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान पर निकले हैं। लगता है राजा राममोहन राय के बाद यही पैदा हुए हैं। तो यह सब कुछ नौटंकीबाजी है, ड्रामेबाजी है। एक तरफ आपकी सरकार में लेसी सिंह जैसी खूनी मंत्री बैठी हुई हैं। एक तरफ सृजन घोटाला में नीतीश कुमार को कायदे से जेल जाना चाहिए था। आपको पता है कि बिहार के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला है सृजन घोटाला। ढाई हजार करोड़ रुपये का घोटाला है। चारा घोटाला 900 करोड़ का था, सृजन घोटाला 2500 करोड़ का। तो कायदे से तो नीतीश कुमार को आज की तारीख में बेउर जेल के भीतर होना चाहिए था सृजन घोटाला में। क्योंकि सीबीआई पिंजरे का तोता है। सीबीआई राजनीतिक दबाव में काम करती है। इसलिए इनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। तो जब आप सृजन घोटाला के सूत्रधार हैं। आपकी सरकार में लेसी सिंह बैठी हुई हैं तो आप किस मुंह से समाज सुधार की बात करते हैं। ये सब ड्रामेबाजी है, नौटंकीबाजी है, पब्लिक को उल्लू बनाने का हथकण्डे हैं।

★ भारतीय जनता पार्टी वर्तमान नीतीश की सरकार में गठबंधन में शामिल है और ऐसा माना जाता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेताओं का सृजन घोटाले में हाथ है। कही भाजपा इसी कारण से तो चुप नहीं है?

बिल्कुल। यह चोर-चोर मौसेरे भाई वाली बात है। क्योंकि कहते हैं न कि बात निकलेगी तो दूर तलक जायेगी। नीतीश कुमार जेल जायेंगे तो उनके साथ पूरी बारात भी जेल जायेगी। तो उसमें भाजपा के भी बड़े-बड़े रामभक्त लोग भी हैं। इसलिए सृजन घोटाला पर सीबीआई को कहा गया है कि बिल्कुल धीमी चाल में चलना है। आप खुद सोचिये कि इतना बड़ा घोटाला है और आजतक सीबीआई ने एक बार भी पूछताछ नहीं की है नीतीश कुमार से। अगर गिरफ्तारी नहीं भी करनी है तो आप पूछताछ तो कर सकते हैं। लेकिन सीबीआई ने तो इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है और सृजन घोटाला पर लगता है कि कोई प्रगति ही नहीं हो रही है। कुछ काम ही नहीं कर रहा है सीबीआई।

★ चारा घोटाला को जिस तरह से विपक्ष ने उठाया था और लालू यादव को जेल के पीछे ढकेल दिया था। क्या सृजन घोटाला अगर सीबीआई का एक तरफ से केन्द्र सरकार के दबाव के कारण रोका हुआ है और विपक्ष भी इस मामले को सही ढंग से नहीं उठा पा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे?

अब यह तो विपक्ष की कमजोरी है। यदि सृजन घोटाला जो इतना बड़ा घोटाला हुआ और उस पर यदि विपक्ष हमलावर नहीं है तो इसको मैं बिहार में विपक्ष की कमजोरी मानूंगा। आप एक हमला करने का मौका चूक रहे हैं, जबकि सृजन घोटाले पर तो बिहार में विपक्ष को जागरूकता फैलानी चाहिए थी। सीबीआई पर दबाव बनाना चाहिए था। विपक्ष को तो ऐसा करना चाहिए था कि एक शिष्ट मंडल लेकर सीबीआई के निदेशक से मिलना चाहिए था। दिल्ली जाकर सीबीआई के डॉयरेक्टर से विपक्ष के डेलीगेशन को मिलना चाहिए था कि इसपर आप कुछ चुस्ती क्यों नहीं दिखा रहे हैं। तो ये सब दबाव बन सकता था। अब यदि विपक्ष हमलावर नहीं है तो आप उसकी बात वही जाने की हमलावर क्यों नहीं है।

★ आप 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं। आपने लालू-राबड़ी शासनकाल को भी देखा है और नीतीश के शासनकाल को भी देखा है। क्या अंतर है दोनों सरकारों में?

अब अंतर यह है कि एक तो नीतीश कुमार का मीडिया का

प्रबंधन जो कहते हैं आज समय में मीडिया मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज हो गई है। सारे गलत काम कीजिए और छवि अच्छा बनाये रखिए। तो मीडिया प्रबंधन जो है नीतीश का वह लालू से बेहतर है। यहां तक की भारतीय जनता पार्टी का भी जो मीडिया प्रबंधन है, मीडिया मैनेजमेंट है, उससे भी नीतीश कुमार का बेहतर है। इस जमाने में उतनी घोटालों की बात नहीं आती है। जैसे लेसी सिंह का ही मामला है। वह लालू सरकार में रहती तो यह बिल्कुल हमलावर हो गया होता। लेकिन अभी नीतीश का समय है, तो मीडिया में चू तक नहीं है या नीतीश कुमार की पत्नी मंजू सिन्हा ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। यदि लालू के समय में ऐसी घटना हुई होती तो मीडिया पूरा हंगामा कर देता, तहलका मचा देता। लेकिन अभी शांति है। तो एक तो यह भी है कि नीतीश कुमार ने एक हथियार बना लिया है विज्ञापन को। जहां कोई अखबार इसके खिलाफ एक लाइन भी लिखता है तो पहला काम होता है उस अखबार का सरकारी विज्ञापन बंद हो जाता है। मुझे कई संपादकों से बात होती है, चीफ रिपोर्टरों से बात होती है। मैं कहता हूँ कि अरे भाई इतनी खूली बात है, इसको आप छाप क्यों नहीं रहे हैं। मैंने लेसी सिंह के खिलाफ लिखा कि एके-47 का जखीरा है लेसी सिंह के पास। मैंने संपादकों से कहा कि मैं अपनी जिम्मेदारी पर यह लिख रहा हूँ। अपने लेटर पैड पर लिख रहा हूँ। आप इसको छाप क्यों नहीं रहे हैं? तो वे कहते हैं कि आप जानते नहीं हैं कि तुरंत हमारा सरकारी विज्ञापन बंद हो जायेगा। फिर प्रबंधन का हमलों पर दबाव पड़ेगा। हो सकता है मेरी कुर्सी चली जाये। नहीं भी कुर्सी जायेगी तो प्रबंधन जो हैं हमारे अखबार का मालिक वह हमपर दबाव डालेगा। तो नीतीश कुमार ने विज्ञापन को एक हथियार बना लिया है। ये विकास पुरूष नहीं, विज्ञापन पुरूष है।

★ आपको कुछ ऐसा यादगार होगा, जब आप एस.पी. के रूप में थे। जो आपको आज भी वह याद आता हो। इस पर कुछ बताइए।


अब मेरा तो एस.पी. का कार्यकाल रहा, वह मार-धार और एक्शन से भरपूर रहा। जैसे जो एक बॉलीवूड की एक फिल्म आती है। मैं जहां-जहां एस.पी. रहा, मैंने हर जगह माफिया से लोहा लिया। लखीसराय का एस.पी. था तो मैंने बालू माफिया से लोहा लिया। प्रहलाद यादव के हथियार मैंने जब्त करवाये। उस समय सूर्यगढ़ा के एमएलए था। बक्सर का एस.पी. था तो मैंने ददन पहलवान को जेल की हवा खिलायी। रेल एस.पी. था तो मैंने रेलवे ठेके पर नीतीश कुमार को घेरा, जो पहले मैंने जैसा की बताया। किशनगंज एस.पी. था तो मैंने तस्लीमउद्दीन की दहशत वहां खत्म की थी। अरवल का एस.पी. था तब मैंने रणवीर सेना पर हमले किये थे। रणवीर सेना पर बहुत कड़ाई की थी। तो ऐसे देखिये तो कोई एक घटना को कह पाना मुश्किल है, लेकिन मुझे इस बात पर संतोष है कि मैं जहां भी एस.पी. रहा, मैंने माफिया की छाती पर मूंग दली है।

★ आप एक जिला के एस.पी. हुआ करते थे। उस समय भी कई जिले थे तो उस समय और और जिले के एस.पी. चूप क्यों थे? आप इस पर क्या कहेंगे।

इसकी तो सबसे बड़ी वजह है आदमी का लालच। कोई भी आदमी जब आईएएस या आईपीएस बनता है तो शुरू में बहुत बड़ी-बड़ी बातें करता है जब एकेडमी में रहता है। ट्रेनिंग करते समय लगता है कि दुनिया ही बदल देंगे। लेकिन उसके बाद फिल्ड में आते ही लोग एक रेट रस हो जाता है, जिसे चूहा दौड़ कहते हैं। इसके बाद आपको ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन ये सब का लालच हो जाता है। कोई भी आईपीएस अधिकारी है तो उसे लगता है कि मुख्यमंत्री हमसे नाराज हो जायेंगे तो कोई प्रोसेडिंग चला दिया जायेगा, प्रमोशन रोक दिया जायेगा। हमको निलंबित कर देगा या ज्यादा हम टकड़ायेंगे तो अमिताभ कुमार दास की तरह हमको

अमिताभ कुमार दास
(भापुरी-94-बिहार)

"नटशेल", द्वितीय तल
पटना स्काइज रोड नंबर एक
विश्वकानंद पार्क, न्यू पाटलिपुत्र कॉलोनी
पटना-13,
फोन: (0612)-2271234,
मोबाईल: 9431682303



सत्यमेव जयते

AMITABH KUMAR DAS
(IPS-94-BIHAR)

"NUTSHELL" Second Floor,
PATNA SKYZ Road Number One
Vivekanand Park, New Patliputra Colony,
Patna-13
Phone : (0612) 2271234
Mobile : 7463924877
94316 82303

पत्रांक: _____ दिनांक: 17 नवंबर 2020

सेवा में,
पुलिस महानिदेशक
बिहार, पटना।

विषय: माननीय मंत्री श्री मेवालाल चौधरी की पत्नी की रहस्यमय मौत की जांच।

महोदय

① बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री मेवालाल चौधरी की धर्मपत्नी श्रीमती नीता चौधरी 27 मई 2019 को अपने अवास पर बुरी तरह जल गई थी। 2 जून 2019 को उनकी मौत हो गयी।

② श्री मेवालाल चौधरी पर भागलपुर के सबीर थाने में नियुक्ति घोटाले का मामला दर्ज किया गया था।

③ मुझे सूचना है कि श्री मेवालाल चौधरी की पत्नी की मौत के पीछे एक गहरा राजनीतिक षडयंत्र है। संभवतः मौत के तार, नियुक्ति घोटाले से भी जुड़े हैं।

④ तुशान्त सिंह राजपूत की मौत को लेकर बिहार पुलिस ने अदभुत तल्परता दिखाई थी। कृपया नीता चौधरी की रहस्यमय मौत में S.I.T. का गठन कर के माननीय मंत्री श्री मेवालाल चौधरी से गहन पूछताछ की जाए।

आपका
अमिताभ
अमिताभ
17-11-2020

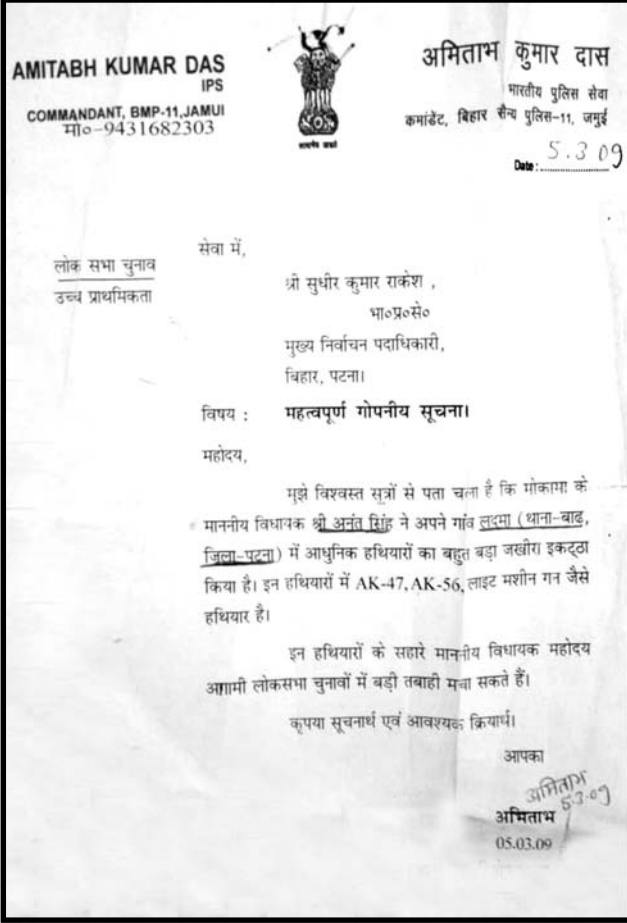
सिस्टम से अलग कर दिया जायेगा। तो ये सब की वजह से जो रेट रस है, चूहा दौड़ की वजह से ज्यादातर आईएएस, आईपीएस चूहा बनकर रह जाते हैं।

★ आप नीतीश कुमार के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं। यह एक बदला है या फिर बिहार को भ्रष्टाचारमुक्त बनाने की पहल?

नहीं, बदला किस बात का। मैं जब रेल एस.पी. था तो उस वक्त मैंने रेलवे ठेके का पर्दाफाश किया था। मेरी नीतीश कुमार से कोई व्यक्तिगत लड़ाई थोड़े ही है, खेत की लड़ाई थोड़े ही है। जब मैं लालू के समय में भी था तो बालू माफिया आरजेडी एमएलए था प्रहलाद यादव, उस पर मैंने एक्शन लिया। तो यह कोई बदले की बात नहीं हो रही। ये बात है कि बिहार को आप जानते हैं कि माफिया का राज है और हमेशा से रहा है। तरह-तरह के माफिया हैं बिहार में। कभी कोयला माफिया का राज था। अभी झारखण्ड अलग हो गया। हमलोग बच्चे थे तो कोयला माफिया था सब धनबाद में। कही बालू माफिया, शराब माफिया, शिक्षा माफिया, जिस क्षेत्र में जाइये बिहार में माफिया हैं। मैं आईपीएस ऑफिसर था तो मेरी ड्यूटी भी थी कि माफिया से लड़ना। आज मैं सर्विस में नहीं हूँ एक नागरिक के रूप में, सिटीजन के रूप में मेरी ड्यूटी है माफिया से लड़ने की। तो उसी ड्यूटी का मैं निर्वहन कर रहा हूँ और कोई बात नहीं है।

★ आज 40 जिला पुलिस मुख्यालयों में कोई एक ऐसा एस.पी. का नाम बताइए, जो वास्तव में अपराध के खिलाफ लड़ रहा हो आपकी नजरों में?

अभी जितने भी एस.पी. हैं जिले में वह मुझसे जुनियर हैं, मेरे छोटे भाई के समान हैं। किसी एक का नाम लेना नहीं ठीक है। हाँ कुछ लोग



अच्छा काम करते हैं तो मैं उनको बधाई भी देता हूँ, उनकी पीठ भी ठोकता हूँ कि आपने अच्छा काम किया। ज्यादा किसी का नाम ले लूंगा। यदि मैंने एस.पी. की ज्यादा तारीफ कर दी और नीतीश कुमार ने पढ़ लिया तो एस. पी. का फिर ट्रांसफर हो जायेगा। इसलिए इस प्रश्न को रहने दीजिए। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे एस.पी. हैं, कोशिश करते हैं अच्छा काम करने की।

★ नीतीश कुमार के शराबबंदी पर क्या कहेंगे?

ये तो बिल्कुल फ्लॉप है। देख रहे हैं क्या हो रहा है। पूरा बिहार में एक शराब माफिया पनप गया है और शराबबंदी में सबसे ज्यादा गरीब आदमी जेल जा रहा है। जितना भी बिहार का जेल भरे हुए हैं, उसमें आप देखेंगे कि ज्यादातर गरीब लोग, जिनका कोई जमानत कराने वाला नहीं है, वह जेल में हैं और बड़े-बड़े माफिया घूम रहे हैं आराम से। बिहार सरकार में मंत्री हैं रामसूरत राय। उनके भाई हैं हंसलाल राय। हंसलाल राय का स्कूल चलता है बोचहा, मुजफ्फरपुर में। स्कूल पर पुलिस ने छापेमारी की तो कई सौ बोटलों में शराब निकली। पुलिस ने स्कूल के चपरासी को जेल भेज दिया और हंसलाल राय पर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो मंत्री महोदय के भाई शराब माफिया बने हुए हैं। अभी मैंने मिस्टर के.के. पाठक जी, जो मध निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव बनाये गये हैं। मेरे व्हाट्सअप पर हैं। मैंने उनको भी लिखकर भेजा था कि सर इस हंसलाल राय को तो कुछ किया जाये। इतना बड़ा यह शराब माफिया है और मंत्री का भाई है। यह करीब 10-15 रोज पहले की बात है। तो देखिए वह क्या करते हैं। उनको तो ऐसे कड़ा पदाधिकारी माना जाता है। तो देखिए कितनी कड़ाई करते हैं। शराब माफिया के साथ पुलिस का बड़ा एक स्त्रोत बन गया है। शराब बिहार में

बंद नहीं हुई है। यदि आपका सम्पर्क है, पैसे हैं तो आपके दरवाजे पर शराब आ जायेगी और दूसरा नुकसान हुआ है कि जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं। पिछले कुछ महीने में बिहार में मुझे लगता है सब जोड़-जाड़कर 50 से ऊपर मौतें हुई हैं। बहुत मौतें की तो रिपोर्ट भी नहीं होती है, लेकिन रिपोर्टेड मौतों को जोड़ लें तो 60 से 70 मौतें हुई हैं। तो जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। शराब माफिया फल-फूल रहा है। यह पूरी तरह से फ्लॉप रहा है।

★ भ्रष्टाचार, अपराध, माफियागिरी चरम पर है, बावजूद इसके नीतीश कुमार बार-बार चुनाव जीतकर क्यों आ जाते हैं?

एक तो बात है कि पलटूराम कुर्सी कुमार हैं। पलटी मारने की नीतीश कुमार ने कला का रूप दे दिया है। तो देखियेगा की नीतीश कुमार कहते थे कि मिट्टी में मिल जाउंगा, लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाउंगा। और आज तड़ीपार होम मिनिस्टर की गोद में बैठे हुए हैं। तो पलटी मारने में तो नीतीश कुमार का जवाब नहीं है। कब लालू को बड़ा भाई कहना शुरू कर दें, कब नीतीश भाजपा के साथ चले जाये, कब क्या कर दें, तो पलटीमार कुर्सी कुमार हैं ये। एक तो ये है कि जिसको आप कह सकते हैं कि मक्कारी कहिए, धूर्त कहिए, वह हैं। दूसरी बात की बिहार की पब्लिक की भी गलती है। बिहार की पब्लिक भी बहुत सोच-समझकर वोट नहीं देती है। लोग जाति के मामले में उलझ जाते हैं। अब मेवालाल चौधरी को देखिए। तारापुर की पूरी जनता जानती थी कि यह घोटालेबाज है। उस पर एफआईआर हुआ था, जब वह कृषि विश्वविद्यालय का वी.सी. था। सबको पता है लेकिन बिहार की पब्लिक समझ नहीं रही है। लोग जातीय आधार पर वोट देते हैं। यदि कोई भूमिहार अपराधी खड़ा होगा तो उसके पीछे भूमिहार दौड़ने लगेंगे। राजपूत अपराधी खड़ा होगा तो उसके पीछे राजपूत दौड़ने लगेंगे और जब अपराध बढ़ जायेगा तब सब बैठकर नेहरू जी को क्रिसाइज करेंगे। तो ये तो बिहार की पब्लिक की भी गलती है और इसमें पब्लिक उतनी जागरूक नहीं है। इसलिए गलत लोगों के हाथ में सत्ता की कमान आ गई है।

★ सरकारी चिकित्सा और सरकारी शिक्षा, इन दोनों जगहों पर भी बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार है। इसपर किस तरह नकेल कसा जाये आपकी नजरों में, जिससे सरकारी शिक्षा और चिकित्सा में सुधार हो सके?

नकेल क्या कसे, यहाँ तो भ्रष्टाचार की जो गंगोत्री है, वह ऊपर से ही बह रही है। तो उसमें नकेल भी कसा जाये तो ऊपर से होगा। आपने स्वास्थ्य की बात की। अब यही बक्सर के ही आरटीआई एक्टिविस्ट हैं ब्रजेश सहाय जी। कई सालों से लड़ रहे हैं स्वास्थ्य के माफियाओं से। लेकिन ये स्वास्थ्य माफिया वाले की पैट इतनी जम चुकी है कि इन लोगों से लड़ना आसान नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय हैं। कुछ साल पहले चमकी बुखार मुजफ्फरपुर में फैला। उसकी समीक्षा बैठक हो रही थी। बच्चे मर रहे थे और स्वास्थ्य मंत्री पूछ रहे हैं कि वर्ल्ड कप क्रिकेट में क्या स्कोर है? तो यह तो स्वास्थ्य मंत्रालय विभाग का हाल हो गया। शिक्षा विभाग में देखिए कुछ साल पहले इंटर में टॉपर रही रूबी राय। पॉलिटीकल साइंस में उसने टॉप किया था बिहार में और उससे टी०बी० वालों ने पूछा कि पॉलिटीकल साइंस में किस चीज की पढ़ाई होती है? तो उसका जवाब था कि पॉलिटीकल साइंस में खाना पकाना सिखाया जाता है। तो नीतीश कुमार ने शिक्षा का बंटोधार कर दिया है और अब तो विश्वविद्यालयों में भी बड़े-बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं। कुलपतियों की शिकायतें हो रही हैं। कुलपतियों पर रेड पड़ रहे हैं।

★ राज्यपाल पर भी आरोप लग रहे हैं?

बिल्कुल। चांसलर हैं तो आरोप तो लगेंगे ही ना। मैंने तो राज्यपाल को भी हटाने की मांग की है। राष्ट्रपति को भी खत लिखा है। जबसे ये कुलाधिपति बन गये हैं श्री फागु चौहान, तब से विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक अराजकता फैल गई है। कॉपियों की जो खरीद होती है, उसमें करोड़ों के घोटाले की बात सामने आ रहा है। अभी मजहूरूल हक यूनिवर्सिटी के वी.सी. ने लिखा था कि मुझे राजभवन से फोन आता है। बाद में शायद मो० युनूस ने इस्तीफा भी दे दिया। उन्होंने कहा कि मुझ से राजभवन से प्रेशराइज किया जाता है भुगतान के लिए। तो ये क्या हो रहा है? तो पूरी शैक्षणिक अराजकता फैल गई है और देखिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दोनो बुनियादी चीजे हैं। यदि ये आदतों को नहीं सुधारियेगा तो राम मंदिर बनाने से कुछ नहीं होता है। शिक्षा और स्वास्थ्य बेसिक चीजें हैं और इन दोनों में भी आप देख ही रहे हैं कि बिहार में क्या हो रहा है। कैसे हालात हैं? अभी पिछले साल बिहार के मुख्य सचिव श्री अरूण कुमार सिंह की मोत हो गई थी और उनको सरकार अस्पताल में एक बेड भी नहीं दिला पायी। ये मुख्य सचिव की स्थिति है, आप सोचिए आम आदमी की क्या हालत होगी? आम आदमी तो पीएमसीएच के बरामदे पर मर जाये।

★ आज कई ऐसे आईएस हैं और कई आईपीएस हैं, जिनको नीतीश कुमार का करीबी माना जाता है और जो सरकार में निविदा का एल-1, एल-2 का जो खेल चल रहा है, उनको एक बड़े लाइज्जर के रूप में देखा जा रहा है। आप क्या कहेंगे?

ये तो नीतीश कुमार का पूरा गिरोह है ना। नीतीश कुमार गिरोहों का सरगना हैं, लेकिन बाकि लोग भी उस गिरोह में शामिल हैं, जो भ्रष्ट आईएस हैं, भ्रष्ट आईपीएस हैं। ये तो पूरा गिरोह चल रहा है। देखेंगे कि कुछ आईएस अधिकारी हैं बिहार के। लोगों के नजर में वह नवरत्न हैं। क्या कोई अकबर बादशाह थोड़े ही हैं। उन पर नीतीश की इतनी मेहरबानी है कि एक-एक अधिकारी के पास चार-चार, पांच-पांच प्रभार में हैं। इसके भी प्रभार में, उसके भी प्रभार में हैं। इतना ही नहीं, जब रियायर्ड कर जाते हैं तो उनको सेवा विस्तार मिल जाता है। ये लोग आज जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कल हो सकता है कि ये लोग भी जेल की हवा खाते दिखे। वक्त तो बदलता है ना। यहां इस दुनियां में सहाम हुसैन और गद्दाफी मिट्टी में मिल गये तो नीतीश कुमार किस खेत की मूली हैं। वक्त बहुत बलवान होता है और वक्त को बदलने में समय भी नहीं लगता है।


★ बिहार के एक आईपीएस, जो बेगूसराय जिला के मूल निवासी हैं, विकास वैभव। अभी बिहार में इम्प्रायर बिहार करके वह चला रहे हैं। बिहार की धूमिल छवि को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। यह पहल किस तरीके का है और क्या इसका परिणाम बिहार को मिलने वाला है?

ठीक है। विकास वैभव मेरे छोटे भाई के जैसा हैं और मेरी मुलाकात भी उससे है। बगहा का एस.पी. था तो मैं बगहा गया था और पढ़ने-लिखने वाला आदमी है और खासकर ऐतिहासिक चीजों में, ऐतिहासिक धरोहरों में उसकी रुचि है। तो अच्छा काम कर रहा है बिहार में। युवा लोगों के बीच कुछ अच्छा पहल ला रहा है तो मैं उसका स्वागत करता हूं।

★ बिहार की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे?

संदेश देने का तो मेरा कद नहीं है कि मैं संदेश देना शुरू कर दूं। लेकिन हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरे साथ लोग जुड़े। मैंने कहा था कि मेरा अपना संगठन है बिहार विप्लव परिषद और मैं माफिया से लड़ाई लड़ रहा हूं। लेकिन यहां इतना ज्यादा कार्यरता का आलम कहिए, बुजदिली का आलम कहिए कि 12 करोड़ बिहारियों में 12 लोग भी नहीं मुझे मिले

अमिताभ कुमार दास
(भापुरे-04-बिहार)
चेयरमैन
बिहार विप्लव परिषद
(समानता-स्वातंत्रता-मृत्यु)
मो: 7463924877



AMITABH KUMAR DAS
(IPS-04-BIHAR)
CHAIRMAN
THE BIHAR VIPLAV PARISHAD
(EQUALITY-LIBERTY-FRATERNITY)
MOBILE: 7463924877

दिनांक: 8-5-2021

8 मई 2021

सेवा में,
पुलिस महाविदेशक
बिहार, पटना।

विषय- कोरोना महामारी के दौरान माजपा सांसद का "एंबुलेंस घोटाला"

महोदय

- ① सूचनानुसार, वरिष्ठ राममक्त और माजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी के ठिकानों से, छिपा कर रखे गए दर्जनों एंबुलेंस बरामद किए गए हैं।
- ② कोरोना महामारी ने समूचे भारतवर्ष को शमशान बना डाला है। ऐसे में एक जनप्रतिनिधि द्वारा एंबुलेंस छिपा कर रखना "नरसंहार" के बराबर है। राजीव प्रताप रूडी के विरुद्ध महामारी अधिनियम (Epidemic Diseases Act 1897) के तहत तुरंत मामला दर्ज किया जाए।
- ③ राजीव प्रताप रूडी शुरू से विवादस्पद रहा है। एक केंद्रीय मंत्री के रूप में 1 जनवरी 2004 को उसने गोआ के होटल ताज में "न्यू ईयर पार्टी" की और बिना बिल चुकाए भाग खड़ा हुआ। बाद में पोल खुलने पर बिल चुकाया।
- ④ कृपया बिना राजनैतिक दबाव में आए, माजपा के लोक सभा सांसद राजीव प्रताप रूडी पर "महामारी अधिनियम" के तहत मामला दर्ज करें। अन्यथा मैं अदालत जाऊंगा।

आपका
अमिताभ
8-5-21

हैं, जो मेरे साथ जुड़ सके। तो इतना ज्यादा लोग कायर हो गये हैं, बुजदिल हो गये हैं। 12 करोड़ बिहारियों में 12 लोग मेरी टीम में नहीं आ सके। तो इसलिए बहुत सारे लोग डर के मारे फोन पर बात नहीं करते हैं कि नीतीश कुमार फोन टैप करवाता हो। तो मेरा यही कहना है कि बुजदिली थोड़ा छोड़िये, कार्यरता का त्याग करें। बिहार में चम्पारण सत्याग्रह हुआ था गांधी जी का। अंग्रेजों को हिला दिया गया था। तो बिहार तो क्रांति की भूमि रही है। यहां बुजदिली और कार्यरता से थोड़े ही काम चलता है।

★ कहा जाता है कि जयप्रकाश नारायण आंदोलन की उपज ही हैं नीतीश और लालू। इस पर क्या कहेंगे?

हाँ, सही है। कहा क्या जाये, ये तो सत्य है कि इन दोनों को पहले कौन जानता था। लोग तो जे.पी. मूवमेंट से हैं और सच पृच्छिए तो जे.पी. मूवमेंट को ऐसे नेताओं ने हाईजेक कर लिया। ये लोग उपज क्या रहेंगे। क्योंकि जिन आदर्शों के साथ जयप्रकाश का आंदोलन हुआ था, उस आदर्श पर तो नीतीश नहीं चल रहे हैं। जयप्रकाश नारायण ने तो ये नहीं कहा था कि मेवालाल चौधरी जैसे को शिक्षा मंत्री बना दें। वह तो सम्पूर्ण क्रांति की बात करते थे और नीतीश अब क्या कर रहे हैं, जान ही रहे हैं। ये जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। लव-कुश समीकरण की बात कर रहे हैं। 12 करोड़ बिहार के लोग हैं तो सबको साथ लेकर चलिए। ये लोग लव-कुश समीकरण कहां से आ गया। ये तो नीतीश कुमार का समीकरण है। तो जात-पात की बदबू फैला रहे हैं। ऐसे नेताओं ने जे.पी. मूवमेंट को हाईजेक कर लिया और जयप्रकाश की आत्मा जहां भी होगी, वह आत्मा बहुत कष्ट में होगी।



स्वास्थ्य मंत्री मरुत पीएमसीएच पर

स्वास्थ्य मंत्री के असहयोगात्मक रवैये के कारण पीएमसीएच में नहीं हो पा रहा है हृदय रोगियों का समुचित इलाज

● शशि रंजन सिंह/राजीव कुमार शुक्ला

पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1874 ई० में मेडिकल स्कूल के रूप में की गई थी और 1925 ई० में इसे मेडिकल कॉलेज के रूप में बदल दिया गया। इस मेडिकल कॉलेज का औपचारिक उद्घाटन 25 फरवरी 1925 को किया गया था। यह मेडिकल कॉलेज, बिहार में चिकित्सा शिक्षा का पथ प्रदर्शक होने का दावा रखता है। इस संस्थान में पोस्ट ग्रेजुएट की शुरुआत 1932 में की गई थी। ऑर्थोपेडिक्स, फिजियोलॉजी, गायनेकोलॉजी एवं रेडियोथैरेपी में स्नातकोत्तर शिक्षण सबसे पहले पूरे अविभाजित भारत में इस संस्थान में शुरू हुआ था। चिकित्सा छात्रों का पहला बैच



कोलकाता मेडिकल कॉलेज, कोलकाता में चिकित्सीय रूप से प्रशिक्षित किया गया था। अविभाजित भारत में इस संस्थान को सबसे पहले स्त्री रोग की शुरुआत हुई थी। कल का गौरव सारी पटना मेडिकल कॉलेज का इतिहास अपने आप पर आसू बहा रहा है।

पन्द्रह साल की लालू-राबड़ी की सरकार से होते हुए 16वें साल से सुशासन की सरकार का अब तक आश्वासन और घोषणाओं का क्रम जारी है। दूसरी तरफ यह चिकित्सा संस्थान पूरे बिहार के रोगियों का इलाज करते-करते आज आईसीयू में जाकर कराह रहा है। जबसे बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की कमान माननीय मंत्री मंगल पांडेय ने संभाला है, तब से घोषणाओं की झड़ी लगी रहती है। मंत्री महोदय सोशल

स्वास्थ्य विभाग के ढूलमूल रवैया के कारण मेडिकल के छात्र आधुनिक शिक्षा से वंचित

मीडिया पर बहुत ही तीव्र गति से एक्टिव रहते हैं, लेकिन मजाल है कि जब तक उनका कोई निजी हित ना हो तो उनके पास कोई फाइल सरक सके। चुकी माननीय मंत्री के हिमाचल के प्रभार में रहते हुए भाजपा ने राज्य में सरकार बनाई थी, तब से मंत्री जी का राजनीतिक कद बढ़ गया है। लेकिन जमीनी स्तर पर कभी भी चुनाव के माध्यम से नहीं चुना जाना, कहीं ना कहीं जनता का लगाव ना होना माना जा सकता है। माननीय मंत्री जी सत्ता के गणित में अपने प्यादे को इस तरह बिठाते हैं कि चित भी उनकी और पट भी उनकी। खैर! यह राजनीति की बातें हैं।

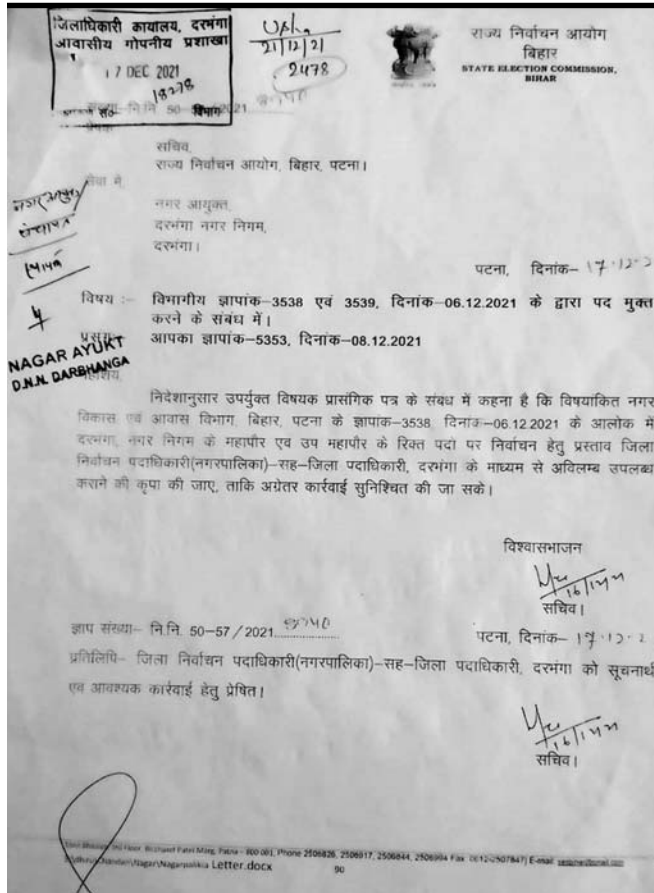
पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में हृदय रोग विभाग जिसमें मेडिसिन विभाग में देश के सबसे बड़े डिग्री धारक डॉक्टर तैनात वीरेन्द्र प्रसाद सिन्हा विभागाध्यक्ष (डीएम कार्डियोलॉजी), डॉक्टर अशोक कुमार, सहायक अध्यापक (डीएम कार्डियोलॉजी), डॉक्टर आशुतोष कुमार सिन्हा, सहायक अध्यापक (डीएम कार्डियोलॉजी), डॉक्टर उपेंद्र नारायण सिंह, सहायक अध्यापक (डीएम कार्डियोलॉजी) हैं। आपको बताते चलें कि पूरे बिहार में मात्र 35 डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर हैं, जिसमें सिर्फ 4 पीएमसीएच

में है, लेकिन इसका फायदा राज्य की जनता को नहीं मिल रहा है। क्योंकि सरकार इन्हें जरूरी उपकरण नहीं मुहैया करा रही है। मात्र 5.97 करोड़ की लागत वाले इस मशीन की स्थापना से हजारों रोगियों की हृदय रोग की समस्या दूर होगी और उसको इसका लाभ मिलेगा। देश के लगभग 10% आबादी हृदय रोग से पीड़ित है। अगर बिहार की आबादी को 15 करोड़ मान ले तो लगभग (डेढ़ करोड़) 1.5 करोड़ लोग बिहार में हृदय रोग से पीड़ित हैं और उसके लिए हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर की संख्या 30 से 35 है। ऊपर से पिछले 5 वर्षों से विभाग द्वारा मांगे जाने पर भी कैथ लैब और उपकरण उपलब्ध नहीं करवाना और सिर्फ लाल फीताशाही को नहीं दर्शाता है बल्कि स्वास्थ्य मंत्री के साथ जनता को क्या करना चाहिए, जनता जानती है। लेकिन जात-पात के दलदल में बिहार की जनता मजबूर है।

पीएमसीएच के हृदय रोग में सहायक प्राध्यापक डॉ आशुतोष कुमार सिन्हा ने केवल सच से बात करते हुए कहा कि रक्त वाहिका रोग, जैसे कोरोनरी धमनी रोग हृदय ताल की समस्याएं (अतालता), हृदय दोष, जिसके साथ आप पैदा हुए हैं (जन्मजात हृदय दोष), हृदय

वाल्व रोग, हृदय की मांसपेशी का रोग, हृदय संक्रमण, स्वस्थ जीवन शैली विकल्पों के साथ हृदय रोग के कई रूपों को रोका जा सकता है या उनका इलाज किया जा सकता है। हृदय रोग के लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि आपको किस प्रकार का हृदय रोग है। आपके रक्त वाहिकाओं में हृदय रोग के लक्षण, आपकी धमनियों में फ़ैटी प्लाक का निर्माण या एथेरोस्क्लेरोसिस (एथ-उर-ओ-स्कलुह-आरओई-सीआईएस) आपके रक्त वाहिकाओं और हृदय को नुकसान पहुंचा सकता है। प्लाक बिल्डअप संकुचित या अवरुद्ध रक्त वाहिकाओं का कारण बनता है, जिससे दिल का दौरा, सीने में दर्द (एनजाइना) या स्ट्रोक हो सकता है। पुरुषों और महिलाओं में कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लक्षण अलग-अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, पुरुषों को सीने में दर्द होने की संभावना अधिक होती है। महिलाओं में सीने में तकलीफ के साथ-साथ सांस लेने में तकलीफ, जी मिचलाना और अत्यधिक थकान जैसे अन्य लक्षण होने की संभावना अधिक होती है।

☞ **संकेत और लक्षणों में शामिल हो सकते हैं :-** सीने में दर्द, सीने में जकड़न, सीने में



प्राचार्य का कार्यालय, पटना मेडिकल कॉलेज, पटना।
दिनांक 06/3/21

पत्रांक 957

सेवा में
प्रमुख निदेशक
बी.एम.एस.आई.सी.एल.
बी.एस.बी.सी.सी.एल.
हॉस्पिटल रोड, शारदा नगर, पटना - 800023

विषय - पटना मेडिकल कॉलेज, पटना के एनोटोमी विभाग में एम.बी.बी.एस. छात्रों के पठन - पाठन हेतु आठ बोन सेट एवं दस सेट हिस्टोलॉजिकल स्लाइड एवं एक Virtual Dissector Table की आपूर्ति करने के संबंध में।

प्रसंग - इस कार्यालय का पत्रांक 846 दिनांक 01.03.20 (आयाप्रति सलन)।

प्रसंग - एनोटोमी विभाग, पटना मेडिकल कॉलेज, पटना का पत्रांक 27 दिनांक 05.02.21 एवं 34 दिनांक 20.02.21 (आयाप्रति सलन)।

महाराष्ट्र
उपरोक्त विषयक सन्दर्भ में सूचित करना है कि स्वास्थ्य विभागीय ड्राफ्ट 1081(1) दिनांक 28.09.2018 द्वारा पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना में सुपरस्पेशलिटी कार्डियोलॉजी विभाग के लिए वैश्वीक (Cash Lab.) का निर्माण अधिष्ठापन तथा उपकरणों की सूची उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भ में सूचित करना है कि स्वास्थ्य विभागीय ड्राफ्ट 692 (1) दिनांक 30.07.2014 द्वारा पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना में सुपरस्पेशलिटी कार्डियोलॉजी विभाग के लिए वैश्वीक एवं गैर-वैश्वीक पदों का सूजन किया गया है। वर्तमान समय में कार्डियोलॉजी विभाग में स्वीकृत पदों के विभिन्न विन्यासित चिकित्सक शिक्षक कार्यरत हैं -

क्र. सं.	चिकित्सक शिक्षक का नाम एवं पदनाम	योग्यता	स्वीकृत पद	कार्यरत बल	शिक्षा
01	डा. वैश्वीक प्रसाद सिन्हा सह-प्राध्यापक	डी०एम० कार्डियोलॉजी	01	00	01
02	डा. अशोक कुमार सहायक प्राध्यापक	डी०एम० कार्डियोलॉजी	02	01	01
03	डा. आशुतोष कुमार सिन्हा सहायक प्राध्यापक	डी०एम० कार्डियोलॉजी	03	03	00
04	डा. उपेन्द्र नाथयम सिंह सहायक प्राध्यापक	डी०एम० कार्डियोलॉजी	04	00	06
05	सीनियर रेजिडेन्ट		06	00	06

स्वास्थ्य विभागीय ड्राफ्ट 1081(1) दिनांक 28.09.2018 द्वारा पटना मेडिकल कॉलेज, पटना के कार्डियोलॉजी विभाग में सुपरस्पेशलिटी कोर्स (डी०एम० कोर्स) प्रारंभ करने हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा आवश्यक संसाधन की सूची की मांग की गयी थी जो पूर्व में भी उपलब्ध कराया गया था तथा पुनः अप्रारंभ करवाई हेतु उपलब्ध करायी जा रही है, जो निम्नवत है -

मशीन/उपकरण का नाम	अनुमानित व्यय राशि	अधिष्ठापन हेतु स्थान
1 कैथलैब-सभी आनुवांशिक उपकरणों के साथ। (On Turnkey Basis)	रु 3.50 करोड़	जगह उपलब्ध।
2 ईकोकार्डियोग्राफी मशीन उच्च स्तर का।	रु 70 लाख	जगह उपलब्ध।
3 टी०एम०टी० मशीन	रु 15 लाख	जगह उपलब्ध।
4 होल्टर मशीन	रु 12 लाख	जगह उपलब्ध।
5 अन्य आवश्यक संबंधित उपकरण (कैथ लैब से संबंधित)	रु 1.50 करोड़	जगह उपलब्ध।
कुल अनुमानित व्यय राशि	रु 5.97 करोड़	

दबाव और सीने में तकलीफ (एनजाइना), सांस लेने में कठिनाई यदि आपके शरीर के उन हिस्सों में रक्त वाहिकाओं को संकुचित किया जाता है, तो आपके पैरों या बाहों में दर्द, सुनता, कमजोरी या ठंडक, गर्दन, जबड़े, गले, ऊपरी पेट या पीठ में दर्द, जब तक आपको दिल का दौरा, एनजाइना, स्ट्रोक या दिल की विफलता न हो, तब तक आपको कोरोनरी धमनी की बीमारी का निदान नहीं किया जा सकता है। कार्डियोवैस्कुलर लक्षणों को देखना और अपने डॉक्टर से चिंताओं पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है। हृदय रोग को कभी-कभी नियमित मूल्यांकन के साथ जल्दी पाया जा सकता है। हृदय दोष के कारण हृदय रोग के लक्षण गंभीर हृदय दोष, जिनके साथ आप पैदा हुए हैं। जन्मजात हृदय दोष, आमतौर पर जन्म के तुरंत बाद देखे जाते हैं। बच्चों में हृदय दोष के लक्षण शामिल हो सकते हैं।

पीला, भूरा या नीला त्वचा का रंग (सायनोसिस), पैरों, पेट या आंखों के आसपास के क्षेत्रों में सूजन, एक शिशु में, दूध पिलाने के दौरान सांस की तकलीफ, जिसके कारण वजन कम होता है। कम गंभीर जन्मजात हृदय दोषों का अक्सर बाद में, बचपन में या वयस्कता के दौरान निदान नहीं किया जाता है। जन्मजात हृदय दोषों

के लक्षण जो आमतौर पर तुरंत जीवन के लिए खतरा नहीं होते हैं। व्यायाम या गतिविधि के दौरान आसानी से सांस लेने में तकलीफ होना, व्यायाम या गतिविधि के दौरान आसानी से थक जाना, हाथ, टखनों या पैरों में सूजन हृदय रोग के लक्षण हैं।

कैथ लैब को अंग्रेजी में Catheterization Laboratory कहते हैं और हिंदी में इसका फुल फॉर्म "नालशलाका-प्रवेशन प्रयोगशाला" होता है। किसी भी हॉस्पिटल तथा क्लीनिक में यह एक Enamination room के रूप में होता है, जिसमें नैदानिक इमेजिंग उपकरण होते हैं। जिसकी मदद से मनुष्य की दिल की धमनियों तथा दिल के कक्षों की कल्पना कर सकते हैं और किसी भी प्रकार के स्ट्रेनोसिस या असामान्यता का इलाज करने में सक्षम होते हैं। ज्यादातर कैथ लैब में single plane facilities होती है, जिसमें एक X-ray image intensifier मशीन होते हैं। इसके स्टाफ में Medical practitioner और Cardiac physiologist काम करते हैं।

अगर पटना चिकित्सा महाविद्यालय में कैथ लैब बना दिया जाए और सारे जरूरी उपकरण मुहैया करा दिया जाए तो हृदय रोग से संबंधित

Congenital heart disease, coronary artery disease, valvular heart disease, cardiomyopathy, hypertension, arrhythmia, peripheral vascular disease, Angioplasty, angiography, pacemaker, device closure, coiling, valve replacement, electrophysiology and radiofrequency ablation Valvoplasty बीमारियों का इलाज किया जा सकता है, लेकिन घोषणाओं के लिए मशहूर मंत्री और अफसर को जमीनी स्तर पर काम नहीं करना है, उनको सिर्फ भवन निर्माण करना है ताकि आका को दिखाया जा सके।

पीएमसीएच में सुपर स्पेशलिटी कार्डियोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ० वीरेंद्र प्रसाद सिन्हा, विभाग को लिखे अपने पत्र में कहते हैं कि पीएमसीएच में कार्डियोलॉजी विभाग के लिए अभी तक कैथ लैब का निर्माण एवं अधिष्ठापन नहीं हुआ है, जिसके कारण कार्डियोलॉजी विभाग में कार्यरत चारों चिकित्सक शिक्षक डीएम कार्डियोलॉजी विषय में विशेषज्ञ डिग्री एवं अनुभव रहने के बावजूद भी क्या कैथ लैब के कमी के कारण अपना पूर्ण कार्य एवं अनुभव का लाभ मरीजों को उपलब्ध नहीं करा

पा रहे हैं। चारों सुपर स्पेशलिटी विभाग यथा नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी विभाग से संबंधित मरीजों के जीवन रक्षा हेतु सबसे खतरनाक रूप में हृदय रोग ही है, जिसका इलाज कैथ लैब किया जाता है।

पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पटना के कार्डियोलॉजी विभाग के लिए कैथ लैब निर्माण एवं अधिष्ठापन हेतु पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पटना के इंदिरा गांधी केंद्रीय आकस्मिक विभाग के लिए आकस्मिक भवन स्थित तृतीय तल पर कार्डियोलॉजी विभाग के लिए कर्णाकिरित वार्ड के पास पर्याप्त स्थान उपलब्ध है, जहां पर सफल पूर्वक कैथ लैब का निर्माण एवं अधिष्ठापन हो सकता है।

डॉ वीरेंद्र प्रसाद सिन्हा ने केवल सच के माध्यम से जनता को जागृत करते हुए कहा कि डीएम कार्डियोलॉजी एंजियोग्राफी कर सकता है, एंजियोप्लास कर सकता है, हृदय के रोगियों कि खून की नली को खोल सकता है, सिकुड़ी बल्ब को डिलीट कर नॉर्मल बना सकता है, हृदय के विभिन्न छिद्रों को बंद कर सकता है। उन्होंने कहा कि छाती के बीच में दर्द शुरू होकर अगर बाईं तरफ की ओर बढ़े तो तुरंत हृदय रोग के चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि छाती भारी होने पर या चक्कर खाकर गिर जाने पर साथ ही धड़कन की गति बढ़ने पर भी हृदय रोग के चिकित्सक से तुरंत संपर्क करना चाहिए। आज जब बड़े-बड़े निजी अस्पताल में रोगियों को जमीन-जायदाद से लेकर बैंक तक खाली करवाने में लगे हुए हैं, उस समय मात्र 5.7 करोड़ की लागत से कई रोगियों को बचाया जा सकता है, लेकिन यह सरकार केवल दिखावा कर रही है और बिहार के इतने बड़े चिकित्सा अस्पताल में कैथ लैब ना होना हास्यप्रद के साथ-साथ सुशासन की सरकारी मानसिकता को भी दिखाता है।

दूसरी तरफ चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सा सेवा को आधुनिक और बेहतर करने के लिए प्रसाद पटना चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा वर्चुअल डिस्ट्रिक्टर टेबल मांगे जाने के बावजूद भी इसे उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। इससे साफ पता चलता है कि सरकार की मंशा सिर्फ घोषणाओं तक सीमित है। इस उपकरण से कितना फायदा मेडिकल छात्रों को हो सकता है, यह हम आपको बता रहे हैं।

एनाटोमेज टेबल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी शिक्षा के लिए सबसे तकनीकी रूप से उन्नत 3डी एनाटॉमी विजुअलाइजेशन और वर्चुअल विच्छेदन उपकरण है और इसे दुनिया के



कई प्रमुख मेडिकल स्कूलों और संस्थानों द्वारा अपनाया जा रहा है। इसे सम्मेलन, पीबीएस, फूजी टीवी और कई अन्य पत्रिकाओं में डिजिटल एनाटॉमी प्रस्तुति के लिए अपने अभिनव दृष्टिकोण के लिए चित्रित किया गया है। एनाटोमेज के प्रसिद्ध रेडियोलॉजी सॉफ्टवेयर और नैदानिक सामग्री के साथ संयुक्त ऑपरेटिंग टेबल फॉर्म फैक्टर एनाटोमेज टेबल को बाजार पर किसी भी अन्य इमेजिंग सिस्टम से अलग करता है। एनाटोमेज टेबल 8 टेबल पर मौजूद सॉफ्टवेयर का मौजूदा वर्जन है।

एनाटोमेज टेबल एकमात्र पूर्ण खंडित वास्तविक मानव 3डी एनाटॉमी सिस्टम है। उपयोगकर्ता शरीर रचना विज्ञान की ठीक उसी तरह कल्पना कर सकते हैं, जैसे वे एक ताजा शव पर करते हैं। व्यक्तिगत संरचनाओं को सटीक 3डी में फिर से संगठित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक सटीक शरीर रचना का एक अभूतपूर्व स्तर होता है, जो 3डी में विदारक होता है। तालिका मानव शरीर रचना विज्ञान की खोज और सीखने की अनुमति देती है, जो कोई भी शव पेश कर सकता है। एनाटोमेज टेबल

आधारित शिक्षा प्रभावी साबित हुई है। बढ़ते प्रकाशन बेहतर परीक्षण स्कोर, अधिक कुशल कक्षा और प्रयोगशाला सत्र और छात्र स्वीकृति दिखाते हैं। तालिका छात्रों को वृद्ध और पतित निकायों के बजाय युवा और अच्छी तरह से संरक्षित डिजिटल शवों के साथ बातचीत करने की अनुमति देती है। सटीक विवरण और समृद्ध सामग्री छात्रों की रुचि और ध्यान आकर्षित करती है, जिससे अधिक प्रभावी शैक्षिक परिणाम प्राप्त होते हैं। एनाटोमेज टेबल आपके संस्थान के लिए उपलब्ध उन्नत तकनीक है। छात्र, माता-पिता, पूर्व छात्र, या आगंतुक तालिका की उपस्थिति और दृश्य प्रभाव से प्रभावित होंगे। कोई रसायन नहीं हैं। कोई अप्रिय गंध नहीं है, कोई आवर्ती सुविधा लागत नहीं है, कोई नियम नहीं है और पारंपरिक शवों पर उच्च छात्र गोद लेने की दर है। यह प्रणाली पीएमसीएच को चिकित्सा शिक्षा का अगुआ प्रौद्योगिकी नेता के रूप में स्थापित कर सकता है। लेकिन बड़बोले स्वास्थ्य मंत्री को सिर्फ दिखावा करना है और अपना निजी हित साधना ही एकमात्र उद्देश्य है। केवल सच सच्चाई को उठाता है, उठाता रहेगा, चाहे लाख धमकियां आ जायें। ●



सुशासन की सरकार कर रही

बिहार सचिवालय सेवा कर्मी के साथ सौतेला व्यवहार

● शशि रंजन सिंह/राजीव कुमार शुक्ला

स चिवालय पटना में राजभवन के पूर्व में स्थित एक शक्तिशाली विक्टोरियन निर्माण है। अंग्रेजों द्वारा इंडो-सरसेनिक शैली में निर्मित, यह 1917 में बनकर तैयार हुआ था। यह 716 फीट लंबा, 364 फीट चौड़ा है और शहर की सबसे बड़ी सरकारी इमारतों में से एक है। जगह के खूबसूरत और हरे-भरे लॉन के बीच एक विशाल घंटाघर खड़ा है। मूल रूप से, यह 198 फीट ऊंचा था, लेकिन इसका एक हिस्सा 1934 के नेपाल-बिहार भूकंप के दौरान गिर गया। वर्तमान में इसकी ऊंचाई जमीन से 184 फीट है। परिसर में लॉन और अन्य उल्लेखनीय चीजें हैं, जैसे बिहार के पहले मुख्यमंत्री की कांस्य प्रतिमा, लॉन के पश्चिम में बिहार केसरी श्रीकृष्ण सिन्हा और 1942 के अगस्त क्रांति आंदोलन के दौरान सात छात्रों के बलिदान को याद करने के लिए शहीद

स्मारक। पटना सचिवालय भवन पटना शहर की उल्लेखनीय इमारतों में से एक है, जो अपने स्थापत्य वैभव के लिए जाना जाता है। इसे



शशांक शेखर

सिडनी के प्रसिद्ध वास्तुकार, जोसेफ मुनिंग्स द्वारा डिजाइन किया गया था और 1913-17 के दौरान कलकत्ता के मार्टिन बर्न द्वारा बनाया गया था। यह अपने ऊंचे घंटाघर के कारण शहर की किसी भी अन्य ऐतिहासिक इमारत से अलग है। आज यह बिहार राज्य सरकार का सचिवालय है। यह सभी प्रकार की सरकारी गतिविधियों का केंद्र है। सभी महत्वपूर्ण सरकारी विभाग, जैसे गृह, वित्त, सामान्य प्रशासन, कैबिनेट सचिवालय आदि यहाँ स्थित हैं। कालांतर में सरकार में विभागों की संख्या बढ़ती गई। उन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सचिवालय के दो नए भवन बनाये गये— एक का नाम विश्वेसरैया भवन है, जिसमें मुख्य रूप से भवन एवं पथ निर्माण विभाग हैं। दूसरा जिसे वर्तमान में नया सचिवालय के नाम से जाना जाता है। जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, नगर विकास, कृषि, उत्पाद एवं मद्य निषेध सहित कई महत्वपूर्ण विभाग हैं।

सचिवालय में तेजी से कार्य निष्पादन के लिए सचिवालय कैंडर की स्थापना की गई। आज यही सचिवालय कैंडर के कर्मचारी पूरे मंत्रालय की रिड के हड़ड़ी हैं। पूरा बिहार का सभी मंत्रालयों सहित सभी विभागों का संचालन इन्हीं के द्वारा होता है। लेकिन सरकार की हनक ने इन्हे बन्धुआ मजदूर बनने पर मजबूर कर दिया है। मानवीय भूल के लिए इन्हे सजा तो तुरन्त दे दी जाती है, लेकिन इनके अच्छे कार्यों के लिए इन्हें कभी भी सम्मानित नहीं किया जाता है।

सचिवालय राज्य के प्रशासन का सर्वोच्च नियंत्रक एवं शक्ति का केन्द्र होता है। सचिवालय सेवा के सदस्य सचिवालय के नीति विन्यासन, नीति विश्लेषण, नीति एवं कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन, आंकड़ों एवं संबद्ध तथ्यों के परिमार्जित तथा शुद्ध संग्रहण में महती भूमिका निर्वहन के कारण शासन के लिए अपरिहार्य

होते हैं। फलतः ये दस एवं अनुभवी कार्मिक राजनीतिक/प्रशासनिक शक्ति केन्द्र के सन्निकट माने जाते हैं। नेपोलियन का कहना था कि युद्ध कौशल में योग देने वाले चार तत्वों—संख्या, हथियार, प्रशिक्षण एवं मनोबल के कुल योगदान में 79 योगदान केवल मनोबल का होता है। परंतु विगत कुछ वर्षों से बिहार सचिवालय सेवा के सदस्यों के मनोबल में ड्रास एवं वृत्ति विकास के प्रति यह मिश्रित चिंता दिख रही है। किसी भी प्रबंध का उत्तरदायित्व है कि वह मनोबल के महत्व को समझे। उसे मापने के लिए मापदंड निश्चित करे और उसे बढ़ाने तथा बनाये रखने के साधनों को खोजता रहे। इस संबंध में बिहार सचिवालय सेवा संघ के महासचिव श्री प्रशांत कुमार ने प्रोन्नति, नियुक्ति, पदनाम परिवर्तन जैसे कुछ बिन्दुओं को रेखांकित किया, जिससे सचिवालय सेवा के सदस्यों में काफी मायूसी एवं शेष है।

विदित हो कि सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-5066, दिनांक-11.04.2019 द्वारा राज्य सरकार के सेवकों की प्रोन्नति पर रोक लगा दी गई है। प्रोन्नति की आस लिए कई अधिकारी/कर्मि सेवानिवृत्त हो गये। जिस अवधि में एक निजी संगठन में कार्यरत कर्मि प्रोन्नति के कई सोपान बढ़ जाता है, उस अवधि में राज्य सरकार के कर्मि एक ही पद पर बने रहते हैं, जिससे उनमें कुंठा पैदा हो जाती है। अंकनीय है कि बिहार राज्य में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा के सेवामार्गीयों की प्रोन्नति पर कोई रोक नहीं लगी है, फलतः उन्हें पूर्व निर्धारित तिथि पर प्रोन्नति मिल जाती है। प्रोन्नति के संबंध में राज्य सरकार की असवेदनशीलता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि विधानमंडल में एक प्रश्न के उत्तर में यह स्वीकार किया गया कि प्रोन्नति नहीं होने से कार्मिकों के



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 फाल्गुन 1931 (शुक्रवार, 26 फरवरी 2010)
(सं० पटना 159)

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
अभिसूचनाएं
25 फरवरी 2010

सं० 15/बि०सा०से०-02-02/2008का०-862—बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 03, 2008) की धारा-19 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उक्त अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती है :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ—(i) यह नियमावली "बिहार सचिवालय सेवा नियमावली, 2010" कही जा सकेगी।
- (ii) इसका विस्तार बिहार राज्य सरकार के सचिवालय के विभागों तथा संलग्न कार्यालयों तक सीमित रहेगा।
- (iii) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।
2. परिभाषाएँ— जब तक अन्यथा अर्थक्षित न हो, इस नियमावली में—
- (i) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 03, 2008);
- (ii) 'सेवा' से अभिप्रेत है बिहार सचिवालय सेवा;
- (iii) 'नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायकों के संदर्भ में सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग तथा सेवा के सभी उच्चतर ग्रेड या पदों के संदर्भ में बिहार के राज्यपाल;
- (iv) 'संलग्न कार्यालयों' से अभिप्रेत है, परिशिष्ट-1 में यथाविनिर्दिष्ट संलग्न कार्यालय;
- (v) 'परिशिष्ट' से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न परिशिष्ट;
- (vi) 'संवर्ग नियंत्री प्राधिकार' से अभिप्रेत है किसी ग्रेड के संबंध में सभी प्रयोजनों के लिए बिहार राज्य सरकार का कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग;
- (vii) 'सरकार' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार का कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग;
- (viii) 'ग्रेड' से अभिप्रेत है नियम-4 में विनिर्दिष्ट कोई ग्रेड;
- (ix) 'नियत तिथि' से अभिप्रेत है अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि; (04 जनवरी 2008)

2 बिहार गजट (असाधारण), 26 फरवरी 2010

निबंधन संख्या पी०टी०-40

- (x) 'सीधी मर्ती' से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी भयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति;
- (xi) 'सीमित प्रतियोगिता परीक्षा' से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा बनायी गई विनियमावली के अनुसार आयोजित सीमित प्रतियोगिता परीक्षा; तथा
- (xii) जिन शब्दों या विषयों को इस नियमावली में परिभाषित नहीं किया गया है उनका वही अर्थ होगा, जैसा कि अधिनियम में परिभाषित है।
3. प्राधिकृत स्थायी बल—
- (i) सेवा का ग्रेडवार संयुक्त प्राधिकृत स्थायी बल, अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि (दिनांक 04 जनवरी 2008) के ठीक पूर्व, अधिनियम की धारा-6 की उप-धारा (1) के आलोक में परिशिष्ट-2 में यथाविनिर्दिष्ट पदबल जो समय-समय पर यथावश्यक पदों के चुनन या समाप्ति या अन्यथा के अनुसार स्वतः पुनरीक्षित सम्झा जायेगा।
- (ii) उप-नियम (1) के अधीन मंजूर की गयी सेवा के प्राधिकृत बल के आधार पर संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा, विभिन्न विभागों के साथ-साथ संलग्न कार्यालयों में पदों की पहचान, राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर की जायेगी।
4. सेवा के विभिन्न ग्रेड एवं पद— (1) अधिनियम की धारा-4 के आलोक में, सेवा विभिन्न ग्रेडों के पद, उनका वर्गीकरण तथा नियुक्ति प्राधिकार निम्नानुसार होगा :-

क्र० सं०	पदनाम	वेतनमान (अपुनरीक्षित/पुनरीक्षित)	वर्गीकरण	अराजपत्रित/राजपत्रित	नियुक्ति प्राधिकार	अभ्युक्ति
1	सहायक	5500-9000/पे-बैन्ड-2 (9300-34,800) ग्रेड-पे-4600	समूह ख	अराजपत्रित	सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	
2	प्रशाखा पदाधिकारी एवं समतुल्य	6500-10500/पे बैन्ड-2(9300-34,800) ग्रेड पे-4800	समूह ख	राजपत्रित	बिहार-राज्यपाल	चार वर्षों की सेवा के उपरान्त पे-बैन्ड-3 (15,600-39,100) ग्रेड-पे-5400
3	अवर सचिव एवं समतुल्य	10000-15200/पे-बैन्ड-3 (15,600-39,100) ग्रेड-पे-6600	समूह क	राजपत्रित	बिहार-राज्यपाल	
4	उप सचिव एवं समतुल्य	12000-16500/पे-बैन्ड-3 (15,600-39,100) ग्रेड पे-7600	समूह क	राजपत्रित	बिहार-राज्यपाल	

- (2) उप-नियम (1) में अंकित वेतनमान राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षण/संशोधन के आलोक में स्वतः पुनरीक्षित/संशोधित सम्झा जायेगा।
5. संवर्ग नियंत्री प्राधिकार के शक्तियों का प्रयायोजन—
- (1) संवर्ग नियंत्री प्राधिकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अपनी कुछ शक्तियों को आयुक्त एवं सचिव/प्रधान सचिव/सचिव या विभागाध्यक्षों को प्रत्यायोजित कर सकेगा।
- (2) सेवा के किसी भी ग्रेड के सदस्य उस विभाग/कार्यालय के परिभालनात्मक नियंत्रण में होंगे, जिसमें वे पदस्थापित होंगे एवं उनके सेवान्त लभों, वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर प्रत्यायोजित शक्तियों के

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

ज्ञापांक:-15/बि0स0से0-02-01/2019सा0प्र0 2759.../पटना-15, दिनांक.28.02.2019
सेवा में,

*अनीपचारिक
रूप में
परामर्शित।

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

द्वारा:- *वित्त विभाग

विषय:-बिहार सचिवालय सेवा के विभिन्न ग्रेडों के पदों का पुनर्गठन के फलस्वरूप सहायक के 600, प्रशाखा पदाधिकारी के 182, अवर सचिव के 116, उप सचिव के 57 एवं निदेशक (संयुक्त सचिव स्तर) के 10 अतिरिक्त पदों का सृजन एवं पद-सृजन के फलस्वरूप वार्षिक व्यय ₹ 80,16,54,240/- (कुल अस्सी करोड़ सोलह लाख चौवन हजार दो सौ धालीस रुपया मात्र) की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय पर कहना है कि राज्य सरकार ने प्रशासी पदवर्ग समिति की अनुसंसा के आलोक में बिहार सचिवालय सेवा के विभिन्न ग्रेडों के पदों का पुनर्गठन के फलस्वरूप सहायक के 600, प्रशाखा पदाधिकारी के 182, अवर सचिव के 116, उप सचिव के 57 एवं निदेशक (संयुक्त सचिव स्तर) के 10 अतिरिक्त पदों का निम्नरूपेण सृजन करने का निर्णय लिया है:-

क्र०	पदनाम	वर्तमान में पद	पुनर्गठन के फलस्वरूप पद	वृद्धि
1	2	3	4	5
1.	सहायक	3231	3631	600
2.	प्रशाखा पदाधिकारी	815	997	182
3.	अवर सचिव	185	301	116
4.	उप सचिव	43	100	57
5.	निदेशक (संयुक्त सचिव स्तर का)	5	15	10
कुल पद:-		4279	5244	965

2. विभागवार/कार्यालयवार पदों की संख्या (अनुसूची-क के रूप में) संलग्न है।


3. उक्त पदों के पुनर्गठन के फलस्वरूप सृजित पदों पर अनुमानित वार्षिक व्यय ₹ 80,16,54,240/- (कुल अस्सी करोड़ सोलह लाख चौवन हजार दो सौ धालीस रुपया मात्र) संभावित है। (व्यय विवरणी संलग्न)

4. बिहार सचिवालय सेवा के उक्त पदों के सृजन पर होने वाला व्यय बजट शीर्ष "2052-सचिवालय सामान्य सेवाएँ-090-सचिवालय" के वेतनादि मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. संबंधित विभाग/कार्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी की जायेगी।


6. उपर्युक्त प्रस्ताव राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक 25.02.2019 की बैठक के मद संख्या-33 में स्वीकृत है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(गुफरान अहमद)
सरकार के उप सचिव


ज्ञापांक:-15/बि0स0से0-02-01/2019सा0प्र0 2759.../पटना-15, दिनांक.28.02.2019

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रालय, बिहार, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी 200 (दो सौ) प्रतियाँ मुद्रित कर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायी जाय।


सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:-15/बि0स0से0-02-01/2019सा0प्र0 2759.../पटना-15, दिनांक.28.02.2019

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, प्र०-3ए0/आय-व्यय शाखा/समी संबंधित कोषागार पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:-15/बि0स0से0-02-01/2019सा0प्र0 2759.../पटना-15, दिनांक.28.02.2019

प्रतिलिपि:-समी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/समी प्रमुख/सचिव/महाधिवक्ता का कार्यालय, बिहार, उच्च न्यायालय, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के उप सचिव

मनोबल पर कोई बुरा असर नहीं पड़ रहा है। प्रोन्नति पर रोक का प्रभाव यह है कि बिहार सचिवालय सेवा के कई सदस्यों द्वारा अर्हता पूरी करने के बावजूद इसके संयुक्त सचिव एवं उपसचिव के सभी पद रिक्त हैं, जबकि अवर सचिव के पदों में से 305 पद रिक्त हैं।

प्रोन्नति पर रोक के साथ सचिवालय सेवा के बेसिक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया

का वर्षों से बाधित रहना इस सेवा की दोहरी समस्या है। बिहार सचिवालय सेवा का मूल पद सचिवालय सहायक है। इसकी नियुक्ति पिछले दो बार से बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जा रही है। इससे पूर्व इसकी नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग एवं अवर सेवा आयोग द्वारा की गई है। जुलाई 2019 में बिहार सचिवालय सेवा के संवर्ग नियुक्ति प्राधिकार

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 1360 पदों की अधियाचना कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गई थी, परंतु ढाई वर्ष बाद वह विज्ञापन तक प्रकाशित नहीं कर पाया। सचिवालय सहायक की नियुक्ति हेतु सचिवालय सेवा संघ द्वारा सरकार को कई ज्ञापन दिया गया, परंतु सरकार इसके प्रति उदासिन है। बिहार राज्य संयुक्त सेवा महासंघ के समन्वयक शशांक शेखर सिन्हा

बिहार सचिवालय सेवा के विभिन्न पदों पर स्वीकृत बल, कार्यरत बल एवं रिक्ति की स्थिति दिसंबर 2021 मे तक निम्नवत थी :-

	Lohdr in	dk; j r cy	fjDr in	
1. सचिवालय सहायक	3964	1598	2366	
2. प्रशाखा पदाधिकारी	1040	375	665	
3. अवर सचिव	311	06	305	99% रिक्त
4. उप सचिव	102	00	102	पूर्णतः रिक्त
5. संयुक्त सचिव/निदेशक	16	00	16	पूर्णतः रिक्त
	5433	1979	3454	

कहते हैं कि सरकार, सचिवालय सेवा के कर्मियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। न ही उन्हें पदनाम दे रही है, न ही उन्हें वेतनमान दे रही है। उन्हें उनके पदनोति से भी वंचित कर रही है। बिहार सचिवालय सेवा संघ के महासचिव प्रशांत कुमार ने केवल सच से बात करते हुए कहा कि सरकार हमारे उचित मांगों पर शीघ्र निर्णय लेगी। पदनाम परिवर्तन हमारे सेवा से जुड़ा विषय है। हमे हमारा हक मिलना ही चाहिए।

वर्ष 2010 में जब प्रथम स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता का विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, तब सचिवालय सहायक के अतिरिक्त उसमें प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, अंचल निरीक्षक, आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, उद्योग विस्तार पदाधिकारी, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी जैसे कई पद भी उसमें शामिल थे। सचिवालय सहायक का पे ग्रेड-4600/- था, जबकि अन्य सभी पदों का पे ग्रेड-4200/- था। इस प्रकार सचिवालय सेवा इन सभी पदों से श्रेष्ठ मानी गई तथा परीक्षा में अबल आये अभ्यर्थियों की पहली पसंद सचिवालय सहायक थी। कालांतर में सचिवालय सहायक को छोड़ शेष सभी पदों पर नियुक्ति का अधिकार बिहार लोक सेवा आयोग को दे दिया गया एवं सचिवालय सहायक के पद पर नियुक्ति का अधिकार कर्मचारी चयन आयोग के पास ही रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि अन्य पदों पर नियमित नियुक्तियां होती रही, जबकि सचिवालय सहायक के पद पर नियुक्ति कराने में कर्मचारी चयन आयोग के फीडबैक को देखते हुए सरकार को यह ज्ञापन दिया कि सचिवालय सहायकों की नियुक्ति BPSK के माध्यम से करवाई जाए, ताकि सरकार को अचानक से कर्मियों की भारी कमी का सामना न करनी पड़े, परंतु इस मांग को भी कूड़ेदान में डाल दिया गया।

वही अप्रैल 2022 तक अवर सचिव के पद पर कार्यरत बल भी शून्य हो जायेगा। इस प्रकार सचिवालय सेवा के शीर्ष तीन पद पूर्णतः रिक्त हो जायेंगे। वर्ष 2023 तक प्रशाखा पदाधिकारी और सचिवालय सहायक अपने स्वीकृत बलों के एक तिहाई क्षमता के साथ राज्य में सुशासन को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की अब तक की कार्यक्षमता रही है। उसके अनुसार यदि आज विज्ञापन प्रकाशित होता है तो 2026 के पूर नियुक्ति संभव नहीं है। 2026 तक



प्रशांत कुमार

सचिवालय के कर्मियों की संख्या इतनी कम हो जायेगी कि पूरा ढांचा ही ध्वस्त हो जायेगा। यह आंकड़ा अत्यंत भयावह स्थिति प्रस्तुत कर रही है। विदित हो कि सरकार के 44 विभाग, 9 आयुक्त कार्यालय सहित राज्य के लगभग 100 से अधिक कार्यालय सचिवालय सेवा के कर्मियों के सहारे ही चल रहे हैं।

विगत कुछ वर्षों से सरकार में यह प्रवृत्ति दिख रही है कि नियुक्ति एवं प्रोन्नति को रोककर घड़ल्ले से सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की संविदा नियुक्ति की जा रही है। यह स्वस्थ प्रशासन के अनुकूल कतई नहीं माना जा सकता है। 60 साल में मनुष्य की कार्यक्षमता एवं मानसिक क्षमता कम हो जाती है। इस प्रकार बुजुर्गों की नियुक्ति से पूरी प्रशासनिक मशीनरी कुप्रभावित हो रही है। प्रोन्नति का अवसर नहीं मिलने से कार्यरत सरकारी सेवकों में हताशा घर कर रही है एवं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं में घोर निराशा एवं आक्रोश की भावना है। नित्य नये तकनिक एवं प्रक्रिया से अवगत होने में कुछ समय लगता है, लेकिन यदि नई नियुक्ति ही नहीं होगी और सेवानिवृत्त लोग चले जायेंगे तो भविष्य में नवनि्युक्त कर्मियों के व्यवहारिक प्रशिक्षण में भी समस्या उत्पन्न होगी। वर्तमान में यदि सचिवालय सेवा अपनी एक तिहाई क्षमता के साथ कार्य कर रहा है तो कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित होनी तय है। इसके बावजूद भी यह सुनने को मिलता है कि उच्चस्थ पदाधिकारियों द्वारा केवल अहम की तुष्टि के लिए विभागीय कार्यवाही जैसी प्रताड़ना का

प्रयोग किया जा रहा है। कुल मिलाकर यही प्रतीत होता है कि कर्मियों को जहां प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, वहां मनोबल तोड़ने पर अधिक ध्यान जा रहा है। दूसरी तरफ सचिवालय सेवा के सदस्य ने बताया कि वे विगत कई वर्षों से सरकार से अपने मूल पद सचिवालय सहायक का पदनाम बदल कर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी करने की मांग कर रहे हैं, जिसे सरकार के नुमाइंदा जानबूझकर टाल रहे हैं। चूंकि पदनाम परिवर्तन एक भावनात्मक मांग के साथ-साथ विधिक मांग भी है। अतः सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। सरकार को पदनाम बदलने में कोई आर्थिक बोझ नहीं है। बिना आर्थिक बोझ का वहन किये सरकार, सचिवालय सेवा के मनोबल को बढ़ा सकती है, परंतु सरकार में बैठे कुछ लोग इस जायज मांग के पूरा होने में बाधक बन रहे हैं।

विदित हो कि बिहार सचिवालय सेवा संघ की पदनाम परिवर्तन की मांग पर सरकार द्वारा तत्कालीन विकास आयुक्त श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक कमिटी गठित की गई थी, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग के सचिव भी शामिल थे। इस कमिटी ने सचिवालय सहायक का पदनाम सहायक प्रशाखा पदाधिकारी करने की अनुशंसा की थी, इस अनुशंसा पर महाधिवक्ता एवं वित्त विभाग द्वारा भी सहमति प्रदान की गई थी, तत्पश्चात् केवल संबंधित अधिसूचना निकाले जाने भर की देरी थी। जो आज लगभग डेढ़ वर्ष बाद भी जारी नहीं की जा सकी। कर्मियों के मनोबल कार्य के प्रति संतुष्टि को लेकर एल्टन मेयों से लेकर हर्जवर्ग एवं मैस्लो जैसे विद्वानों ने कई प्रयोग किये एवं निष्कर्ष दिये हैं। हार्थोन प्रयोग के माध्यम से एलटन मेयो ने यह साबित किया कि सामाजिक-मनोवैज्ञानिक तत्व कर्मियों के कार्य, मनोबल तथा उत्पादन को प्रभावित करते हैं। हर्जवर्ग ने अपने द्विघटक सिद्धांत में उत्प्रेरणात्मक घटक एवं आरोग्य घटक का सिद्धांत प्रतिपादित कर यह निष्कर्ष दिया कि कर्मियों में उत्प्रेरणा का आवश्यक उचित स्तर बनाये रखने से उनके असंतोष में कमी एवं संतोष में वृद्धि होती है। परंतु ऐसा लगता है कि बिहार सरकार बिल्कुल नये प्रयोगों पर चल रही है एवं उन तत्वों की भरसक उपेक्षा कर रही है, जिससे कर्मियों के मनोबल पर विपरीत प्रभाव पड़े। सचिवालय की यह सर्वप्रयोजी सामान्यवादी सेवा ब्यूरोपैथोलाज के कारण योगदान-संतुष्टि असंतुलन से संघर्षरत है। ●

बिहार में नर्सिंग कॉलेज का मतलब

खाता ना बही, जो कहे वही सही

● शशि रंजन सिंह/राजीव कुमार शुक्ला



धीरेन्द्र कुमार



निर्जला कुमारी

इं डियन नर्सिंग काउंसिल की स्थापना सन् 1974 ई० में संसद द्वारा पारित आदेश के बाद इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1947 के तहत हुई है। लेकिन बिहार में बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल की स्थापना बिहार और उड़ीसा नर्सिंग रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 के तहत हुई है। उस समय इसे दो समूहों में बांटा गया—एक का नर्स/परिचारिका, दूसरे को मिडवाइफ/दाई कहा गया। मिडवाइफ के लिए डिप्लोमा था, तो परिचारिका के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होना था।

आज पूरे दुनिया में स्वास्थ्य के क्षेत्र में नर्स के रूप में रोजगार की अपार संभावनाओं को देखते हुए कई निजी नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान कुकुरमुत्ता के तहत भ्रष्टाचार की गंगोत्री में नहाते हुए खोल दिए गए हैं। आज बिहार में कई नर्सिंग संस्थान कागज पर चल रहे हैं। बिहार का स्वास्थ्य विभाग इसे पैसे कमाने की मशीन की तरह चला रहा है। आज बिहार में अधिकतर निजी संस्थानों को पैसे के दम पर मान्यता दी गई है। जबसे

बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मंगल पांडे ने कार्यभार संभाला है, तब से स्वास्थ्य विभाग में ईमानदारी के साथ रिश्वतखोरी बढ़ गई है। हो सकता है इस आलेख के बाद मेरे साथ बहुत सारी षड्यंत्र किया जाए, लेकिन मेरा कलम अब रुकने वाला नहीं है।

दिनांक 5/08/2019 को तत्कालीन प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग श्री संजय कुमार ने

अपने आदेश संख्या-991(6) द्वारा एक आदेश सभी सिविल सर्जन बिहार को निर्गत करते हुए अपने आदेश में कहा कि, भारतीय उपचार्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के अनुसार एएनएम एवं उच्च नर्सिंग संस्थानों को 100 बेड का स्वयं अस्पताल होना अनिवार्य है। उन्होंने अपने आदेश में साफ कहा कि प्रस्तावक संस्थान के पास उपलब्ध बेड अस्पताल व्यवहारिक प्रशिक्षण के संबंध में अस्पताल की जांच संबंधित जिले के सिविल सर्जन से किए जाने तथा अस्पताल का बिहार क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से निर्बाध होना अनिवार्य किया गया है। इस आदेश में साफ शब्दों में कहा गया कि प्रस्तावक संस्थान का अनापत्ति देते हुए यह ध्यान रखना है कि एक बेड ब्रेकअप की उपलब्धता/शयाधान की उपलब्धता के साथ-साथ संस्थान को बिहार क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट निर्बाधित है कि नहीं, इसे स्पष्ट रूप से अनापत्ति देते हुए उल्लेख करें। आदेश में कहा गया है कि पैरेंट अस्पताल एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण से संबंधित दिशा-निर्देश एवं मापदंड के लिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल के वेबसाइट से उपलब्ध दस्तावेज से मिलान करें। इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा दिए गए निर्देश में साफ तौर से कहा गया है कि नर्सिंग कॉलेज के 100 बेड वाले मूल स्वयं का अस्पताल होना अनिवार्य है, नहीं तो ऐसे संस्थान जिसे नर्सिंग कॉलेज के निदेशक संबंधन अस्पताल

अनुमति रूप से आईएमसीएचएचएच के मानक के अनुरूप संबंधित अस्पताल का निर्माण करुण अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे। उक्त प्रमाण पत्र में संबंधित अस्पताल का बेड ब्रेकअप, बेड की उपलब्धता, शयाधान वर की उपलब्धता तथा अस्पताल Bihar Clinical Establishment Act से निर्बाध है अथवा नहीं का भी उल्लेख रहेगा। उक्त अस्पतालों में कार्यरत शिक्षणार्थ एवं पारामेडिकल कर्मियों की विवरणी भी उपलब्ध कराया जाएगा। उक्त प्रमाण पत्र तीन प्रति में तैयार किया जाएगा। एक प्रति निर्गत करने वाले कार्यालय में स्थायित होगा। दूसरा प्रति प्रस्तावक संस्थान को उपलब्ध कराया जाएगा तथा तीसरी प्रति निदेशक प्रमुख (नर्सिंग), स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना के नाम भेजकर विभाग की उपलब्ध कराया जाएगा।

(i) इसके उपरान्त प्रस्तावक ट्रस्ट/सोसाइटी/कम्पनी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए नर्सिंग संस्थानों की स्थापना के लिए अनुमति हेतु निर्गत विहित प्रपत्र में आवेदन निदेशक प्रमुख (नर्सिंग), स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना के नाम से करेंगे।

(ii) पूर्व से स्थापित भाष्यता प्राप्त संस्थान अपने पैरेंट अस्पताल को Bihar Clinical Establishment Act से विधायन कर लेते एवं बेड ब्रेकअप, बेड की उपलब्धता तथा शयाधान वर के संदर्भ में संबंधित जिले के सिविल सर्जन से तीन माह के अन्दर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर विभाग को सूचित करेंगे।

शिवशामराज
24/7/19/19
(नर्सिंग प्रमुख)
प्रधान सचिव।

आदेश संख्या-991(6) दिनांक-5/8/2019

विषय: राज्यों के अनापत्ति निजी क्षेत्र में नर्सिंग संस्थानों की स्थापना के लिए पैरेंट अस्पताल एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु अस्पताल की जांच के संबंध में।

प्रस्ताव: उपर्युक्त विषय के संबंध में अज्ञात है कि राज्यों के अनापत्ति निजी क्षेत्र में नर्सिंग विद्या हेतु भाष्यता प्राप्त एएनएमएच/डीएनएमएच/बीएनएमएच (नर्सिंग)/केएच डेंटिक बीएनएमएच (नर्सिंग) एवं एएनएमएच (नर्सिंग) प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हैं। नर्सिंग प्रशिक्षण-निकाशित एकेडमिस्ट्रीयन एवं केएचएच डेंटिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए नर्सिंग कानून, 1947 के नियम-04 के उपबन्ध-11 के अन्तर्गत कौशल प्रमाणपत्र नर्सिंग संस्थानों की स्थापना में लिए अनुमति प्रदान किया जाता है। उपरोक्त उपबन्ध-11 के अन्तर्गत निदेशक प्रमुख द्वारा संस्थान का निर्माण करके अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है।

आदेश संख्या-991(6) दिनांक-5/8/2019 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार एएनएमएच एवं उच्चतर नर्सिंग संस्थानों की स्थापना के लिए 100 बेड का पैरेंट अस्पताल का अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे। एएनएमएच के लिए 150 बेड वाले जिले अस्पताल या क्षेत्रीय स्तर अस्पताल तथा बीएनएमएच स्वास्थ्य कार्यलयों में अनुमति हेतु न्यूनतम 30 एवं अधिकतम 50 बेड की संख्या वाले उच्चतर अस्पताल से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा है। इसके निर्मित प्रस्तावक संस्थान के पास उपलब्ध पैरेंट अस्पताल/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु संबंध अस्पताल की जांच संबंधित जिले के सिविल सर्जन से किया जाने तथा अस्पताल का Bihar Clinical Establishment Act से निर्बाध होने की अनुमति किया गया है। पैरेंट अस्पताल एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण से संबंधित दिशा-निर्देश एवं मापदंड की प्रति वेबसाइट www.indiannursingcouncil.org पर उपलब्ध है।

3-राज्यों के अनापत्ति निजी क्षेत्र में नर्सिंग कलेज/संस्थान की स्थापना के लिए अस्पताल की जांच हेतु निर्गत दिशा-निर्देश एवं प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है :-

(i) नर्सिंग संस्थानों की स्थापना के निर्मित प्रस्तावक ट्रस्ट/सोसाइटी/कम्पनी पैरेंट अस्पताल/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु संबंध अस्पताल की जांच हेतु संबंधित जिले के सिविल सर्जन का नाम अनिवार्य तौर पर आवेदन सूचीबद्ध करेंगे। सिविल सर्जन आवेदन प्रपत्र के एक पृष्ठ के अन्तर्गत

शुक्र, 04 जुलै 2020

2020 No. 11-30000

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY [PART III-SEC.4]

शुक्र, 04 जुलै 2020: बंगालूर



संकेत: टी.एन. 30-0607/2021-228110 CG-DL-6-60872021-231810

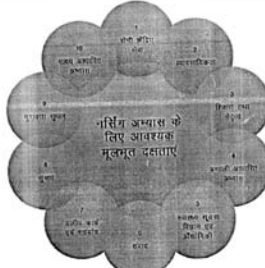
व्यवस्थापक EXTRAORDINARY PART III-SECTION 4 अधिनियम के अधीन प्रकाशित

नं. 275 नई दिल्ली, बुधवार, 4 जुलाई 2020, भा.शा.सा. 14, 1942 नं. 275 NEW DELHI, MONDAY, JULY 6, 2020/ASHA.SHA 14, 1942

राष्ट्रीय अस्पताल अधिनियम, 2020

राष्ट्रीय अस्पताल अधिनियम, 2020 (2020 का XLVIII) अधिनियम, 2020... 1. नर्सिंग अधिनियम, 2020... 2. नर्सिंग अधिनियम, 2020... 3. नर्सिंग अधिनियम, 2020... 4. नर्सिंग अधिनियम, 2020... 5. नर्सिंग अधिनियम, 2020... 6. नर्सिंग अधिनियम, 2020... 7. नर्सिंग अधिनियम, 2020... 8. नर्सिंग अधिनियम, 2020... 9. नर्सिंग अधिनियम, 2020... 10. नर्सिंग अधिनियम, 2020...

1. नर्सिंग अधिनियम, 2020... 2. नर्सिंग अधिनियम, 2020... 3. नर्सिंग अधिनियम, 2020... 4. नर्सिंग अधिनियम, 2020... 5. नर्सिंग अधिनियम, 2020... 6. नर्सिंग अधिनियम, 2020... 7. नर्सिंग अधिनियम, 2020... 8. नर्सिंग अधिनियम, 2020... 9. नर्सिंग अधिनियम, 2020... 10. नर्सिंग अधिनियम, 2020...



11. नर्सिंग अधिनियम, 2020... 12. नर्सिंग अधिनियम, 2020... 13. नर्सिंग अधिनियम, 2020... 14. नर्सिंग अधिनियम, 2020... 15. नर्सिंग अधिनियम, 2020... 16. नर्सिंग अधिनियम, 2020... 17. नर्सिंग अधिनियम, 2020... 18. नर्सिंग अधिनियम, 2020... 19. नर्सिंग अधिनियम, 2020... 20. नर्सिंग अधिनियम, 2020...

21. नर्सिंग अधिनियम, 2020... 22. नर्सिंग अधिनियम, 2020... 23. नर्सिंग अधिनियम, 2020... 24. नर्सिंग अधिनियम, 2020... 25. नर्सिंग अधिनियम, 2020... 26. नर्सिंग अधिनियम, 2020... 27. नर्सिंग अधिनियम, 2020... 28. नर्सिंग अधिनियम, 2020... 29. नर्सिंग अधिनियम, 2020... 30. नर्सिंग अधिनियम, 2020...

31. नर्सिंग अधिनियम, 2020... 32. नर्सिंग अधिनियम, 2020... 33. नर्सिंग अधिनियम, 2020... 34. नर्सिंग अधिनियम, 2020... 35. नर्सिंग अधिनियम, 2020... 36. नर्सिंग अधिनियम, 2020... 37. नर्सिंग अधिनियम, 2020... 38. नर्सिंग अधिनियम, 2020... 39. नर्सिंग अधिनियम, 2020... 40. नर्सिंग अधिनियम, 2020...

41. नर्सिंग अधिनियम, 2020... 42. नर्सिंग अधिनियम, 2020... 43. नर्सिंग अधिनियम, 2020... 44. नर्सिंग अधिनियम, 2020... 45. नर्सिंग अधिनियम, 2020... 46. नर्सिंग अधिनियम, 2020... 47. नर्सिंग अधिनियम, 2020... 48. नर्सिंग अधिनियम, 2020... 49. नर्सिंग अधिनियम, 2020... 50. नर्सिंग अधिनियम, 2020...

में ट्रस्टी निदेशक के रूप में हो। उस अस्पताल को किसी अन्य नर्सिंग संस्थान अस्पताल से संबंधन की मान्यता की अनुमति नहीं देगा और यह वचन पत्र कम से कम 30 वर्षों के लिए वैध होगा। साथ ही इस आदेश में स्पष्ट रूप से आदेश है कि मूल अस्पताल की सभी बेंड एक ही अस्पताल में अर्थात् एक ही भवन एक ही परिसर में होने चाहिए। इस आदेश को राजपत्र संख्या-275, दिनांक- 5 जुलाई 2021 को भारत का राजपत्र के रूप में लाया गया है। भारतीय उपचार्या परिषद और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के आदेश को टेंगा दिखाते हुए पूरे बिहार में कुकुरमुत्ता के तहत नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी गई है। स्वास्थ्य सेवा निदेशक प्रमुख कौशल कुमार अध्यक्ष बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन परिषद और पूर्व रजिस्ट्रार/निबंधक रितु कुमारी सिन्हा के माध्यम से सैकड़ों फर्जी नर्सिंग कॉलेज की स्थापना पूरे बिहार में की गई है। जिस नर्सिंग कॉलेज की स्थापना फर्जी तरीके से हुई है। उसके छात्रों को सुर्ई भी नहीं लगाना आता है। वैसे छात्रों को खुलेआम नर्सिंग का प्रमाण पत्र बांटा गया है। समाजसेवी धीरेन्द्र कुमार कहते हैं कि अप्रशिक्षित नर्स के

गलती से एक भी मरीज की मौत होती है तो उसके लिए विभागीय मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि हम सुशासन के प्रतीक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग करते हैं कि, ऐसे किसी भी मौत के लिए पूर्व अध्यक्ष बिहार नर्सिंग परिषद कौशल कुमार और पूर्व रजिस्ट्रार रितु कुमारी सहित विभागीय मंत्री और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 120, 120 बी और 304 के तहत उन पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाए।

सं0सं0-6/N-08-07/2019.19294(6)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य निदेशालय

प्रेषक, **डॉ० नवीन चन्द्र प्रसाद, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना।**

सेवा में, **निदेशक/ प्राचार्य (सूची के अनुसार)**

पटना, दिनांक: 10 / 12 / 2021

विषय: विभागीय दिशा-निर्देश का अनुपालन नहीं किये जाने के लिए स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग: स्वास्थ्य निदेशालय का आदेश संख्या-6/एन0-08-07/2019, दिनांक-21.05.2019, आदेश संख्या-6/एन0-08-07/2019, दिनांक-27.07.2019, पत्रांक-768(6), दिनांक-16.07.2021 एवं पत्रांक-769(6), दिनांक-16.07.2021

गहाशय, निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के अन्तर्गत नर्सिंग शिक्षा में गुणात्मक सुधार के निमित्त मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थानों के लिए आदेश क्रमांक-631(6), दिनांक-17.05.2019 तथा 944(6), दिनांक-26.07.2019 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किया गया एवं प्रेस विज्ञापित का प्रकाशन भी किया गया। उक्त निर्देश के अनुसार दिनांक-26.08.2019 तक संस्थानों का अपना वेबसाईट तैयार करना था एवं उस पर नर्सिंग संस्थान से संबंधित नामांकित/उत्तीर्ण वर्षवार प्रशिक्षणार्थियों, शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक कर्मी, स्कूल एवं संचालक ट्रस्ट/सोसाईटी का नाम, पूरा पता, दूरभाष संख्या, शैक्षणिक/छात्रावास भवन का फोटोग्राफ एवं विवरणी भी अपलोड करने का निर्देश दिया गया था। साथ ही यह भी सूचना अंकित करने का निर्देश था कि उक्त नवनों में नर्सिंग पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त कोई अन्य पाठ्यक्रम संचालित है अथवा नहीं।

2.-निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना के पत्रांक-1844, दिनांक-03.09.2019, पत्रांक-3035, दिनांक-06.10.2021 एवं पत्रांक-3078, दिनांक-18.10.2021 द्वारा भी नर्सिंग संस्थानों को वेबसाईट तैयार करने एवं वेबसाईट पर अपलोड किये गये डाटा की विवरणी उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया। निर्धारित अवधि में वेबसाईट तैयार करने के उपरान्त संस्थान को उक्त अनुपालन की सूचना, निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, बिहार, पटना को देना अनिवार्य किया गया था, परन्तु निम्नांकित संस्थानों द्वारा इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की गयी है -

Sl.No	Name of Nursing School/College	Nursing Course Name
1	Akash Nursing Institute, Buxar	ANM

के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि हम सुशासन के प्रतीक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग करते हैं कि, ऐसे किसी भी मौत के लिए पूर्व अध्यक्ष बिहार नर्सिंग परिषद कौशल कुमार और पूर्व रजिस्ट्रार रितु कुमारी सहित विभागीय मंत्री और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 120, 120 बी और 304 के तहत उन पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाए। इस संबंध में बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल पटना के रजिस्ट्रार/निबंधक श्रीमती निर्मला कुमारी, नव पदस्थापित निदेशक प्रमुख नर्सिंग महेश प्रसाद गुप्ता से बात की तो उन्होंने कहा कि हम पूरे मामले को देख रहे हैं। इस संबंध में जांच कर जल्द ही कार्रवाई की जा रही है। केवल सच दोनों पदाधिकारियों से अपेक्षा करती है कि सच का साथ देंगे और भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसी जायेगी। केवल सच इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है। केवल सच ने अपनी पिछली आलेख में श्यामलाल चंद्रशेखर नर्सिंग कॉलेज, खगड़िया का चित्र प्रकाशित किया था तो उनके निदेशक को घोर आपत्ति हुआ। उनका कहना है कि

Sl. No.	Name of the Institution	Program
46	Magadh ANM Training School, Anand Vihar, Sobhiya, Akbarpur, Nawada	ANM
47	Aryabhata Institute of Nursing & Paramedical, Ashiyana Digha Road, Patna	ANM
48	Raj ANM training School, Muzaffarpur	ANM
49	S.A Institute of Nursing, Nalanda	ANM
50	Mahabir Nursing School, Nh-28, Muzaffarpur	ANM
51	Madhubani Institute of Nursing and Paramedical Science, Madhubani-847212	ANM
52	Patel School of Nursing, Jehanabad	ANM
53	Narayan Nursing College, Jamuhar, Sasaram, Rohtas	GNM
54	Apollo Nursing Training School, Saidnagar, Laheriasarai, Darbhanga	GNM
55	Yamuna Institute of Nursing, Rajaura, Begusarai	GNM
56	Verma College of Nursing & Paramedical Science, Ara	GNM
57	M G M College of Nursing and Paramedical, Ajad Nagar, Patna	GNM
58	Shubhadra Devi School of Nursing, S.D.O. Road, Hajipur, Vaishali	GNM
59	National Institute of Nursing and Paramedical Sciences, Chandl, Nalanda-803108	GNM
60	Vivekanand Paramedical and Nursing College, Near DAV School, Gaya Dobhi, Road, Gaya	GNM
61	Magadh Paramedical and Nursing Institute ((B.Sc.(N)) Kevala, Dhamna, Gaya	GNM
62	Triveni College of Education, Kunti Nagar, Nawada	GNM
63	Sri Raj Nursing Training institute, Bus stand road, Near Jakkanpur, Patna	GNM
64	Best Nursing Institute (GNM), Buxar	GNM
65	Guro Binda College, Nawada	GNM
66	Narayan Nursing college, Sasaram, Rohtas	BSC (N)
67	Shyam Lal Chandra Shekhar Nursing College, Khagaria	BSC (N)
68	Prameela Adhar Nursing College Satapur, Samastipur	BSC (N)
69	M.G.M. College of Nursing and Paramedical, Ajad Nagar, Patna	BSC (N)
70	Dr. Trishuldhari Pandey Memorial College of Education (B.Sc.(N) Nursing College), Tharthari, Nalanda	BSC (N)
71	Magadh Paramedical and Nursing Institute (B.Sc.(N)), Kevala, Dhamna, Gaya	BSC (N)
72	Vivekanand Paramedical and Nursing College, Near DAV School, Gaya Dobhi, Road, Gaya	BSC (N)
73	Verma College of Nursing and Paramedical Science, Anaith, Ara, Bhojpur	BSC (N)
74	Mona School of Nursing and Paramedical College, Trilok Nagar, Agamkuan, Patna	BSC (N)
75	Priyadarshini Nursing Institute, Beta Chowk, Darbhanga	BSC (N)
76	Applo College of Nursing, Darbhanga	BSC (N)
77	Yamuna Institute of Nursing, Rajaura, Begusarai	BSC (N)
78	Katihar BSC Nursing College, Katihar	BSC (N)

3-राज्य सरकार नर्सिंग शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए प्रतिबद्ध एवं सतत प्रयासरत है। समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी विभागीय निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जाना परिलक्षित करता है कि उपर्युक्त संस्थान नियमानुकूल रूप से संचालित नहीं है। यह अत्यन्त ही गंभीर मामला है जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती।

1224(6)
10/12/2021

1/18/22, 6:28 PM
Gautam Institute of Nursing and Paramedics

This course of Auxiliary Nurse Midwife of Nursing acquires Two years (2 years)

This course of M.Sc. Nursing of Nursing acquires Two years (02 years)

60 Seat 2 Years Details

Clinical Training Facility

The students of Gautam Institute of Nursing & Paramedics are getting their clinical experience training at following hospitals:-

1. Sri Ram Govind Pyare Hospital, Chandl
2. Prabhat Nursing Home, Chandl
3. Vardhaman Institute of Medical Sciences, Pawapuri
4. Sadar Hospital, Biharsharif
5. Sub-divisional Hospital, Hilsa
6. Referral Hospital, Chandl
7. Primary Health Centre, Tharthari
8. Bihar State Institute Mental Health & Allied Sciences, Koelwar (Bhojpur)

REGISTER NOW

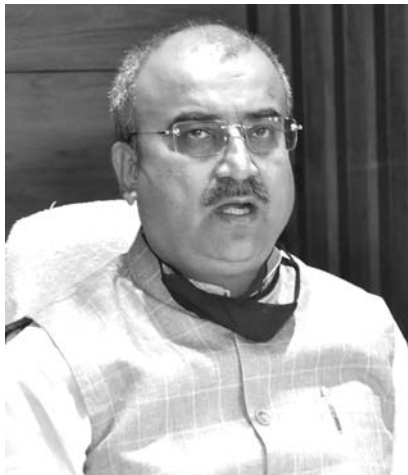
GALLERY - GINP

Gautam Institute of Nursing & Paramedics (GINP) is sharing some of the gallery images of campus and students.



उनका संस्थान विश्वस्तरीय है और उनका भवन देश के सबसे अच्छे भवनों में से है। लेकिन बिहार सरकार के आदेश संख्या-1224(6), दिनांक-10.12.2021 में श्यामलाल चंद्रशेखर नर्सिंग कॉलेज, खगड़िया सहित 78 नर्सिंग कॉलेजों को विभागीय दिशा निर्देश का अनुपालन नहीं किए जाने के लिए स्पष्टीकरण पूछा गया और कहा गया कि- स्वास्थ्य निदेशालय का आदेश संख्या-6/एल-08-07/2019, दिनांक 2105-2019, आदेश संख्या-6/एल-08-07/2019 दिनांक-27-07-2019, पत्रांक-768(6), दिनांक-16-07-2021 एवं पत्रांक-769(6), दिनांक-16-07-2021 के साथ बिहार परिचारिका निबंधन परिषद पटना के पत्रांक-1844, दिनांक-03-09-2019, पत्रांक-3035, दिनांक-06-10-2021 एवं पत्रांक-3078, दिनांक-18-10-2021 द्वारा भी नर्सिंग संस्थानों को वेबसाइट तैयार कर वेबसाइट पर डाटा की विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। उक्त आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि नर्सिंग

संस्थान से संबंधित नामांकित उत्तीर्ण वर्ष वार प्रशिक्षक और शैक्षणिक कर्मी, गैर शैक्षणिक कर्मी, शैक्षणिक भवन, छात्रावास भवन का फोटोग्राफ भी विवरणी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दें। साथ ही यह भी सूचना देना था कि उक्त भवनों में नर्सिंग पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त कोई भी अन्य



पाठ्यक्रम संचालित है या नहीं। लेकिन संस्थानों द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अतः यह गंभीर मामला है। इस स्पष्टीकरण में साफ तौर से कहा गया है कि विभागीय निर्देश की अवहेलना के लिए क्यों नहीं नियमानुसार विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। लेकिन श्यामलाल चंद्रशेखर नर्सिंग कॉलेज, खगड़िया सहित सभी नर्सिंग कॉलेजों में शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक शैक्षणिक कर्मचारी लगभग एक दूसरे में समाहित होते हैं, इसलिए संस्थानों द्वारा यह विवरण उपलब्ध नहीं करवाई गई। संस्थानों के साथ यह स्थिति है कि “जब सैंया भए कोतवाल तो डर काहे का”। जब निजी नर्सिंग संस्थान की जेब में अधिकारी हो तो स्पष्टीकरण सिर्फ आंख साफ करने का प्रेम पत्र ही होकर रह सकता है। इस स्पष्टीकरण को भी नर्सिंग शिक्षा माफियाओं ने कोई तरजीह नहीं दी और उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। मजबूरन विभाग के अपर सचिव कौशल किशोर ने अपने आदेश संख्या-03(6) दिनांक 7.01.2022 को एक आदेश नर्सिंग कॉलेज के निदेशक/ प्रचार्या/सचिव को

देते हुए कहा कि माननीय उच्च न्यायालय पटना के याचिका संख्या 13720/2021 में दिए गए आदेश के आलोक में प्राप्त अभ्यावेदन में संस्थान की गुणवत्ता में सुधार एवं निर्धारित मानक के आलोक में इनके संचालन की आवश्यकता को देखते हुए सभी निजी नर्सिंग संस्थान को Google Form में डाटा तैयार कर 5 दिनों के अंदर अर्थात् 12/01/2022 तक निश्चित रूप से उपलब्ध करवा दें। लेकिन कई संस्थानों ने अभी तक इसका अनुपालन नहीं किया। जिस संस्थान ने किया भी उनकी भी जांच की आवश्यकता है। करे भी क्यों? जब मंत्री से लेकर संतरी तक इस महाभ्रष्टाचार के आकंट में डूबे हो तो सरकारी आदेश सिर्फ दिखावा ही हो सकता है। आज केवल सच इस बात को दावे के साथ कहता है कि कुछ संस्थान को छोड़कर अधिकतर संस्थानों के पास ना तो अपना अस्पताल है, ना ही परिभाषित शैक्षणिक परिसर है। सरकार को अगर जांच करनी है तो जिले के बिहार क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत निर्बंधित अस्पतालों की पूरी विवरणी मंगा कर देख ले, सारा प्रमाण उन्हें मिल जाएगा। लेकिन अधि कारी और मंत्री ऐसा नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनकी पोल खुल जाएगी। नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए जो भौतिक सत्यापन की कमेटी बनाई गई थी, आज कमेटी में एक-एक सदस्य करोड़पति हो गए, हम यह डंके की चोट पर कह रहे हैं।

ऐसे तो कई निजी नर्सिंग संस्थान फर्जी रूप से चल रहे हैं, लेकिन हम बात कर लेते हैं माननीय मुख्यमंत्री के गृह जिले नालंदा की, जहां का एक निजी नर्सिंग संस्थान गौतम इंस्टिट्यूट ऑफ नर्सिंग पारामेडिकस अपने संस्थान को छात्रों की क्लीनिकल ट्रेनिंग दूसरे निजी संस्थान और तो और सरकारी संस्थानों में करवाने के बात खुलेआम अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करता है। कहाँ गई सुशासन की सरकार? कहाँ गया भाजपा का भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का वादा? स्वास्थ्य विभाग में एक कहावत है, 'खाता न बही, जो मंत्री जी कहे वही सही'। बिहार के निजी नर्सिंग संस्थान मंत्री से लेकर संतरी तक के लिए दुधारू गाय बनकर रह गई है और यह कहावत है कि दुधारू गाय की लतारभली, चाहे लाख भ्रष्टाचार होता है लेकिन जब तक भ्रष्टाचार रूपी नर्सिंग कॉलेज से पैसा आ रहा है, इसे छूने वाला कोई नहीं। अपने

सं०सं०- AT/8/2022-SEC6-HEA-HEALTH-03.62...

बिहार सरकार
स्वास्थ्य निदेशालय

प्रेषक, कौशल किशोर,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में, निदेशक/प्राचार्य/सचिव/सेटलर,
राज्य के सभी निजी नर्सिंग स्कूल/संस्थान/कॉलेज, बिहार, पटना।
दिनांक: 07/01/2022

विषय: राज्य में संचालित निजी नर्सिंग संस्थानों में निर्धारित मानक के आलोक में उपलब्ध संसाधनों की समीक्षा के संबंध में।

महाशय,
उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के अन्तर्गत नर्सिंग शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा संस्थानों को अपना वेबसाइट तैयार करने, संस्थान में नामांकित/उत्तीर्ण वर्षवार प्रशिक्षणार्थियों, शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक कर्मी, स्कूल/संस्थान के संचालन ट्रस्ट/सोसाईटी का नाम, पूरा पता, दूरभाष संख्या, शैक्षणिक/छात्रावास भवन का फोटोग्राफ एवं विवरणी अपलोड करने का निदेश स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा विभिन्न आदेशों के माध्यम से दिया गया था।

2- विभिन्न संस्थानों द्वारा अपना वेबसाइट बना दिया गया है। किन्तु कई संस्थानों द्वारा अभी भी अपना वेबसाइट नहीं बनाया गया है और वांछित डाटा अपने वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं किया गया है। ऐसे संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है। साथ ही राज्य में संचालित सभी नर्सिंग संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार हेतु समय-समय पर निर्धारित मानक के अनुरूप संसाधनों की उपलब्धता की जांच/सत्यापन आवश्यक है। इस संबंध में एक जनहित याचिका संख्या-13720/2021 धीरेन्द्र कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर किया गया था।

3- वर्णितस्थिति में समावेश याचिका संख्या-13720/2021 में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक-03.08.2021 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में यादी से प्राप्त अभ्यावेदन (Representation) के आलोक में संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार एवं निर्धारित मानक के आलोक में इनके संचालन की आवश्यकता को देखते हुए राज्य के सभी निजी नर्सिंग संस्थानों से Google - form (जिसका लिंक है- https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmwNMer6cx6GH8hHSBbGnXCqYSudvTa-h6T_zQnp29LeEmA/viewform?usp=sf_link) में डाटा तैयार कर 5 दिनों के अन्दर (दिनांक-12.01.2022 तक) निश्चितरूपेण उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

सभी संस्थानों को google form का लिंक ई-मेल के माध्यम से भी भेजा जा रहा है।
उच्च प्राथमिकता अपेक्षित है।

विश्वासभाजन
(कौशल किशोर)
सरकार के अपर सचिव।

वर्णित स्थिति में आपको निदेश दिया जाता है कि विभागीय आदेश ज्ञापक-631(6), दिनांक-17.05.2019, 944(6), दिनांक-26.07.2019, पत्रांक-768(6), दिनांक-16.07.2021 एवं पत्रांक-769(6), दिनांक-16.07.2021 तथा निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना के पत्रांक-1844, दिनांक-03.09.2019, पत्रांक-3035, दिनांक-06.10.2021 एवं पत्रांक-3078, दिनांक-18.10.2021 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन दो दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से किया जाय। साथ ही स्पष्टीकरण भी समर्पित किया जाय कि विभागीय निदेश की अवहेलना के लिए क्यों नहीं नियमानुसार आपके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाय।

अनुलग्नक- यथोक्त।

विश्वासभाजन
(डॉ० नवीन चन्द्र प्रसाद)
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापक - 6/N-08-07/2019 1224(6) /पटना, दिनांक - 10/01/2021

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को आम सूचनार्थ विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित। -

(10/1/21)
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

आप को विश्वस्तरीय संस्थान बताने वाले खगड़िया के नर्सिंग कॉलेज के छात्र का दो-दो प्रमाण पत्र बन जाता है और जब सुधार के लिए परिषद भेजा जाता है, तो कहा जाता है टंकक भूल है। टंकक भूल शब्दों का होता है, पूरे के पूरे प्रमाण पत्र का नहीं। इससे साफ पता चलता है कि नर्सिंग कॉलेज से लेकर बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन परिषद सब के सब मिले हुए हैं। यहां परीक्षा केंद्र नर्सिंग कॉलेज के सुविधा अनुसार तय किए जाते हैं। हम अपने अगले अंक में पटना और दरभंगा के कई नर्सिंग संस्थानों की हकीकत से आपको रूबरू कराएंगे। अगर आपको सच्चाई के साथ रहना है तो, केवल सच के साथ बने रहे। क्योंकि भ्रष्टाचार से मुकाबला करना बकरे को कसाई से बचाना, दोनों एक जैसा है। ऊपर से कसाई ऐसा कि जिस की पहुंच दिल्ली से लेकर पटना तक मजबूत हो और पटना से दिल्ली तक हिस्सेदारी ईमानदारी के साथ बांटी जाती हो। ●

कम उम्र की शादी रोकें, जीवन की बर्बादी रोकें



21 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की की शादी बाल विवाह है और यह कानूनी अपराध है।

बैण्ड बाजा बराती, पंडित और सराती सब होंगे बाल विवाह कानून के दोषी

सब जायेंगे जेल में और लगेगा जुर्माना भी

आइये, हम सब मिलकर बिहार को बाल विवाह गुप्त बनायें

किसी भी प्रकार की जनसहरी अत्याचार संयोग के लिए अपने जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अनुभवकाल पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, स्थानीय मान्य, पुलिसवा/सरपंच/धर्मपंड, महिला/डेप्युटी, स्वयं सहायता समूह, आंगनवाड़ी केन्द्र अथवा टॉल फ्री नंबर 1821 पर संपर्क करें।

जनहित में जारी: **महिला एवं बाल विकास निगम, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार**

जिला प्रशासन, पटना

आखिर नीतीश कुमार को ब्राह्मणों से क्या दुश्मनी है?

● राजीव कुमार शुक्ला

क्यों सरकार को लगता है शादियां सिर्फ हिंदू धर्म में होती है? क्या इस्लाम में निकाह मौलवी नहीं करवाते हैं? क्या ईसाई में पादरी मेरेज नहीं करवाते हैं? अगर सरकार ऐसा सोचती है इस्लाम और ईसाई धर्म के प्रति सरकार सही नजरिया नहीं रखती है। हम यह बात इसलिए कर रहे हैं कि राजधानी पटना के आयकर चौराहे पर बिहार सरकार के महिला एवं बाल विकास निगम, समाज कल्याण विभाग द्वारा लगाए गए हार्डिंग बोर्ड से यह पता चल रहा है जिसमें कहा गया है कि कम उम्र की शादी रोकें जीवन की बर्बादी रोकें साथ ही कहा गया है कि बैण्ड, बाजा, बाराती, पंडित और सराती सब होंगे बाल विवाह कानून के दोषी। इसमें ऐसा क्यों नहीं कहा गया है कि पादरी/मौलवी आदि भी दोषी, आखिर यह सरकार का कैसा दोगलापन है सरकार मानसिक रूप से दिवालिया हो गई है या दिवालिया होने के कगार पर है।

ब्राह्मण पंडित जिसका नाम सुनते ही आदमी का सर झुक जाता है। देवता और भक्तों के बीच की सीढ़ी को ब्राह्मण कहते हैं। आज

छद्म धर्मनिरपेक्षता के चलते राजनीतिक दलों के निशाने पर है और हिंदू धर्मावलंबियों के धार्मिक रूप से कमजोर करने के लिए भक्तों से उसकी सीढ़ी को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। ब्राह्मण हिंदू धर्म की ऐसी करी है जो ब्राह्मंड से जजमान को जोड़ता है।

चाणक्य विकास मोर्चा के राज्य संयोजक श्री संजय पाठक कहते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार का रवैया ब्राह्मणों पंडितों के प्रति उपेक्षा पूर्ण रही है। शायद नीतीश कुमार अपनी गृहस्थी



सही से नहीं चल पाने के लिए शादी करवाने वाले पंडित को ही दोषी मानकर चल रहे हैं। और उनसे दुश्मनी का भाव लेकर चल रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा चाणक्य विकास मोर्चा इसके लिए पूरे राज्य में आंदोलन करेगी। श्री पाठक ने कहा कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं और लगातार राजनीतिक पतन के कारण उटपटांग हरकत कर रहे हैं। जिससे हिंदू धर्म के बीच एक अलग सा आक्रोश दिख रहा है। जिस तरह का हार्डिंग लगाया गया है और उसमें से पंडित को ही टारगेट किया गया है ताकि मौलवी और पादरियों के शुभचिंतकों का वोट हासिल कर सकें। इन्हीं अभद्र लक्षणों के वजह से हिंदू धर्म ने अपने शुभचिंतकों के साथ मिलकर इनके राजनीतिक सोच को दूल्ती दे दिया है। नीतीश कुमार की पार्टी 117 से 44 पर समेट दिया गया है। आगामी चुनाव में इसका परिणाम नीतीश कुमार को भुगतना होगा।

आज स्थिति यह है कि कोरोना महामारी में पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। व्यवसाई से लेकर प्राइवेट जॉब वाले का त्राहिमाम-त्राहिमाम कर रहे हैं। अगर आप धोबी, माली मेहतर, बनिया, नाई, बढई मल्लाह, केवट को व्यवसायिक दृष्टि से देख सकते हैं, तो पुरोहित

को भी व्यवसायिक दृष्टि से देख सकते हैं। आज नीतीश कुमार ब्राह्मण और सनातन को आर्थिक रूप से कमजोर करने की साजिश करते दिखते हैं। साथ ही उनके सरकार का रवैया यह है कि वह पंडितों को अपराधी बनाने पर तुली हुई है। कोरोना में सबसे पहले मंदिर को बंद करवाते हैं। मंदिर से बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के माध्यम से “जजिया कर” की वसूली करवाते हैं। गौशाला और मंदिर के जमीन पर अस्पताल और भवनों का निर्माण करते हैं। सरकार की मंशा साफ है कि किसी तरह ब्राह्मण/ पंडित को आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा सके। आज दरभंगा में वक्फ बोर्ड की सैकड़ों एकड़ जमीन अतिक्रमणकारियों के कब्जे में है लेकिन सदर अस्पताल का निर्माण गौशाला के जमीन पर हो रहा है। समस्तीपुर मेडिकल कॉलेज का निर्माण राम जानकी ट्रस्ट की जमीन पर हो रहा है। यह एक उदाहरण है ऐसे सैकड़ों मंदिर को तोड़कर नीतीश कुमार की सरकार ने ब्राह्मणों के माध्यम से सनातन को कमजोर करने का प्रयास किया है। ब्राह्मण/पंडित के बिना हिंदुओं की कल्पना करना बेमानी है। अगर आप धार्मिक अंधविश्वास पर चोट कर रहे हैं तो हिंदुओं का ब्राह्मण क्यों? इस्लाम का मौलवी और ईसाई का पादरी क्यों नहीं? यह सवाल तो हर हिंदू जनमानस पूछेगा आज बॉलीवुड में जितने भी फिल्म और विशेषकर



वेब सीरीज का निर्माण हो रहा है, आखिर हिंदू धर्म को ही टारगेट ब्राह्मणों के माध्यम से क्यों किया जा रहा है पंडितों को ही दुराचारी क्यों

दिखाया जा रहा है ?

भाजपा की केंद्र और राज्य की सरकारें केवल हिंदुओं के नाम पर वोट लेगी या हिंदुओं को गाली देने वाले लोगों के खिलाफ कोई कानून बनाएगी। इनकी मंशा क्या है यह सनातन धर्म की जनता बखूबी देख रही है। इसका परिणाम अगला लोकसभा और राज्य के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा।

जाने-माने तांत्रिक लक्ष्मण चौबे कहते हैं:-

विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम
विप्र प्रसादात् कमला वरोहम
विप्र प्रसादात् अजिता जितोहम
विप्र प्रसादात् मम् राम नामम्॥

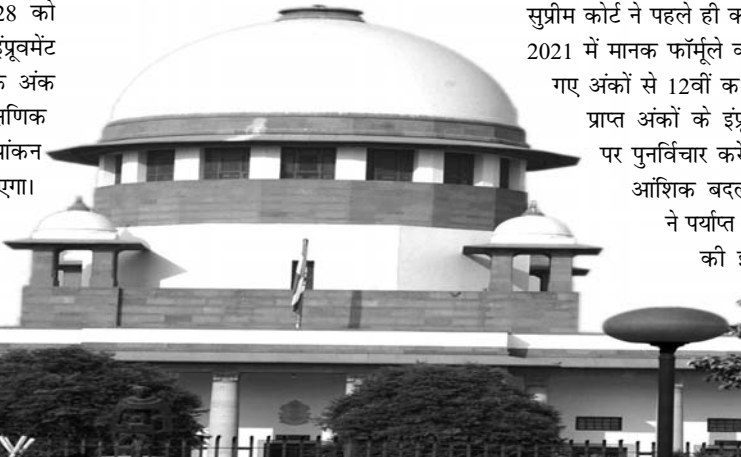
ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैंने धरती को धारण कर रखा है अन्यथा इतना भार कोई अन्य पुरुष कैसे उठा सकता है, इन्ही के आशीर्वाद से नारायण को कर मैंने लक्ष्मी को वरदान में प्राप्त किया है, इन्ही के आशीर्वाद से मैं हर युद्ध भी जीत गया और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मेरा नाम 'राम' अमर हुआ है, अतः ब्राह्मण सर्व पूजनीय है और ब्राह्मणों का अपमान ही कलियुग में पाप की वृद्धि का मुख्य कारण है।

किसी में कमी निकालने की अपेक्षा किसी में से कमी निकालना ही ब्राह्मण का धर्म है। ●

सुप्रीम कोर्ट का सीबीएसई की अंक सुधार नीति को लेकर अहम फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने छात्रहित में अहम फैसला देते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की अंक सुधार नीति के प्रावधान-28 को रद्द कर दिया, क्योंकि सीबीएसई मार्क्स इंप्रूवमेंट पॉलिसी के प्रावधान में कहा गया था कि अंक सुधार परीक्षा में प्राप्त अंकों को पिछले शैक्षणिक वर्ष के लिए कक्षा 12वीं के छात्रों के मूल्यांकन के अंतिम अंक के रूप में माना जाएगा। जस्टिस एम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ कर इस मामले की सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा कि छात्र अपने मूल अंकों को बनाए रखने की मांग कर

रहे हैं, क्योंकि सुधार परीक्षा के अंकों को बनाए रखने से उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने में समस्या हो सकती है। पीठ ने आगे कहा कि छात्रों के पास



परीक्षाओं के दौरान प्राप्त “दो अंकों में से बेहतर” के बीच चयन करने का विकल्प होना चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि वह दिसंबर, 2021 में मानक फॉर्मूले के अनुसार हासिल किए गए अंकों से 12वीं कक्षा की सुधार परीक्षा में प्राप्त अंकों के इंप्रूवमेंट की अपनी नीति पर पुनर्विचार करे। लेकिन बोर्ड ने सिर्फ आंशिक बदलाव किए थे, जो कोर्ट ने पर्याप्त नहीं माने और सीबीएसई की इंप्रूवमेंट मार्क्स पॉलिसी खारिज कर दी। साथ ही छात्रों को चॉइस विकल्प देने के लिए निर्देशित किया। ●



छोटी और बड़ी महारानी चला रही

पटना सिविल सर्जन कार्यालय

पटना का नया पिकनिक स्पॉट सिविल सर्जन कार्यालय

● शशि रंजन सिंह

पटना में अगर आपको चिकित्सा व्यवसाय चलाना है तो हो जाइए चौकन्ने क्योंकि यहां मंत्री और सचिव की नहीं चलती है नहीं यहां चलता है बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग का कोई नियम। यहां तो भारत का राजपत्र (गजट) को ही रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। यहां की सिविल सर्जन बड़ी महारानी ,उनके पति महाराजा और उनके प्रिय पात्र डॉक्टर अनुपमा छोटी महारानी है। यहां कानून भी डॉक्टर अनुपमा बनाती है और कानून का पालन सिविल सर्जन के पति करवाते हैं। यहां के सिविल सर्जन के पति सेवानिवृत्त लेकिन ACMO लिखकर लाल रंग की गाड़ी से सरकारी ड्राइवर का उपभोग करते प्रतिदिन डॉक्टर अनुपमा द्वारा लाए गए कानून की समीक्षा करने कार्यालय आते हैं, और कर्मचारियों को निलंबित करने की धमकी देते हुए गैर कानूनी कार्य करवाते हैं और एक बात यहां एक जितेंद्र

कुमार जो कि सहायक है लेकिन अपने आप को विधि विशेषज्ञ समझता है और केवल सच को कानूनी नोटिस भी सिविल सर्जन और उसके पति के बदले जारी करता है। सिविल सर्जन कार्यालय में सचिव और मंत्री के आदेश को ना मानने वाले को इनाम दिया जाता है। सिविल सर्जन अपने कार्यालय में दूसरे स्वास्थ्य संस्थानों के कर्मचारी को बैठाकर कार्यालय में दलाली का कार्य करवाती है।

अगर आपका चयन सरकारी सेवाओं के लिए हुआ है और आपको मेडिकल फिटनेस सिविल सर्जन से लेना है तो किसी भी सरकारी नियम का हवाला सिविल सर्जन कार्यालय पटना में नहीं दे, नहीं तो हो सकता है आप फिट होते हुए भी अनफिट हो जाएंगे अगर आपको थोड़ा सा भी चु-चक्रम किए तो कम से कम 1 महीना सिविल सर्जन कार्यालय का दौड़ लगाते रह जाएंगे क्योंकि यहां बिहार सरकार का कोई कानून लागू नहीं है यहां लागू है डॉक्टर अनुपमा के द्वारा लाया

गया कानून।

अगर आपको पटना में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत अपने क्लीनिक का निबंधन करवाना है, तो यहां यह जान लीजिए यहां भारत का राजपत्र संख्या 254 दिनांक 4 जून 2012 और भारत का राजपत्र संख्या 11 दिनांक 9 जनवरी 2014 लागू नहीं है। यहां लागू है छोटी महारानी का कानून जिनका चेहरा उनको अच्छा लगेगा उनको मिलेगा निबंधन नहीं तो एक्ट को लेकर घूमते रह जाइएगा। पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट को डील करने के लिए कार्यालय सहायक हैं सत्यदेव कुमार व जनता का फोन नहीं उठाते हैं नहीं अपने टेबल पर मिलते हैं वह मिलते हैं गुप्त जगह पर जहां पर चढ़ावा चढ़ने के बाद उनका फोन उठाते हैं और आपका निबंधन जारी होता है। छोटी महारानी के कृपा से यह महाशय विधायक अस्पताल से सिविल सर्जन कार्यालय में पदस्थापित हैं और अपने सहकर्मियों को कहते हैं कि हम लाल बादशाह हैं, सिविल सर्जन कार्यालय



सत्यदेव कुमार

क्लीनिक खुलेआम 5 गुने दर पर लिंग परीक्षण करते हैं और बेटियां को ख में ही मार दी जाती है। पटना की सिविल सर्जन डॉ विभा कुमारी और सुपर सिविल सर्जन दोनों महिला बावजूद यहां कन्या भ्रूण हत्या कई अस्पतालों में खुलेआम हो रहा है यहां नारी शक्ति दुर्गा का रूप नहीं होकर ड्रैकुला के रूप में है जो अपने निजी हित के लिए लोगों का खून पी रही है।

अगर आप अपने चहेते का जन्मदिन मनाने की योजना बना रहे हैं, तो हम आपको नए सरकारी पिकनिक स्पॉट का नाम बताने जा रहे हैं। पिकनिक या यूं कहें जन्मदिन मनाने का उत्तम व्यवस्था है, पटना सिविल सर्जन कार्यालय यहां आपको केक से लेकर बैलून की सजावट फ्री में मिल जाएगी और वह भी सरकारी खर्चे पर। ●

बेटी

माँ मैं क्यों जाती मारी,
 गर्भ से मैं हूँ पुकारी,
 बेटी हूँ तुम्हारी,
 मेरी करो रखवाली।

हो मेरी भी,
 सुमन सा सुन्दर नाबाद पारी,
 प्रण करो! अब ना जाऊँगी मारी,
 तब होगी मेरी अपनी दुनियादारी,
 बनुंगी भारत माता की राजदुलारी।

यो ही गर्भ में गयी मारी तो,
 कौन बनेगी माँ, बहु, बेटी, कन्या कुमारी,
 कोई कहता तु है अबला नारी,
 माँ मै हूँ तेरे दुःख मे यारी।

सम्पति मे भी न करती हकमारी,
 मैं करती अच्छी रखवाली,
 करो ये समझदारी,
 गर्भ में मैं ना जाऊँ मारी।।

.....

बेटी है कमल सा सुन्दर फुल,
 खिलायेगी सबके जीवन में गुल,
 इस बात को मत जाना भुल,
 बेटी ही हैं सृष्टि की मूल।

बेटी है तो कल है,
 बेटी है तो बल है,
 बेटी है तो खुशी हरपल हैं।

देश है जान से प्यारी,
 बेटी भी माँ बाप की प्यारी।

डॉ सुमन कुमार सिंह (कन्हैया)
 चिकित्सा पदाधिकारी

हम ही चलाते हैं।

भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का पूरे जिले में पालन नहीं किया जाता पूरे जिले के चिकित्सा व्यवसाई से सिर्फ चढ़ावा लेकर कानून को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट में भारत का राजपत्र संख्या 254 दिनांक 4 जून 2012 के अनुसार एक संस्थान /डॉक्टर का प्रत्येक जिले में दो या दो से ज्यादा क्लीनिक नहीं हो सकता है लेकिन इसका पालन यहां नहीं हो रहा है प्रत्येक क्लीनिक केंद्र के द्वारा परामर्श घंटे स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किए जाएंगे इसके लिए क्लीनिक केंद्र पर लॉग बुक रखे जाएंगे और उस लॉग बुक की एक प्रति प्रत्येक महीने के 5 तारीख तक सिविल सर्जन कार्यालय में जमा हो जाना चाहिए जो नहीं हो रहा है।

भारत का राजपत्र संख्या 11 दिनांक 9 जनवरी 2014 इस अधिनियम का कार्यान्वयन, कार्यान्वयन निकायों के माध्यम से किया जाता है। केंद्रीय पर्यवेक्ष्य बोर्ड, राज्य पर्यवेक्ष्य बोर्ड, राज्य प्राधिकरण, राज्य सलाहकार समिति, जिला और उप जिला स्तर पर समुचित प्राधिकारी की व्यवस्था लेकिन पटना सहित पूरे राज्य में धवस्त है। प्रत्येक अल्ट्रासाउंड केंद्र पर गर्भधारण पूर्व



प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम की प्रति उपलब्ध होनी चाहिए। लेकिन यह किसी भी केंद्र पर आपको देखने को नहीं मिलेगा साथ ही निबंधन प्रमाण पत्र क्लीनिक के दीवार पर प्रदर्शित करना है लेकिन आपको विरले ही क्लीनिक आपको देखने को मिलेगा। प्रत्येक क्लिनिक को प्रशिक्षण करने वाले महिला/पुरुष का नाम, पता, पति/ पिता का नाम के साथ प्रशिक्षण की तारीख प्रक्रिया या प्रशिक्षण के लिए पिछली बार का रिपोर्ट प्रत्येक महीने की 5 तारीख से पहले नियमित रूप से सक्षम प्राधिकार को एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए। सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर वाली एक मासिक रिपोर्ट की एक प्रति जिसमें प्राप्त की अभीस्वीकृति दी गई हो 2 वर्ष तक सुरक्षित रखी जानी चाहिए।

क्लीनिक पर FORM F डॉक्टरों की रेफरल की पर्चियां कॉपी, सहमति के फॉर्म सोनोग्राफी प्लेट या स्लाईड सभी रिकॉर्ड 2 वर्ष तक सुरक्षित रखे जाने चाहिए सभी क्लीनिक को एक लॉग बुक रखना अनिवार्य है। लॉग बुक और उसका मूल्यांकन लॉग बुक किए गए प्रशिक्षण क्रियाकलाप क्षमताओं को रिकॉर्ड करती है अंतरिम मूल्यांकन के द्वारा लॉग बुक के रखरखाव और नियमित निरीक्षण डॉक्टर की उपस्थिति में दस्तावेजों के समुचित भागों पर हस्ताक्षर आवश्यक है। सभी सहभागी इस बात का महत्व समझेंगे और उनके मानकों के अनुरूप कार्य करेंगे। पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट में जितने भी नियम हैं उनके अधिकतर क्लीनिक के द्वारा नहीं किया जाता है सभी क्लीनिक में प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण गैरकानूनी है। लेकिन कुकुरमुत्ता के तहत गलत प्रमाण पत्र खुले हुए अल्ट्रासाउंड के

जातिगत जनगणना से किसका भला जाति का या जाति आधारित राजनीतिक पार्टियों का



● शशि रंजन सिंह/राजीव कुमार शुक्ला

भारत सरकार के 3 जुलाई 2015 के लिए के लिए गए निर्णय के अनुसार बिहार सरकार के अनुमंडल अधिकारी द्वारा जारी राशन कार्ड में सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के आधार पर जन वितरण प्रणाली की दुकानों में राशन का वितरण हो रहा है तो किस आधार पर आज बिहार की क्षेत्रीय पार्टी राजद, जनता दल यूनाइटेड, पार्टियों जातीय जनगणना की बात करती है, इन पार्टियों को गरीबी से नहीं जाती आधारित वोट से मतलब है। जब सरकारें अंतर्जातीय शादियों को बढ़ावा देने के लिए शादी करने वाले को ₹100000 पुरस्कार के रूप में देती है और दूसरी तरफ जाति आधारित राजनीति करने के उद्देश्य से जातीय जनगणना पर आधारित गृहस्त राशन कार्ड जारी करना कहीं ना कहीं सरकार किए दोगली नीति का परिचायक है। सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 (एसईसीसी) 2011 की भारत की जनगणना के लिए आयोजित की गई थी। मनमोहन सिंह सरकार ने

2010 में संसद के दोनों सदनों में चर्चा के बाद सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना 2011 को मंजूरी दी। भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में और पहला निष्कर्ष 3 जुलाई 2015 को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा प्रकट किया गया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपने सभी कार्यक्रमों जैसे मनरेगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशलता योजना में सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना डेटा का उपयोग करने का निर्णय लिया है। 2011 भारत की 1931 की जनगणना के बाद पहली जाति-आधारित जनगणना थी। दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में जाति-आधारित जनगणना को लेकर पार्टी के भीतर मतभेद थे। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने जाति-आधारित जनगणना के विचार का समर्थन किया, जबकि तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम जनगणना करते समय जाति की गिनती में व्यावहारिक कठिनाइयों का हवाला देते हुए इसके खिलाफ थे। डेटा का उपयोग लाभार्थियों की पहचान करने और श्राड (प्रधान मंत्री जन धन योजना-आधार-मोबाइल शासन) त्रिमूर्ति पर निर्माण करने की अपनी योजना के हिस्से के रूप में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना का विस्तार करने के लिए भी किया जाएगा। 2011 ने भारत में मैनुअल स्कैनिंग और ट्रांसजेंडर काउंट जैसे अन्य पहलुओं को भी गिना। 2011 को 1948 की जनगणना अधिनियम, के तहत आयोजित नहीं किया गया था, जिसने बदले में नागरिकों के लिए सूचना प्रकटीकरण को

स्वैच्छिक बना दिया, न कि अनिवार्य प्रकटीकरण। सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना 2011 भारत में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले परिवारों की पहचान करने के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित चौथा अभ्यास था, जिसे 1992, 1997 और 2002 में तीन जनगणनाओं के बाद विभिन्न अधिकार प्राप्त होंगे। पिछली बीपीएल जनगणना 2002 में भारत में आयोजित की गई थी और अपनाई गई प्रक्रिया प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए 13 संकेतकों पर जानकारी एकत्र करने और इनमें से प्रत्येक के लिए एक चिह्न निर्दिष्ट करने के लिए थी। भारत में पहली जाति जनगणना 1881 में आयोजित की गई थी। जनवरी 2017 में, केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक योजनाओं के लिए लाभार्थियों की पहचान और धन के हस्तांतरण के लिए मुख्य साधन के रूप में गरीबी रेखा के बजाय सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना का उपयोग करने की सिफारिशों को स्वीकार किया। 2011 में तीन जनगणना घटक हैं जो तीन अलग-अलग प्राधिकरणों द्वारा संचालित किए गए थे, लेकिन भारत सरकार में ग्रामीण विकास विभाग के समग्र समन्वय के तहत ग्रामीण क्षेत्र में जनगणना ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयोजित की गई है। शहरी क्षेत्रों में जनगणना आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में है। जाति जनगणना गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है, भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त। डेटा 2011 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह द्वारा विश्लेषण के लिए भेजा गया है। यह विशेषज्ञ समूह सार्वजनिक करने से पहले सामाजिक न्याय



और आदिवासी विकास मंत्रालयों द्वारा स्थापित किया गया है। जाति जनगणना जुलाई 2014 में प्रकाशित हुई भारत के महापंजीयक द्वारा आयोजित सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना 2011 जाति और कबीले के नामों में जाति, उप-जाति, पर्यायवाची, विभिन्न उपनाम, गोत्र की 46,73,034 श्रेणियों के साथ सामने आया है। ये जाति संबंधी आंकड़े सभी राज्यों को नवंबर 2014 में जाति गणना को समेकित करने के लिए क्लब करने के लिए भेजे गए थे। 28 जुलाई 2015 को, भारत सरकार ने कहा कि जाति विवरण और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 8,19,58,314 त्रुटियां पाई गईं, जिनमें से 6,73,81,119 त्रुटियों को ठीक किया गया है। हालांकि, 1,45,77,195 त्रुटियों को अभी भी ठीक किया जाना है। क्रमांक राज्य त्रुटियाँ (1) महाराष्ट्र 69.1 लाख (2) मध्य प्रदेश 13.9 लाख (3) पश्चिम बंगाल 11.6 लाख (4) राजस्थान 7.2 लाख (5) उत्तर प्रदेश 5.4 लाख (6) कर्नाटक 2.9 लाख (7) बिहार 1.75 लाख (8) तमिलनाडु 1.4 लाख 2011 की जनगणना में 11.65 लाख ग्रामीण बेघर लोगों को दर्ज किया गया, जबकि एसईसीसी में उनकी संख्या केवल 6.1 लाख थी। सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 के अंतिम ग्रामीण डेटा में अनुसूचित जातियों को 18.46% (या 15.88 करोड़), अनुसूचित जनजातियों को 10.97% (9.27 करोड़), अन्य को 68.52%, और 2.04% (या 36.57 लाख) को "कोई जाति और जनजाति" परिवारों के रूप में नहीं दिखाया गया है।

भारत के राजनीतिक पार्टियों का चाल-चेहरा और चरित्र एक जैसा है। कांग्रेस सत्ता में थी तो उनके गृह मंत्री पी चिदंबरम जाति आधारित जनगणना के पक्ष में नहीं थे, उस समय की भाजपा नेत्री सुषमा स्वराज जाति आधारित जनगणना के पक्ष जोरदार आवाज लगा रहे थी। आज गृह मंत्री अमित शाह त्रुटियों का हवाला देकर जातीय जनगणना से इंकार कर चुके। सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 में आयोजित की गई और पहला निष्कर्ष 3 जुलाई 2015 को घोषित किया गया तो फिर आज भाजपा सरकार से इससे पीछे क्यों भाग रही है।

आज बिहार में राजद, जनता दल यूनाइटेड, हम सहित जिन पार्टियों कि अपनी राजनीतिक जमीन तक नहीं है, जातीय जनगणना की बात करती है, लेकिन जाति, सामाजिक, आर्थिक जनगणना जब हो चुकी है तो फिर क्यों अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के सभी जातियों का गरीब और गरीब होते जा रहे हैं अमीर और अमीर होते जा रहे हैं।

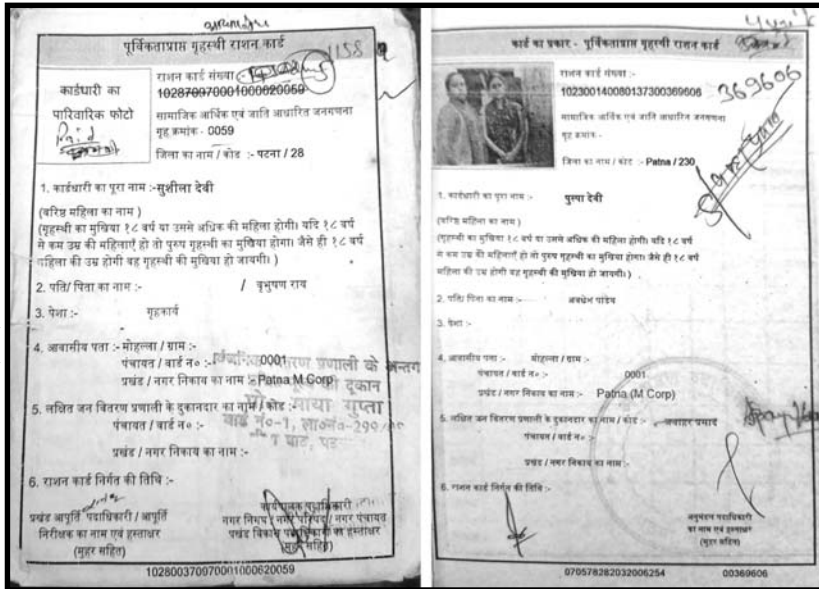
आज सत्ता पक्ष हो या विपक्ष चाहे क्षेत्रीय पार्टियां हो या राष्ट्रीय पार्टी जातीय जनगणना कराने के पीछे मात्र उनका मकसद जाति आधारित वोट बैंक में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करना। जब सरकार ने 3 जुलाई 2015 को ही अपने कार्यक्रमों मनरेगा, राष्ट्रीय खाद सुरक्षा

मतलब होता है इसलिए राष्ट्रीय पार्टियां जाति आधारित राजनीति का विस्तारीकरण नहीं करना चाहती 90 के दशक के बाद बिहार में जाति आधारित राजनीति का बढ़ गया है। आज जो सभी राजनीतिक पार्टियां जाति आधारित जनगणना के कारण अपने को जातियों का जाति के प्रतिशत के हिसाब से अपना सीट बड़ी पार्टियों से मोलभाव कर सकें। मुकेश सहनी की पार्टी जो कि निषाद की राजनीति करती है पिछले चुनाव में उसके चार विधायक मिश्री लाल यादव (यादव), स्वर्णा सिंह (राजपूत), राजू सिंह (राजपूत), मुसाफिर पासवान (दुसाध)। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के चार विधायक जीतन राम मांझी, उनकी समधीनी ज्योति कुमारी, उनके

रिश्तेदार प्रफुल्ल मांझी, अनिल कुमार भूमिहार जाति से हैं। अब आप गन्ना कर लीजिए कि जाति आधारित पार्टियों में उनकी जातियों क्या-क्या राजनीतिक भविष्य है।

आज स्थिति यह है कि सभी क्षेत्रीय पार्टियां सिर्फ सीट के मोल भाव के कारण जातीय जनगणना पर जोर दे रहे हैं। उनका एकमात्र मकसद अपना और अपने परिवार के लिए राजनीतिक विरासत संजोना है। अगर जातीय जनगणना 2015 में घोषित

किया गया तो भारत के राजपत्र में क्यों नहीं प्रकाशित करवाया गया? सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के आधार पर जनगणना का मकसद सिर्फ जातियों की गोलबंदी ही बनकर क्यों रह जाती है। जाती की जनगणना के साथ आर्थिक और सामाजिक जनगणना भी हुई है तो इसका आधार योजनाओं के लिए क्यों नहीं बनाया जा रहा है? आज जाति की राजनीति का एकमात्र उद्देश्य अपने सगे - संबंधियों राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करना है। आज पूरे देश में जाति आधारित राजनीति करने वाले खानदान अपने पूरे परिवार का राजनीतिक भविष्य पुख्ता कर चुके हैं। भारत के जाति मकड़जाल से निकलने के लिए कड़ाह रहा है। आज नहीं तो कल यह जाति के मकड़जाल से निकलेगा यह हमारी आशा है।



अधिनियम और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना का डेटा का उपयोग करने का निर्णय लिया था तो फिर क्यों सरकार द्वारा लाई गई योजना आयुष्मान भारत में सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना का डेटा का उपयोग नहीं किया गया। किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार को जनता को जातीय गणित में उलझा कर रखना चाहती है और उसका यही एक मात्र उद्देश्य है। आज बिहार के पिछड़ेपन का मूल कारण बिहार में लगभग 33 साल से क्षेत्रीय पार्टियां राजद और जनता दल यूनाइटेड की सरकार है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टियों को जाति आधारित वोट से मतलब नहीं होता है लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों का पूरा राजनीतिक भविष्य जाति आधारित होती रही है। राष्ट्रीय पार्टियों का दूसरे राज्यों के वोट बैंक से भी



राँची पुलिस को मिली बड़ी सफलता दिनेश गोप को समान मुहैया कराने आठ लोग गिरफ्तार

● ओम प्रकाश

राँ

ची पुलिस को पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है।

पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप को दैनिक सामान उपलब्ध कराने वाले 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने भारी मात्रा में दैनिक सामान बरामद की है। गिरफ्तार हुए लोगों में निवेश कुमार, शुभम पोद्दार, ध्रुव कुमार सिंह, अमीर चन्द, आर्या कुमार सिंह, उज्ज्वल कुमार, प्रवीण कुमार और सुभाष पोद्दार है। पुलिस ने इनके पास से पीएलएफआई का 70 पीस पर्चा, नक्सलियों के लिए जंगल में लगाए जाने वाले पोर्टेबल टेंट, नक्सलियों के लिए जंगल में उपयोग में लाए जाने वाले 15 पीस स्लीपिंग बैग, एक स्कूटी, एक जाइलो कार, छह आधार कार्ड एक बीएमडब्ल्यू कार, एक थार जीप, कुल सत्तर लाख तीन हजार दो

सौ दस रुपये, एक

7.05 बोर का खुला

हुआ पिस्टल, 9 एम

एम के 13 कारतुस,

7.65 एम एम का 18

कारतुस तथा प्वाइंट

380 एम एम का 1

कारतुस बरामद किए हैं।

झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा ने नक्सलियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। झारखण्ड राज्य में उग्रवादी संगठनों एवं संगठित अपराधिक गिरोहों के विरुद्ध ठोस कार्यवाई करने एवं अपराधिक गिरोह को सहयोग



वाले सहायियों के विरुद्ध ठोस कार्यवाई करने के आदेश दिया था। इस संबंध में इन संगठनों के विरुद्ध राँची पुलिस भी कई बार कार्यवाई की गई है। इसी क्रम में

एवं विस्फोटक सामग्री जैसे हथियार, गोला बारूद, जंगल में रहने योग्य वस्तुओं, मोबाईल फोन, सीम कार्ड, पैसा इत्यादि की सहायता करने

राँची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि निवेश कुमार, शुभम पोद्दार, ध्रुव सिंह एवं अमीर चन्द नामक व्यक्ति के द्वारा

पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप को

हथियार, गोली, सीम कार्ड एवं

अन्य जरूरत के सामानों को

सप्लाई किया जाता है। यही

नहीं इसमें लेवी से वसूले

गये पैसों का उपयोग

पीएलएफआई संगठन को

चलाने के लिए किया जाता

है। इस सूचना के आधार

पर राँची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने

सीटीएसपी सौरव को टीम गठित कर जांच करने

का आदेश दिया था। सिटी एसपी सौरभ के



निर्देशन में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया। एसआईटी टीम के द्वारा 6 जनवरी को धुर्वा डैम के पास छापामारी की गई जहाँ से आर्या कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से पीएलएफआई को सफ़लाई किये जा रहे जियो कम्पनी का 5 सीम कार्ड बरामद किया गया। वही घटनास्थल से तीन लोग जिनमें 1, निवेश कुमार 2, शुभम पोद्दार एवं 3. ध्रुव सिंह भागने में सफल

रहे। आर्या कुमार सिंह के बयान के आधार पर खुंटी में जियो कम्पनी में काम करने वाले उज्ज्वल कुमार को गिरफ्तार किया गया एवं अमीर चन्द के बयान के आधार पर निवेश के भाडे के मकान जो कि ग्राम-होटवासी थाना नगडी जिला राँची में निश्चित है, वहां से नगद तीन लाख पच्चास हजार रूपये, पीएलएफआई का पर्चा एवं नक्सलियों के लिए जंगल में उपयोग में लाया जाने वाला

पोर्टेबल टेन्ट, स्लीपिंग बैग एव अन्य सामानो को बरामद किया गया। इस कांड में फरार निवेश कुमार, शुभम पोद्दार और ध्रुव सिंह जिस गाडी से भागे थे उन गाडियो को जगन्नाथपुर थाना के पटेल नगर तथा खुंटी के करी रोड से बरामद किया गया जिसमें बीएमडब्ल्यू कार का रजिस्ट्रेशन यूपी का है और एक मॉडिफाइड थार जीप है।

आठ उग्रवादी चढ़े पुलिस के हथ्थे

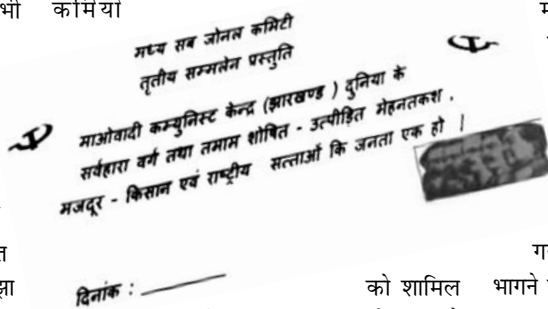
● ओम प्रकाश

राँची पुलिस ने आठ उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादियों के नाम राहुल गझु उर्फ खलील जी, टिबु गंजु उर्फ जितेंद्र गंजु, अर्जुन कुमार, शौफ अलीअहमद, सजीबुल अंसारी, अनिशा अंसारी और छोटू पहान है। पुलिस ने इन उग्रवादियों के पास से एक इंसोस राइफल, एक देसी राइफल, 14 जिंदा गोली, 32 पीस नक्सली पर्चा समेत मोबाइल और एक बाइक जब्त की है। राँची के एसएसपी सुरेंद्र झा ने बताया कि और भी उग्रवादियों के नाम सामने आए हैं जिसकी तलाश राँची पुलिस कर रही है। उन्होंने ने आगे बताया कि शहर में किसी भी हाल में उग्रवादियों को लेवी व रंगदारी नहीं दिया जाएगा। इसके लिए पुलिस अपने स्तर पर काम कर रही है और उग्रवादियों पर शिकंजा कसने की तैयारी भी कर रही है।

आपको बता दें राँची के एसएसपी को गुप्त सूचना मिली की बड़ी संख्या में उग्रवादी लेवी वसूलने का काम कर रहे हैं। गुप्त सूचना के आधार पर एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने ग्रामीण एसपी नौशाद आलम के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया। जिसमें पुलिस उपाधीक्षक खलारी, अनिमेष नैथानी, थाना प्रभारी



मांडर, थाना प्रभारी ठाकुरगाँव, थाना प्रभारी चान्हो सहित अन्य कई पुलिस कर्मियों



को शामिल किया गया। छापामारी दल के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए बुद्धमू थाना अतर्गत ग्राम सिरम के पश्चिम बासवाडी और झाड़ीनुमा

खेत (जंगल) में घेराबंदी करते हुये छापामारी की गयी, जहाँ बुद्धमू थाना क्षेत्र के ईट भट्टा मालिको एव ठेकेदारों से रंगदारी व लेवी वसूलने एवं लूटपाट तथा विध्वंसकारी कार्य करने हेतु एकत्रित प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी के एरिया कमांडर राहुल गझु उर्फ खलील जी सहित तीन अन्य को अवैध आग्नेयास्त्र, जिन्दा गोली एवं नक्सली पर्चा के साथ गिरफ्तार किया गया। जबकि तीन नक्सली वहाँ वहाँ से भागने में सफल हो गये। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पुछताछ के क्रम में एवं स्वीकारोक्ति बयान में बताया गया कि ये सभी प्रतिबंधित संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुती कमीटी (टीएसपीसी) के सदस्य है। तथा बुद्धमू थाना क्षेत्र के ईट भट्टा सचालको एवं ठेकेदारों से लेवी की रकम वसूलने एवं नहीं देने पर लूटपाट एवं तोड़फोड़ करने की योजना से ग्राम सिरम के जंगल किनारे एकत्रित हुये थे। इस संगठन के सदस्यों का असली मकसद आग्नेयास्त्र के बल पर लोगों को धमका दे कर लेवी की रकम वसूलना है। ये लोग बुद्धमू, सलारी, पिपरवार, मांडर, चान्हो, ठाकुरगाँव, पिठोरिया एवं बालुमाथ आदि थाना क्षेत्रों के भट्टा संचालको तथा सरकारी योजनाओं से चल रहे निर्माण कार्य के ठेकेदारों से लेवी वसूलने का कार्य करते हैं।



बजरंगी गैंग के दो अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

● ओम प्रकाश

22

सितम्बर 2021 को बीजेपी नेता जीतराम मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राजधानी राँची के ओरमांझी थाना क्षेत्र में 22 सितम्बर 2021 को बीजेपी नेता जीतराम मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में शामिल कुख्यात बजरंगी गिरोह के दो अपराधियों को झारखण्ड पुलिस और यूपी की एसटीएफ टीम ने वाराणसी से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में जौनपुर के काजीहद का रहने वाला अजीत सिंह उर्फ लल्लन और जौनपुर के खनुसापुर का रहने वाला राजीव कुमार सिंह शामिल है। दोनों को कैंट थाना क्षेत्र के मिंट हाउस तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से हत्या में प्रयुक्त डस्टर कार व दो मोबाइल फोन बरामद हुआ है। जानकारी के लिए बता दें भाजपा नेता हत्याकांड मामले में नीरज सिंह हत्याकांड में जेल में बंद शूटर अमन सिंह ने हत्या की सुपारी ली थी। अमन ने जेल में ही मनोज मुंडा से भाजपा नेता की हत्या की सुपारी पांच लाख रुपये में ली



थी। अमन ने भाजपा नेता जीतराम की हत्या आजमगढ़ के देवगांव निवासी अलीशेर उर्फ बाबूसाहब उर्फ बूढ़ा और गाजीपुर के भुजाडी निवासी हेमंत यादव उर्फ डब्लू से कराई थी। बीते 25 अक्टूबर 2021 को एसटीएफ ने मुठभेड़ में अलीशेर और उसके साथी कामरान को मार गिराया था। अजीत और राजीव ने अलीशेर को झारखण्ड पहुंचने में मदद की थी। 2017 में अमन सिंह के साथ मनोज मुंडा जेल में बंद था। जेल में उनके साथ पीएलएफआई नक्सली डेविड उर्फ बलराम साहू भी था। उसने ही मनोज की मुलाकात

अमन से कराई। जीतराम की गवाही के कारण मनोज को सात साल की सजा हुई थी। मनोज इसका बदला लेना चाहता था। जीतराम की हत्या की सुपारी लेने के बाद अमन ने राजीव और अजीत के जरिए फरारी काट रहे एक लाख के इनामी अलीशेर से बात की। राजीव और अजीत ने डस्टर कार से अलीशेर और हेमंत को डेहरी ऑन सोन तक छोड़ा था। इसी दौरान 22 सितंबर 2021 को ओरमांझी थाना क्षेत्र स्थित आर्यन ढाबा में जीतराम मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ●

चोरी के वाहनों के साथ आठ गिरफ्तार

● ओम प्रकाश

रां

ची के रातू पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का खुलासा करते हुए चोरी किए गए वाहनों के साथ 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में जियाउल अंसारी, यूनस अंसारी उर्फ जगड़ा, अली मुर्तुजा अंसारी उर्फ मोटे शमशेर अंसारी चारों निवासी रातू रांची के। मोहम्मद सरफराज उर्फ कैदी निवासी नगड़ी, अनिल उरांव निवासी बेड़ो, मुंसफ और शाहिद अंसारी निवासी मांडर रांची को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से एक पैशन प्रो मोटरसाइकिल, एक स्प्लेंडर प्रो

बजाज डिस्कवर मोटरसाइकिल लाल एवं ब्लू रंग का बिना नंबर प्लेट का जिसका इंजन एवं चेचिस नंबर घिस कर मिटाए गए हालत में बरामद किया है। आपको बता दें 21 दिसंबर मंगलवार को वरीय पुलिस अधीक्षक रांची को गुप्त सूचना मिली कि रांची के रातू थाना क्षेत्र से चोरी हुई मोटरसाइकिल को जियाउल अंसारी और यूनस उर्फ जगड़ा एवं उसके अन्य सहयोगियों के द्वारा चोरी कर लिया गया है।



के निर्देशन में थाना प्रभारी रातू आभास कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जियाउल अंसारी एवं यूनस अंसारी उर्फ जगड़ा को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जिसके बाद दोनों ने मामले में अपनी सलिपता को स्वीकार करते हुए अपने अन्य सहयोगियों के नाम बताए। जिसके बाद छापामारी दल द्वारा उनके अन्य साथियों जिसमें अली मुर्तुजा अंसारी उर्फ मोटे, शमशेर अंसारी, सरफराज उर्फ कैदी, अनिल उरांव मुंसफ अंसारी एवं शाहिद अंसारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ●



मोटरसाइकिल, एक डिस्कवर मोटरसाइकिल, एक सीबीजेड एक्सट्रीम मोटरसाइकिल खुली हालत में और दो

सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक रांची सुरेंद्र कुमार झा के द्वारा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नौशाद आलम रांची



सुधा डेयरी के इंजीनियर हुए लापता

● ओम प्रकाश

रां ची के धुर्वा थाना क्षेत्र के एचईसी परिसर स्थित सुधा डेयरी के इंजीनियर लापता हो गए हैं। लापता इंजीनियर का नाम सुजीत कुमार है और वह हिनू में रह रहे थे। लापता इंजीनियर सुजीत कुमार बिहार के नवादा जिले के रहने वाले हैं। 22 दिसंबर को सुजीत कुमार बाइक से सुधा डेयरी में काम करने के लिए गए थे लेकिन वापस घर नहीं लौट सके। घर नहीं लौटने पर परिवार वालों ने छानबीन किया तो इंजीनियर सुजीत कुमार नहीं मिले। परिवार वालों ने बताया कि कुछ माह पहले सुधा डेयरी के मैनेजर से उनका बकझक हुआ था। उसके बाद से वह

काफी परेशान चल रहे थे। परिवार वालों ने आशंका जताई है कि सुजीत कुमार की हत्या कर दी गई है। इस घटना की सूचना धुर्वा थाना प्रभारी



धुर्वा थाना प्रभारी प्रवीण कुमार



लापता इंजीनियर सुजीत कुमार

को दी गई। सूचना मिलने के बाद धुर्वा थाना प्रभारी प्रवीण कुमार दल बल के साथ घटनास्थल

पर पहुंचकर मामले की जांच की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में या पाया है की सुजीत कुमार पैदल किसी तालाब की ओर जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद अंदर झाड़ियों में जाने के बाद वे वापस नहीं लौटे। न उसके बाद से उनका कुछ भी पता नहीं चल पाया है। धुर्वा थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने एनडीआरएफ टीम की मदद से पूरे तालाब में छानबीन की लेकिन सुजीत कुमार नहीं मिल सके हैं। फिलहाल उस तालाब को खाली भी किया जा रहा है। धुर्वा थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने बताया कि मामले की तहकीकात जारी है और जल्द ही मामले को सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा।

ट्रैक्टर चोरी में दो अपराधी गिरफ्तार

● ओम प्रकाश

ब डो के सेमरा गांव निवासी तीर्थदेव महतो के चोरी हुए ट्रैक्टर का खुलासा करते हुए पुलिस ने दो अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्त में आये आरोपितों में पवन उरांव और नामदेव उरांव शामिल है। गिरफ्तार अपराधियों ने की गई चोरी में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। ट्रैक्टर चोरी की घटना की जांच के लिए रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा के निर्देश में ग्रामीण एसपी नौशाद आलम के मार्गदर्शन में बेडो डीएसपी रजत मानिक

बाखला के नेतृत्व में टीम गठित कर जांच करने का आदेश दिया। गठित टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई



करते हुए गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि चोरी किए गए ट्रैक्टर को सुकवीर उरांव उर्फ आया तुफान अपने घर ले गया है। पुलिस द्वारा की जा रही लगातार छापामारी के डर से सुकवीर उरांव उर्फ आया तुफान ने उक्त चोरी के ट्रैक्टर को ग्राम-सेमला ककरिया, थाना-लापुंग, जिला-राँची में छोड़कर भाग गया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सुकवीर उरांव उर्फ आया, तुफान ने पूर्व से ही तुफान गिरोह बनाकर चोरी, रंगदारी जैसे कई अपराधों में संलिप्त रहा है। काड में फरार अपराध कर्मी की गिरफ्तारी हेतु लगातार छापामारी की जा रही है। ●



अपराधियों की हुई जमकर धुनाई

● ओम प्रकाश

स दर थाना क्षेत्र के गौस नगर गढ़ा टोली में शुक्रवार 17 दिसंबर को दिन में हवाई फायरिंग करने के आरोप में छोटा अनवर नामक युवक की स्थानीय लोगों ने पिटाई कर दी थी। पिटाई के बाद वह बुरी तरह से घायल हो गया था। जिसे बाद उसे आनन-फानन में रिस्स में भर्ती कराया गया। जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इस संबंध में स्थानीय लोगों में जुबेर, यासीन, एनामुल और कलाम ने लिखित शिकायत सिटी एसपी से की है। शिकायत में कहा है कि यह लोग रंगदारी मांगने, जमीन कब्जा और लूटने के इरादे से आए थे। जिसके बाद मोहल्ले के डरे सहमें हुए लोगों ने अपने बचाव के दौरान मारपीट

की ये घटना घटी। हवाई फायरिंग करने के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना रहा लेकिन पुलिस प्रशासन की टीम ने मोहल्ले वासी को



समझाया और मामले की निष्पक्ष जांच करने का आश्वासन दिया। मोहल्ले वासियों ने बताया कि छोटा अनवर अपने गैंग के साथ शराब पीने के बाद हर घर से रंगदारी की मांग करने और जमीन

हड़प लेने की बात कहता था। मोहल्ले वासियों ने ये भी बताया कि ये लोग दिनभर शराब पीकर हवा में फायरिंग करते हैं। छोटा अनवर गैंग लोगों को हमेशा धमकी देता है कि पुलिस को सूचना दी तो सारे घर को जप्त कर लेंगे और बच्चों का अपहरण कर लेंगे। ऐसे में कुछ माता-पिता हैं जो अपने बच्चों को स्कूल तक भेजना बंद कर दिए हैं। वहीं सदर थाना प्रभारी श्याम किशोर ने बताया कि ये आदिवासी जमीन है, जिस पर अवैध रूप से लोग यहां बसे हैं और इस जमीन का मामला थाना नहीं बल्कि सीइओ अपने स्तर से जांच करेगी। उन्होंने आगे बताया कि जहां तक मारपीट का संबंध है वहां पर हवाई फायरिंग की बात सामने आई है, तो अपराधियों पर लगाम लगाया जाएगा और नए तरीके से मामले की जांच की जाएगी फिलहाल मामला शांत है। ●

हाई स्पीड बाइक पर थी चोरों की नजर

● ओम प्रकाश

रा जधानी राँची के नामकुम थाना पुलिस ने चोरी की पाँच हाई स्पीड बाइक के साथ चार बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में सूरज गंडू, निवासी कोयरी बेड़ा, अनिल कच्छप और अनिल लिण्डा दोनों निवासी चरनाबेड़ा, बिरसा टुटी, निवासी कोलाद नामकुम शामिल हैं। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने बताया कि वरीय



पुलिस अधीक्षक महोदय सुरेंद्र कुमार झा के निर्देश पर जांच अभियान चलाया गया। जाँच के

दौरान रामपुर रिंग रोड की ओर से आ रहे बाइक सवार दो युवक पुलिस को देखकर भागने लगे जिसे पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ा एवं कागजात की मांग की। पर युवकों ने कागजात नहीं दिखाया जांच के क्रम में बाइक चोरी की निकली जिसपर आरोपी फर्जी नंबर प्लेट लगाकर चला रहे थे। युवकों ने बताया कि बाइक चोरी की है। जिसे बेचने के लिए निकले थे। उनकी निशानदेही पर चोरी की पाँच हाई स्पीड बाइक जब्त किया गया एवं चोरी में शामिल चार लोगों को गिरफ्तार किया गया। ●

अफीम तस्क़र हुआ गिरफ्तार

● ओम प्रकाश

रां ची की बुंदू पुलिस ने अफीम तस्क़र जनार्दन सेट को गिरफ्तार किया है। पुलिस में इसके पास से 3 किलोग्राम अफीम और एक बोलेरो गाड़ी जब्त की है। आपको बता दें की 14 दिसंबर मंगलवार की रात रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि बुंदू से जमशेदपुर की ओर एक बोलेरो से अफीम ले जाया जा रहा है। सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक रांची सुरेंद्र कुमार झा के द्वारा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नौशाद आलम रांची के निर्देशन में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बुंदू अजय कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने एक बोलेरो जो रंगमाटी से जमशेदपुर की ओर जा रही थी को देखा और उसे रुकने का इशारा किया। पुलिस को देखते ही बोलेरो पर सवार दो व्यक्ति वाहन को छोड़कर



बाहर निकलकर भागने लगे जिसे छापामारी दल द्वारा खदेड़ कर उनमें से भाग रहे एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया। जबकी दूसरा भागने में सफल रहा। गिरफ्त में आए व्यक्ति ने अपना नाम जनार्दन सेठ उर्फ लोखाई सेठ निवासी तमाड़ जिला रांची बताया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बुंदू अजय

कुमार के समक्ष जब बोलेरो की तलाशी ली गई तो बोलेरो से करीब 3 किलोग्राम अफीम बरामद किया गया। बरामद अफीम को टेस्टिंग किट से जांच करने पर अफीम ही पाया गया। पुलिस ने जनार्दन सेठ को गिरफ्तार कर उस पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। एवं उसके दूसरे साथी की तलाश के लिए छापेमारी कर रही है। ●

चोरी करने के आरोप में दो नाबालिग समेत आठ गिरफ्तार

● ओम प्रकाश

रां ची की सदर एवं मेसरा ओपी पुलिस ने नवोदय स्कूल में हुई चोरी की घटना का खुलासा कर लिया है। नवोदय विद्यालय के स्मार्ट क्लास रूम से 14 सैमसंग कंपनी का लैपटॉप, एक एसर कंपनी का डेक्सटॉप एवं एक 55 इंच का एलईडी टीवी 23 दिसंबर बुधवार को चोरी कर ली गई थी। विद्यालय में हुई चोरी की घटना को गंभीरता से लेते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक रांची सुरेंद्र कुमार झा के द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर सौरव के मार्गदर्शन में मामले का उद्भेदन एवं चोरी किए गए सामानों की बरामदगी के लिए पुलिस उपाधीक्षक सदर प्रभात रंजन बरवार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने तकनीकी एवं मानवीय सूत्रों का सहारा लेते हुए मामले का खुलासा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गठित टीम ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें दो नाबालिग शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों में राजू मिर्धा, संजय मिंज,



रवि कुमार प्रजापति, अनूप साहू, बबलू महतो उर्फ छोटू और अनमोल कालीन शामिल हैं। पुलिस जांच में पता चला है की यह लोग चारदीवारी फांद कर ग्रांड फ्लोर स्थित स्मार्ट क्लास में गए

वहां से लैपटॉप और डेक्सटॉप चोरी कर लाए और ग्रांड फ्लोर पर खड़े नाबालिग को ग्रिल के ऊपर से देते गए फिर ग्रिल फांद कर बाहर निकल गए। ●



डिलीवरी बॉय को चाकू गोदकर कर दी हत्या

● ओम प्रकाश

रा जधानी राँची के चुटिया थाना क्षेत्र स्थित ओवर ब्रिज के नीचे निवारनपुर में 30 दिसंबर गुरुवार को हुए डिलीवरी बॉय की हत्या के मामले का राँची पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने तीन अपराधियों को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया है। इनमें मुख्य अपराधी (चाकू मारने वाले) सहित तीन अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, जिनके नाम राजा, विष्णु थापा और नुमान हैं। आपको बताते चलें कि तीन से चार की संख्या में अपराधियों ने डिलीवरी बॉय मनोहर किशन की गुरुवार सुबह 9 बजे लूटपाट के दौरान चाकू



डिलीवरी बॉय मनोहर किशन



चुटिया थाना प्रभारी
वेंकटेश कुमार

मारकर हत्या कर दी थी। घटना की सूचना मिलते ही राँची के सिटी डीएसपी दीपक कुमार, चुटिया थाना प्रभारी वेंकटेश कुमार, डोरंडा थाना प्रभारी रमेश सिंह और लोअर बाजार थाना प्रभारी संजय कुमार मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए। इस घटना को गम्भीरता से लेते हुए राँची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने अभिलंब कार्रवाई करने का निर्देश दिया। घटना के तुरन्त बाद एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा के निर्देश पर सिटी एसपी सौरभ के मार्गदर्शन में सिटी डीएसपी दीपक कुमार के नेतृत्व में टीम घटित कर त्वरित कार्रवाई शुरू की गई थी। जिसके बाद चुटिया, लोअर बाजार, डोरंडा और अरगोड़ा के थाना प्रभारियों के साथ कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू की

गई। वही टेक्निकल टीम को भी लगाया गया था। जिसका नतीजा ये निकला कि राँची पुलिस ने 10 घंटे के अंदर ही इस हत्याकांड का खुलासा कर लिया। जानकारी के लिए आपको बता दें की चाकू मारने वाले अपराधी का नाम राजा है और वह राँची के डोरंडा थाना क्षेत्र का रहने वाला है।

चुटिया थाना प्रभारी वेंकटेश कुमार ने बताया की मृतक का नाम मनोहर किशन है और वह हरमू स्थित विद्या नगर में रहता था। वह मूल रूप से लोहरदगा जिले का रहने वाला हैं। सुबह जीप से डिलीवरी करने पहुंचे मनोहर को तीन अपराधियों ने लड़की से छेड़खानी करने की बात कहते हुए घेर लिया और एक के बाद एक पेट में चाकू से कई वार कर दिया। चाकू लगने के बाद



राँची के सिटी डीएसपी
दीपक कुमार

युवक मौके पर ही गिर पड़ा। इसके बाद उसके सहयोगी ने आनन-फानन स्थानीय लोगों की मदद से उसे सदर अस्पताल पहुंचाया। वहां से बेहतर इलाज के लिए घायल युवक को रिम्स भेज दिया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी ने यह भी बताया कि लड़की छेड़ने का आरोप महज एक बहाना था। असली उद्देश्य लूट की घटना को अंजाम देना था। मृतक डिलीवरी बॉय के साथ आए एक अन्य सहयोगी ने बताया कि हम लोग समान डिलीवरी के लिए आये थे। इसी बीच तीन चार युवक आकर मनोहर से बात करने लगे। उसके बाद एक युवक ने आते ही चाकू से हमला कर दिया। उसके बाद सब पैदल ही भाग गए। वहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे पर खून से लथपथ मनोहर की मदद करने के लिए कोई नहीं आया। इसी बीच एक सज्जन व्यक्ति आये और उसे उठा कर अस्पताल ले गये, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही उनकी मौत हो गई।



नशा है तो अपराध है :- बड़े दुख की बात है कि आज जहां भी देखो नशे का कारोबार ही फल-फूल रहा है। नशे के कारण आज के युवकों की मानसिकता खराब होती जा रही है। ये लोग नशा करने के आदि हो गए हैं। चिड़चिड़ी हो गए हैं। किसी की बात सुनना पसंद नहीं करते

हैं। आज के नव युवकों में नशा इस कदर हावी हो गया है कि ये लोग अपने शौक को पूरा करने के लिए हत्या जैसे संगीन जुर्म को करने से भी पीछे नहीं हटते। हर बुराई की जड़ के पीछे एक कारण होता है और वह कारण है नशा। जिस दिन नशा के खिलाफ समाज एकजुट होकर मुहिम

चलायेंगे। उस दिन अपराध खुद-ब-खुद खत्म हो जाएंगे। आज हम लोगों को चाहिए कि हर गली मोहल्ले में पांच पांच लोगों की कमेटी बनाकर इस नशे के आदी हुए युवकों के खिलाफ अभियान को और तेज करने की आवश्यकता है। ताकि नशा करने वालों पर अंकुश लगाया जा सके। ●

आईआईटी दिल्ली व जामिया समेत छः हजार संस्थानों का पंजीकरण खत्म

● रीता सिंह

भा रतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) और नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय उन करीब 6,000 संस्थानों या संगठनों में शामिल हैं, जिनका विदेशी चंदा (विनियमन) अधिनियम (FCRA) पंजीकरण शनिवार को समाप्त हो गया। अधिकारियों ने कहा कि इन संस्थानों ने या तो अपने थ्रू लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया या केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनके आवेदनों को खारिज कर दिया। विदेशी चंदा (विनियमन) अधिनियम (FCRA) से संबंधित आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, जिन संगठनों और संस्थानों का FCRA के तहत पंजीकरण समाप्त हो गया है या वैधता समाप्त हो गई है, उनमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, लाल बहादुर शास्त्री

मेमोरियल फाउंडेशन, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमन, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और ऑक्सफैम इंडिया शामिल हैं। FCRA के तहत पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों (NGO) और इसके सहयोगियों की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने



कहा कि अधिनियम के तहत पंजीकरण 1 जनवरी से समाप्त माना गया है।

विदेशी चंदा प्राप्त करने के लिए किसी भी संगठन और एनजीओ के लिए FCRA

रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। शुक्रवार तक 22,762 FCRA रजिस्टर्ड एनजीओ थे। यह घटकर 16,829 हो गए क्योंकि 5,933 एनजीओ ने कामकाज बंद कर दिया। जिन संगठनों का FCRA रजिस्ट्रेशन समाप्त हो गया है, उनमें मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI), इमैनुएल हॉस्पिटल एसोसिएशन, जो पूरे भारत में एक दर्जन से अधिक अस्पताल चलाता है, ट्यूबरकोलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, विश्व धर्मायतन, महर्षि आयुर्वेद प्रतिष्ठान, नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशरमेन को-ऑपरेटिव्स लिमिटेड शामिल हैं। इसके अलावा हमदर्द एजुकेशन सोसाइटी, दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क सोसाइटी, भारतीय संस्कृति परिषद, डीएवी कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी, इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर, गोदरेज मेमोरियल ट्रस्ट, दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी, जेएनयू में न्यूक्लियर साइंस सेंटर, इंडिया हैबिटेड सेंटर, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमन, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच भी इन संस्थानों या संगठनों में शामिल हैं। ●

महाप्रभु का रहस्य

सोने की झाड़ू से होती है सफाई...!

भगवान कृष्ण ने जब देह छोड़ी तो उनका अंतिम संस्कार किया गया, उनका सारा शरीर तो पांच तत्व में मिल गया, लेकिन उनका हृदय बिल्कुल सामान्य एक जिन्दा आदमी की तरह धड़क रहा था और वो बिल्कुल सुरक्षित था, उनका हृदय आज तक सुरक्षित है, जो भगवान् जगन्नाथ की काठ की मूर्ति के अंदर रहता है और उसी तरह धड़कता है, ये बात बहुत कम लोगो को पता है! प्रस्तुत है रीता सिंह की रिपोर्ट :-

महाप्रभु जगन्नाथ (श्री कृष्ण) को कलियुग का भगवान भी कहते हैं... पुरी (उड़ीसा) में जगन्नाथ स्वामी अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ निवास करते हैं, मगर रहस्य ऐसे है कि आजतक कोई न जान पाया...! हर 12 साल में महाप्रभु की मूर्ती को बदला जाता है, उस समय पूरे पुरी शहर में ब्लैकआउट किया जाता है, यानी पूरे शहर की लाइट बंद की जाती है, लाइट बंद होने के बाद मंदिर परिसर को CRPF चारों ओर से घेर लेती है, उस समय कोई भी मंदिर में नहीं जा सकता!

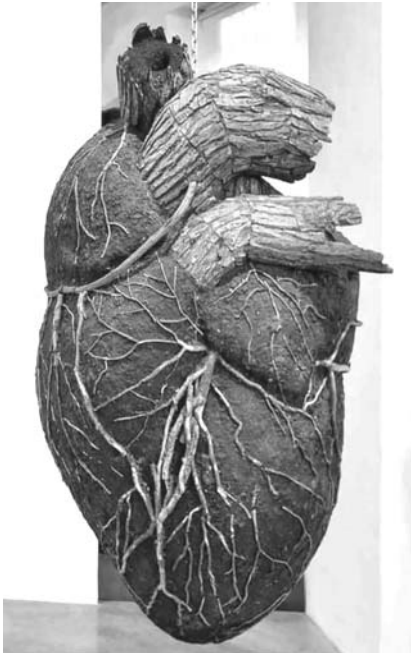
मंदिर के अंदर घना अंधेरा रहता है, पुजारी की आँखों में पट्टी बंधी होती है, पुजारी के हाथ में दस्ताने होते हैं, वो पुरानी मूर्ती से “ब्रह्म पदार्थ” निकालता है और नई मूर्ती में डाल देता है। ये ब्रह्म पदार्थ क्या है आजतक किसी को नहीं पता। इसे आजतक किसी ने नहीं देखा। हजारों सालो से ये एक मूर्ती से दूसरी मूर्ती में ट्रांसफर



किया जा रहा है!

ये एक अलौकिक पदार्थ है जिसको छूने मात्र से किसी इंसान के जिस्म के चिथड़े उड़ जाए। इस ब्रह्म पदार्थ का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। मगर ये क्या है, कोई नहीं जानता, भगवान जगन्नाथ और अन्य प्रतिमाएं उसी साल बदली जाती हैं, जब साल में आसाढ़ के दो महीने आते हैं। 19 साल बाद यह अवसर आया है, वैसे कभी-कभी 14 साल में भी ऐसा होता है, इस मौके को नव-कलेवर कहते हैं! मगर आजतक कोई भी पुजारी ये नहीं बता पाया की महाप्रभु जगन्नाथ की मूर्ती में आखिर ऐसा क्या है? कुछ पुजारियों का कहना है कि जब हमने उसे हाथ में लिया तो खरगोश जैसा उछल रहा था...आँखों में पट्टी थी...हाथ में दस्ताने थे तो हम सिर्फ महसूस कर पाए...! आज भी हर साल जगन्नाथ यात्रा के उपलक्ष्य में सोने की झाड़ू से पुरी के राजा खुद झाड़ू लगाने आते हैं...! भगवान जगन्नाथ मंदिर के सिंहद्वार से पहला कदम अंदर रखते ही समुद्र की लहरों की आवाज अंदर सुनाई नहीं देती, जबकि आश्चर्य में डाल देने वाली बात यह है कि जैसे ही आप मंदिर से एक कदम बाहर रखेंगे, वैसे ही समुद्र की आवाज सुनाई देगी...!

आपने ज्यादातर मंदिरों के शिखर पर पक्षी बैठे-उड़ते देखे होंगे, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं गुजरता, झंडा हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है, दिन में किसी भी समय भगवान जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई नहीं बनती! भगवान जगन्नाथ मंदिर के 45 मंजिला शिखर पर स्थित झंडे को रोज बदला जाता है, ऐसी मान्यता है कि अगर एक दिन भी झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा! इसी तरह भगवान जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है, जो हर दिशा से देखने पर आपके मुंह आपकी तरफ दिखता है! भगवान जगन्नाथ मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए मिट्टी के 7 बर्तन एक-दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, जिसे लकड़ी की आग से ही पकाया जाता है, इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान पहले पकता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर में हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के लिए कभी कम नहीं पड़ता, लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि जैसे ही मंदिर के पट बंद होते हैं वैसे ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है और भी कितनी ही आश्चर्यजनक चीजें हैं, हमारे सनातन धर्म की! ●



अपराध करने वाला सिर्फ अपराधी है : स्वर्ण

शांत स्वभाव, मृदुभाषी एवं तीखे तेवर वाले 2017 बैच के आईपीएस स्वर्ण प्रभात अपराध, अपराधियों एवं शराब माफियाओं पर लगातार नकेल कसते हुए शांतिपूर्ण विधि व्यवस्था बनाने के लिए प्रयासरत हैं एवं फिलवक्त भागलपुर एसपी सिटी का पदभार संभालने के उपरांत हमारे प्रतिनिधि श्रीधर पाण्डेय ने खास मुलाकात की, जिसके सम्पादित कुछ अंश :-

★ **बतौर सिटी एसपी भागलपुर का पद आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण है?**

भागलपुर प्राचीनकालीन शहर है, काफी पुराने शहर होने की वजह से बहुत सी पुरानी परम्पराएं बृहत ढंग से मनाई जाती हैं। अगर पुलिसिंग दृष्टिकोण से देखा जाए कम्युनलिंग चौलेंज रहा हैं। यहाँ त्योहारों के सीजन जैसे बकरीद, मुहर्रम, दशहरा, विषहरी पूजा एवं काली पूजा तो बड़े स्तर पर होता है और उस समय आपसी टकराव की आशंका बनी रहती थी। यहाँ मिक्स पॉपुलेशन है और विगत के कुछ वर्षों में आने वाले त्योहारों में कई छोटी छोटी घटनाएं सामने आई हैं। मैंने जब यहाँ का पदभार सम्भाला था तो हमारे लिए भी चुनौतीपूर्ण रहा है क्योंकि मेरी पहली पोस्टिंग एसपी सिटी भागलपुर के रूप में है एवं पदभार संभालने के तुरंत बाद त्योहारों के सीजन शुरू हो गए और हमलोग के प्रयास एवं यहाँ की जनता की सहयोग से सभी पर्व शांतिपूर्वक सम्पन्न हो गए।

★ **विगत वर्षों में भागलपुर में साम्प्रदायिक दंगे जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, भविष्य में ऐसा न हो इसके लिए आप किस तरह से प्रयासरत हैं?**

भागलपुर में 1989 के बाद से शांति समिति काफी सक्रिय एवं कारगर हैं। यहाँ के लोग प्रशासन के काम में मदद करते हैं। हर लेवल पर कमिटी का गठन हुआ है, थाना, अनुमंडल एवं जिला स्तर पर शांति समिति हैं ही साथ ही साथ सेंट्रल मुहर्रम कमिटी, काली पूजा समिति एवं अन्य कई समितियां जिसके साथ बैठकर हर लेवल की गतिविधियों की जानकारी हासिल किया जाता रहा है। कभी जिला तो कभी थाना लेवल पर भी बैठकर उनका पक्ष जानने की कोशिश की जाती है एवं पुलिस अपनी पक्ष समझाती हैं। समितियों में अच्छे लोग के जुड़े होने की वजह से हर तरह की सूचना मिल जाती है। ये समितियों भी अपराध नियंत्रण में भी कुछ हद तक भूमिका निभाते हैं। शराब, गाँजा ब्राउन शुगर एवं अन्य तरह की प्रतिबंधित चीजों पर नकेल कसने में आसानी हो जाती है। समितियों के बैठक के अलावा कम्युनिटी पुलिसिंग के बदैलत भी बहुत सी सूचनाएं वन टू वन मिलने के उपरांत कार्रवाई की जाती है।

★ **बतौर सिटी एसपी भागलपुर आपकी प्राथमिकता क्या है?**

मेरा मानना है कि पुलिस का सबसे बड़ा काम शांति एवं सुरक्षा का माहौल देना ही है। मेरे नजर में अपराध छोटा हो या बड़ा अपराध करने वाला हर शख्स अपराधी ही है उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। मैंने भागलपुर सिटी एसपी का पदभार जब सम्भाला तो यह पद सात महीनों

से रिक्त था। जब आए तो काफी चैलेंजिंग था क्योंकि पद खाली होने की वजह से ऑफिस का प्रभाव धीरे-धीरे कम होने लगता है। सिटी एसपी को एसपी और एसएसपी के बीच में पहचान बनाना होता है और जब पद रिक्त हो तो स्ट्रीम लाइन में नहीं रहता है, ऑफिस सेटअप करना, लोगो का अप्रोच नहीं करने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। लेकिन मैं जॉइन करने के तुरंत बाद बैठने लगा तो पब्लिक के बीच मैसेज जाने लगी, कोई जरूरत हो तो वो मुझसे ऑफिस में आकर मिलने लगे। जॉइन के दो दिन बाद ही बकरीद थी और सारे फेस्टिवल आने लगे। लॉ एंड आर्डर सबकुछ देखा पड़ा। लोग ऑफिस सेटअप के बाद अपनी समस्याएं लेकर मिलने लगे। अपराध-अपराधियों एवं शराब माफियाओं तथा प्रतिबंधित चीजों पर नकेल कसी जा रही है। अभी हाल ही में जीरो माइल थाना के द्वारा 159 किलोग्राम गाँजा

बरामद की गई। क्राइम डिटेक्ट करते हुए सैकड़ों अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है जिसकी वजह से घटनाएं में काफी कमी आई है।

★ **शहर में यातयात की समस्याओं से निजात से दिलाने के लिए किस तरह के प्रयास जारी हैं?**

भागलपुर काफी प्राचीन होने की वजह से कुछ स्ट्रक्टर इशू है जिसकी वजह से कुछ

जगह जाम की समस्याएं उत्पन्न रहती हैं। भागलपुर में ट्रैफिक डीएसपी का पद है जो फिलहाल रिक्त है और उसके प्रभार मुख्यालय डीएसपी देख रहे हैं। सड़को पर लगभग 75 सिपाही जाम से निजात दिलाने के साथ-साथ मोटर अधिनियम के उल्लंघन करने वालों पर नकेल कसने के लिए प्रयासरत हैं। ट्रैफिक थाना भी अच्छे ढंग से कार्य कर रहा है। जाम होने की वजह के कुछ बिंदु होते हैं जैसे सड़को का चौड़ीकरण, फ्लाय ओवर, ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक पुलिस प्रयासरत है ताकि अतिक्रमण एवं नो पार्किंग में गाड़ी लगाकर कोई जाम की समस्या उत्पन्न न करे।

★ **आप युवा हैं और आईपीएस भी। आईपीएस बनने से पूर्व पुलिस के लिए मन में क्या भ्रांतियां थी?**

मन में भ्रांतियां तो रहता है पुलिस काफी अप्रोचबल नहीं है। डीएसपी, एसपी से कैसे मिले, कैसे बातें करें लेकिन जब मैं आया तो देखा कि काफी चीजे बदल गई हैं एवं जनता में जागरूकता ने उसे पुलिस को मित्र बना दिया है। व्हाट्सएप के माध्यम से भी लोग अपनी सूचना पुलिस तक पहुंचा देते हैं एवं वरीय लोग भी उनकी सूचनाओं को गम्भीरता से लेते हैं। हमलोग का नंबर इजली अविलेवल है तो लोगो का कॉल उठाते हैं उन्हें



जवाब दिया जाता है।

★ युवा आईपीएस हैं, क्या बदलाव लाना चाहेंगे?

अभी जो बदलाव की बात है तो सबसे जरूरी है हमारे विभाग में मेन पावर की कमी है ही साथ ही साथ सिपाही से लेकर ऊपर लेवल तक के लोगो को लगातार ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। रिसोर्सिंग भी धीरे धीरे बढ़ा है लेकिन उसमें और जरूरत है। जैसे गाड़िया कम थी, भवन कम थे लेकिन अब बढ़े हैं लेकिन इसमें और सुधार लाया जा सकता है।

★ अपराध अनुसन्धान के कोई नया तरीका जिसमें दोषियों पर सख्त कारवाई की जा सके?

कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए एविडेंस की जरूरत होती है। साक्ष्य के लिए टेक्निकल एवीडेंस एवं फोरेंसिक एविडेंस हैं, सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्, एफएसएल पहले ये चीजें नहीं होती थी जिसकी वजह

से सिर्फ बयान के आधार पर ही केश डायरी तैयार किया जाता था।

★ अपराधी बनने की वजह क्या मानते हैं आप?

ऐसे तो अपराधी दो तरह के होते हैं एक तो हार्ड कोर क्रिमिनल दूसरा परिस्थिति वश अपराध में भाग लेना। पेशेवर अपराधी जैसे के लिए कुछ भी करता है दूसरा परिस्थितियाँ ऐसी बनी जैसे 498ए, आपसी कलह संपत्ति विवाद लेकिन ये सब अपराध ही हैं।

★ केवल सच के माध्यम से बिहार के युवाओं के लिए संदेश।

जो भी युवा भटक रहे हैं जैसे स्मैक, शराब, अपराध, छिनतई में अपनी भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, उन्हें जेल जाने से नौकरी मिलने से रह गया एवं उनका भविष्य खराब हो जाता है इसलिए ऐसे शार्ट पथ पर कभी न चले। मेहनत करे, पढ़ाई करें और ऐसे पथ पर चले जिनसे उनका भविष्य बेहतर हो और राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्ती भूमिका निभा सके।

सही गाइडेंस और रणनीति दिलायेगी सफलता : काम्या मिश्र

● श्रीधर पाण्डेय

सि

विल सर्विसेज की प्रतिष्ठा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह राष्ट्र के अधिकांश युवाओं का सपना होता

है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित इस परीक्षा में हर वर्ष अपनी संजोए लाखो युवा भाग लेते हैं और परिणाम में अंततः पॉइंट में सफल होते हैं और जिन्होंने सफलता हासिल कर लिया हो उसकी दुनिया में चर्चा होने लगती है और यहीं से उसका संघर्ष लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता बटोरता नजर आने लगता है। आज हम वैसे ही एक सफल व्यक्तित्व की चर्चा करेंगे जो अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी की दहलीज में प्रवेश कर, अपने सेवा के अल्पकाल में ही लोगो के बीच चर्चा का विषय बनी हुए हैं वह शख्सियत हैं 2019 बैच के आईपीएस मूलरूप से उड़ीसा निवासी काम्या मिश्र का जिन्होंने 22 साल के उम्र में ही यूपीएससी की परीक्षा में सफल बनकर युवाओं के बीच एक आइकॉन के रूप में अपनी छवि



स्थापित करने में सफल रही। 2019 में सिविल सर्विसेज में टॉप करने के उपरांत काम्या को हिमाचल प्रदेश कैडर में आईपीएस के रूप में अलॉट हुआ लेकिन परिस्थितिवश सेवा के अल्प काल के बाद ही इनको बिहार कैडर अलॉट हो गया है। काम्या मिश्र के पति भी बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं।

बिहार कैडर की आईपीएस नियुक्त होने के उपरांत सहायक पुलिस अधीक्षक वैशाली

के रूप में काम्या को कमान सौंपी गई जहाँ उन्होंने अपनी कर्मठता, दक्षता, योग्यता एवं अनुभव के दम पर खूब सुर्खियां बटोरी एवं ट्रेनिंग के बाद प्रमोट करते हुए सुशासन सरकार की नाक कहा जाने वाला राजधानी पटना के अतिसंवेदनशील क्षेत्र सचिवालय का अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बनाया गया। सचिवालय एएसपी का पदभार संभालने के उपरान्त ही काम्या मिश्र ने अपराध, अपराधियों

परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करनी चाहिए। असफलताओं से घबराने की जरूरत नहीं है, जो लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं उन्हें सफलता निश्चित तौर पर मिलती है और मिलेगी भी। आजकल के युवाओं के बीच भटकाव के बहुत सारे माध्यम पास में ही हैं, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आज समाज पूरी तरह से हाई टेक हो रहा है, मोबाइल टीवी, इंटरनेट का प्रयोग ज्ञानवधन के लिए जरूरी है और इनका ज्यादा प्रयोग भटकाव का माध्यम भी बन सकता है। यूथ को अपने कैरियर के बारे में सोचनी चाहिए, कैरियर ही प्राथमिकता है क्योंकि बेहतर कैरियर का राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होता है। खासकर यूपीएससी जैसी देश की प्रतिष्ठित परीक्षा में शामिल होने वाले युवाओं के लिए यही संदेश की आजकल हर तरह की सेवाओं के लोग यूपीएससी में भाग ले रहे हैं साथ ही साथ इंजीनियर, डॉक्टर भी इसमें भाग ले रहा है इसलिए

एवं शराब माफियाओं पर नकेल कसना शुरू कर दी साथ ही साथ विधि व्यवस्था एवं वीआईपी सुरक्षा में भी काफी मुस्तैद दिखती नजर आ रही है। काम्या मिश्रा ग्रेजुएट होते ही आईपीएस अधिकारी बन गई हैं, युवा हैं एवं युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय भी। युवाओं के बारे में बातचीत के दरम्यान बताया कि युवा देश के भविष्य हैं, इन्हें अपनी कार्यक्षमता एवं शक्ति को पहचानने की जरूरत है। यूथ अगर कोई प्रतियोगी

रणनीति की तहत पढ़ाई करना जरूरी है क्योंकि बीच में कहीं भी चूक हो जाए तो पुनः फिर से प्रयास करना होगा। युवाओं के सही गाइडेंस के साथ साथ कठिन परिश्रम यूपीएससी में सफलता निश्चित दिला सकती है। जरूरी नहीं कि आप दिन रात पढ़ते रहे लेकिन एक रणनीति के तहत मिनिमम 12 14 घन्टे की पढ़ाई जरूरी है क्योंकि आप देश के सबसे कठिन परीक्षा में भाग में लेने जा रहे हैं। ●

हर क्षेत्र को विकसित करना मेरी प्राथमिकता : डीडीसी

2018 बैच के आईएएस डीडीसी भागलपुर प्रतिभा रानी से विभिन्न मूद्दों पर वार्ता करते हुए हमारे

पत्रिका प्रतिनिधि श्रीधर पाण्डेय, जिनके सम्पादित कुछ अंश :-

★ बतौर डीडीसी भागलपुर शहर में कैसा महसूस कर रही हैं?

भागलपुर मुझे बहुत अच्छा लगा। बड़ा एवं ऐतिहासिक शहर हैं, बड़ा क्षेत्र हैं तो काफी कुछ यहाँ मुझे सीखने को मिलेगी।

★ जिले में ऐसा क्या खास एवं महत्वपूर्ण हैं, जिससे यह प्रदेश में अलग स्थान रखता है?

भागलपुर काफी प्राचीनकालीन शहर हैं एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसकी महत्ता आज भी बरकरार हैं। जिलों में बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें हैं एक तो जिले में काफी क्षेत्र से होकर गंगा नदी होकर गुजरती हैं दूसरी सिल्क के क्षेत्र में इसका अपना अलग महत्व हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय यहाँ के लोगो को लंबे समय से शिक्षा के प्रति जागरूक होने की संकेत देते हैं।

★ बतौर डीडीसी आपकी प्राथमिकता क्या है?

बतौर डीडीसी मेरी पहली पोस्टिंग यहाँ हैं। केंद्र एवं राज्य सरकार की तरफ से चलायी जाने वाले जनकल्याणकारी योजनाओ को धरातल पर मजबूती से लागू करना हमारी प्राथमिकताओं में शामिल हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना, लोहिया स्वच्छ अभियान, मनरेगा के साथ साथ अन्य योजनाओं का कार्यन्वयन का लोगो को अधिक से अधिक एवं जल्द लाभ मिल सके।

★ क्या भागलपुर में साम्प्रदायिक माहौल विकास में बाधा बने, भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर आप क्या सोचती हैं?

विगत कुछ वर्षों में ऐसा हुआ था लेकिन अब यहाँ की पुलिस प्रशासन के साथ जनता भी बढ़-चढ़कर शांतिपूर्ण माहौल तैयार के अपनी महत्ती भूमिका निभाती हैं। इस वर्ष भी शांतिपूर्ण विधि व्यवस्था रही।

★ क्या आपके विभाग में सभी कर्मचारी एवं पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से करते हैं?

हमारी यही कोशिश रहती हैं कि सभी लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से करे। जहाँ ऑफिसर अच्छे होते हैं वहाँ तेजी से काम होता है और जहाँ ऑफिसर थोड़े सुस्त हैं वहाँ काम स्लो हो जाता है। लेकिन हमलोग, हमारे डीएम सर हर विभागों की क्रमवार समीक्षा करते हुए कार्यों में तेजी लाने के लिए दिशा निर्देश देते हैं और उसके बाद भी कार्यों में कोताही होती है तो उनके पर विधि सम्मत करवाई भी होती है। जो भी कार्य जनता के लिए है ससमय हो जानी चाहिए, यहाँ लगभग सभी अच्छे पदाधिकारी लोग हैं।

★ मनरेगा में काफी गड़बड़ियाँ सुनने को मिल रही हैं, इसमें कितनी सच्चाई है?

जहाँ तक मनरेगा की बात है इसका मुख्य उद्देश्य दो हैं एक तो

अकुशल लोगो को 100 दिन के कार्य की गारंटी देता है वहीं दूसरी तरफ रूलर एरिया में कोई एसेट तैयार किया जाता है। इन दोनों क्षेत्र में जहाँ भी कुछ गड़बड़ी हो तो विधिवत करवाई तय है।

★ आप युवा आईएएस अधिकारी हैं। बतौर युवा प्रशासन को किस नजरिये से देखती हैं?

आज समाज की जागरूकता ने युवाओं को प्रशासन से काफी हद तक जोड़ दिया है। प्रशासन जागरूक युवाओं के लिए एक बड़ा माध्यम है जिसके साथ वह मिलकर समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, सोशलवर्क, पर्यावरण के साथ साथ अन्य पॉजिटिव बिंदुओं पर कार्य कर एक अच्छा माहौल क्रिएट कर सकता है।

★ भागलपुर डीडीसी के रूप में आप ऐसा क्या करना चाहेंगी जिससे आपको लोग सदियों तक याद रखे?

हमलोग ऐसा सोचकर कार्य कार्य नहीं करते हैं। जहाँ हमलोग की पोस्टिंग होती है वहाँ हमलोग बेहतर देने की प्रयास करते हैं। मुझे लगता है लोगो को मुझे जानने से ज्यादा बेहतर है कि हमसे ज्यादा हमारे क्षेत्र में चल रही जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को जाने, उसका जो महत्व है उसे समझे। हमारी कोशिश

है कि अधिक से अधिक लोगो को योजनाओ के लाभ मिले। छोटी से छोटी जानकारियाँ लोगो तक पहुँचे। हमारे यहाँ आंगनबाड़ी को बाला टेक्निक बनाने की तैयारी चल रही है, हर पंचायत में एक आंगनबाड़ी बाला टेक्निक से बने, जिससे की बच्चों को ठीक - ठाक शिक्षा मिले। ग्रामीण परिवेश के बच्चे को बेसिक एजुकेशन महत्वपूर्ण है। उद्योग विभाग के द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है, लोगो को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा है मार्केट क्रिएट एवं ब्रांड बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है।

★ आपके काम पारदर्शिता के साथ लोगो के बीच पहुँचे उसके लिए क्या प्रयास जारी है?

सारे काम पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। हर चीजें ऑनलाइन पोर्टल पर मौजूद हैं। सारी योजनाओ का क्रियान्वयन भी है। अधिप्राप्ति की राज्यस्तर पर भी होती है हर एक चीजे की डाटा एंट्री होती है इसे आवश्यक माना गया है।

★ केवल सच के माध्यम से राष्ट्र के युवाओं के लिए कोई सन्देश?

मेरी तरफ से जो भी कोई कुछ करना चाहे उसे दृढ़ निश्चय एवं ईमानदारी से करे उसमें आवश्य सफलता मिलेगी। समाज को भी सही दिशा में ले जाने के लिए प्रयासरत रहे। सही एवं गलत में फर्क समझे। गलत अट्रैक एवं आसान हो तो भी उस तरफ कभी झुकाव न हो यह राष्ट्र के युवाओं के लिए सन्देश है।

दृढ़निश्चय एवं ईमानदार प्रयास दिलायेगी सफलता : शुभम

सिविल सेवा परीक्षा को देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। इस परीक्षा में सफलता का प्रतिशत बहुत कम होता है। इस परीक्षा का सिलेबस बहुत ज्यादा होता है और इसकी तैयारी में बहुत समय लगता है। ज्यादातर उम्मीदवारों का धैर्य इस परीक्षा की तैयारी के दौरान जवाब दे जाता है और जिन्होंने धैर्य के साथ ईमानदारी पूर्वक प्रयास करते रहे उन्होंने सफलता की गाथा इतिहास में दर्ज कर दिया है। हम वैसे ही शिखरतक की चर्चा करेंगे जो मिडिल क्लास की फैमिली से आते हैं उन्होंने अपने दूसरे प्रयास में यूपीएससी की दहलीज में प्रवेश करके भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी बन गए हैं वह हैं मूल रूप से उत्तरप्रदेश के सहारनपुर निवासी एवं वर्तमान में भागलपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर शुभम आर्य। आईपीएस शुभम आर्य से हमारे विशेष प्रतिनिधि श्रीधर पाण्डेय ने खास मुलाकात कर विभिन्न मूद्दों पर वार्ता की जिसके सम्पादित कुछ अंशः-

बा तचीत के क्रम में आईपीएस शुभम आर्य बताते हैं कि वह मूल रूप से उत्तरप्रदेश के सहारनपुर जिले के एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं जहाँ इनके माताजी हाउस वाइफ हैं और पिता जी कृष्णलाल आर्य पेशे से सिविल इंजीनियर हैं। दो भाई बहनों में सबसे बड़े शुभम का लगाव शुरू से ही शिक्षा के प्रति रहा है और वह पढ़-लिखकर जल्द ही सरकारी नौकरी में आना चाहते हैं। इन्होंने मैट्रिक आईसीएसई से तो वहीं 12वीं सीबीएसई से करने के उपरांत एससीआरए की परीक्षा निकाला एवं बीटेक में केनिकल इंजीनियरिंग से पूरा कर जमालपुर में भारतीय रेल में जॉइन किया। इन्होंने रेलवे में आईआरएसएमई के पद पर अपने कर्तव्य का निर्वहन करने लगे उसी दरम्यान सिविल सर्विसेज की तैयारी का सवाल मन में पनपने लगा। एक तो रेलवे में नौकरी पाना मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी बात होती है दूसरी तरफ समाज के साथ जुड़कर कार्य करने की दृढ़ इच्छा ने सिविल सर्विसेज के प्रति झुकाव उत्पन्न कर दिया। नौकरी से लीव लेकर यूपीएससी के तैयारी के लिए दिल्ली तो निकल गए लेकिन प्रथम प्रयास में प्री तक ही पहुँच पाए फिर भी हिम्मत नहीं हारी और लगातार 12 घन्टे से ज्यादा



समय का मेहनत जारी रहा और उनका दृढ़ निश्चय एवं ईमानदारी पूर्वक प्रयास में दूसरी बार में सफलता दिलाया और वह भारतीय पुलिस सेवा में आ गए। शुभम बताते हैं कि कोई भी अभ्यर्थी शयोर नहीं रहता कि इस बार वह 100% सफल हो ही जाएगा लेकिन परीक्षा देने के बाद क्वेश्चन से समझ आने लगता है कि शायद इस

बार चांस बन जाएगा। यूपीएससी डेडिकेशन मांगता है, हार्डवर्क ईमानदारी पूर्वक मांगता है। मैंने कोचिंग में एडमिशन लिया था लेकिन क्लास जा पाना मुश्किल था घर पर ही 12 घन्टे से ज्यादा समय पढ़ाई पर फोकस करते हैं। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले युवाओं को लगातार मेहनत एवं सही दिशा में करनी चाहिए तो सफलता निश्चय हो जाएगी।

बतौर आईपीएस बिहार सरकार एवं

यहाँ की पुलिस व्यवस्था काफी बेहतर है। जब मैं पुलिस में नहीं था तो उनके कार्यप्रणाली को समझ नहीं पाया था, पुलिस का जॉब काफी चौलेंज है। समाज के मन में भ्रातियां होती ही हैं लेकिन पुलिस का स्वरूप काफी बदला है और इसमें और सुधार की जरूरत है। धीरे-धीरे बिहार पुलिस भी फ्रंटली होती जा रही है। अपने ट्रेनिंग के दिनों की याद करते हुए शुभम आर्य बताते हैं कि नेशनल पुलिस एकाडेमी एक सिविल को पुलिस अधिकारी में कन्वर्ट कर देता है। हर तरह की गतिविधियों से ट्रेड कराया जाता है। पुलिस में डिजीनन तुरन्त लेने की जरूरत पड़ती है और एनपीए फिजिकल मेंटली हर तरह से मजबूत कर देता है। देश के युवाओं को सन्देश देते हुए भारतीय पुलिस सेवा 2019 बैच के अधिकारी शुभम आर्य बताते हैं कि यह भारत के लिए चैलेंजिंग समय है। प्रगतिशील देश में देश के युवाओं की भूमिका बहुत ज्यादा है, युवाओं के सही दिशा में योगदान उनके सक्षम एवं देश को मजबूत बना पाएंगे। देश को तरक्की के नई राह पर ले जाएगा। यूपीएससी की तैयारी करने वाले युवाओं को देश की हर समस्याओं की जानकारी सही ढंग से रहती है। देश के हर गतिविधियों की जानकारी रखने वाले युवा यूपीएससी को सिर्फ नौकरी नहीं समझे यह राष्ट्र की सेवा है। राष्ट्रहित का सोच सबसे पहला कदम देश के अच्छे सेवक बनने का प्रयास प्रिपेशन से शुरू हो जाता है। ●

नववर्ष, गणतंत्र दिवस एवं बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर पंचायत की समस्त जनता को हार्दिक शुभकामनाएँ।

-: निवेदक :-

संतोष कुमार राय

पैक्स अध्यक्ष, बाबुबांध पंचायत
प्रखण्ड-चरपोखरी, भोजपुर

जनसुनवाई में न हो परेशानी, इसलिए खुले में बैठे जिला लोकशिकायत पदाधिकारी पटना

● श्रीधर पाण्डेय

को रोना की तीसरी लहर देश में तेजी से फैल रही हैं। कोरोना की पहली एवं दूसरी लहर ने दुनिया की विकास की रफ्तार को रोक रखा था उसी से संघर्ष करते हुए समाज आगे बढ़ने की कोशिश कर ही रहा था कि तीसरी लहर ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया हालांकि वैक्सिनेशन हो जाने की वजह से इसका प्रभाव कम दिख रहा है लेकिन पॉजिटिव मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने कोरोना की नई गाईडलाइन जारी कर दिया है जिसके तहत सभी क्षेत्रों में थोड़ी बहुत परेशानियां बढ़ी हैं। दीगर बात यह है कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए जिला लोकशिकायत पदाधिकारी पटना अजय कुमार ने अपने ऑफिस के बगल में बने हॉल में जनसुनवाई के माध्यम से लोगों की समस्याओं का निराकरण करते दिखे। अजय कुमार ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर काफी तेजी से बढ़ रही



हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए हॉल में कार्य किया जा रहा है ताकि सामाजिक दूरियों का

पालन करते हुए लोगों की समस्याओं का निष्पादन किया जा सके। ●

झांसी रेलवे स्टेशन अब हुआ वीरंगना लक्ष्मीबाई के नाम

● रीता सिंह

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक और रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया है। अब झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरंगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के नाम परिवर्तित करने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी मिलने के बाद शासनादेश जारी कर दिया गया है। बता दें कि तीन महीने पहले गृह मंत्रालय को ये प्रस्ताव दिया गया था कि झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाए। अब उसी प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए यूपी सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल वीरंगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया है। रेलवे स्टेशन का कोड भी अब बदल दिया जाएगा। सरकार की तरफ ये तर्क दिया जा रहा है कि स्टेशन का नाम बदलने से भी क्षेत्र में पर्यटन

की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। बुंदेलखंड इलाके में भी इसका लाभ देखने को मिल सकता है। वैसे



राज्य सरकार ने कई मौकों पर ये स्पष्ट किया है कि जरूरत के हिसाब से नाम बदले जाएंगे। इससे पहले योगी सरकार ने अपने कार्यकाल में फैजाबाद

को अयोध्या, इलाहाबाद को प्रयागराज, मुगलसराय को दीन दयाल उपाध्याय नगर बना दिया है। इस बार फर्क ये रहा है कि सरकार ने शहर की जगह किसी रेलवे स्टेशन का नामकरण कर दिया है।

☞ **शायरों के नाम पर विवाद :-** इसके अलावा यूपी में शिक्षा आयोग ने कई मशहूर शायरों के नामों को बदलकर प्रयागराज के नाम पर कर दिया है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी का नाम बदलकर "अकबर प्रयागराजी" कर दिया। साथ ही तेग इलाहाबादी का भी नया नामकरण करके तेग प्रयागराज और राशिद इलाहाबादी को राशिद प्रयागराज कर दिया लेकिन जब इस फैसले पर विवाद बढ़ा तो आयोग ने सफाई दी कि उनकी साइट को हैक कर लिया गया था। ●

जमुई में निर्विरोध जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पांच प्रमुख

जमुई में निर्विरोध का बाढ़ आ गया

इस बार जमुई जिला पंचायत चुनाव में इतिहास बनाया है। निर्दलीय और निर्विरोध का तो छड़ी लग गया है जमुई में। नव वर्ष के साथ ही जमुई की राजनैतिक परिदृश्य भी करबट बदल रहा है। मानो जिले में मात्र एक ही नेता का दबदबा हो। इस बार के जिला परिषद् अध्यक्ष और प्रखंड प्रमुख चुनाव में किसी भी नेताओं ने हस्तक्षेप नहीं किया है और एक निर्विरोध जिला परिषद् सदस्य फिर वही निर्विरोध जिला परिषद् अध्यक्ष और तो और जिले के दस प्रखंडों में से पाँच प्रखंड के प्रखंड प्रमुख का निर्विरोध चयन होना जिले के विकास की पहिए को गति मिलता दिखाई दे रहा है तथा यह एक स्वस्थ राजनीति के परिचायक भी है। जमुई से हमारे जिला ब्यूरो अजय कुमार की रिपोर्ट :-

राज्य की राजनीति में जमुई जिले का अहम योगदान रहा है। हमेशा जमुई जिले की राजनीति दो धुरी में हुआ करती थी। एक धुरी नरेन्द्र सिंह की तो दूसरी धुरी जयप्रकाश नारायण यादव की। चिराग पासवान के जमुई से लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद से तीसरी धुरी तैयार होने का आसार बना था पर यह तीसरी धुरी तैयार नहीं हो सकी तो कभी चौथी धुरी बनने में अग्रसर था और वह था दामोदर रावत का जो जिले में एक मात्र सत्ता पक्ष के मंत्री हुआ करते थे पर यह धुरी भी खास स्थान नहीं बना सकी। यह सारी बातें हम इस लिए कर रहे हैं कि सारी धुरी एक खास जाति के दमदार नेता को अपने पाले में रखने की राजनैतिक खेल होता रहा। कभी यादव समाज से आने वाले दमदार नेता हुआ करते थे राजेन्द्र यादव उर्फ राजू यादव। राजू यादव हमेशा से राजद के जयप्रकाश नारायण यादव के करीबी हुआ करते थे पर नरेन्द्र सिंह अपने राजनैतिक



गुड्डू यादव अपनी पत्नी जिला परिषद् अध्यक्षा के साथ



गुलाबी यादव अपनी पत्नी लक्ष्मीपुर प्रखण्ड प्रमुख के साथ

कौशल से राजू यादव को अपने पाले में करने में सफल रहे। राजू यादव जमुई जिला परिषद् के चार बार उपाध्यक्ष रहे और एक बार अध्यक्ष भी बनाये गये। राजू यादव के असामयिक निधन के बाद से जिले में एक यादव समाज के मजबूत और दमदार नेता को अपने पक्ष में करने में नरेन्द्र सिंह और जयप्रकाश गुट लगे रहे ताकि राजनीति का पलड़ा भारी बना सके। हालिया राजनैतिक समीकरण में नरेन्द्र सिंह गुट इसमें कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। नरेन्द्र सिंह के छोटे पुत्र सुमित सिंह चकाई से निर्दलीय विधायक हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी हैं जो जमुई की राजनीति में नरेन्द्र सिंह के छाप छोड़ते दिखाई देते हैं। वर्तमान जिला परिषद् अध्यक्ष के चुनाव निर्विरोध करवाने में सुमित का अहम योगदान रहा है और तो और

चकाई से जिला परिषद् उपाध्यक्ष देकर वे अपनी राजनैतिक कुशलता को दर्शाया है।

हम आपको बता दूँ कि कभी सिकन्दरा विधानसभा क्षेत्र के दबंग के रूप में अपनी खास पहचान बना चुके गुड्डू यादव पिछले तीन बार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपनी पत्नी दुलारी देवी को सिकन्दरा के दोनो जिला परिषद् क्षेत्रों से रिकार्ड मतों से जिताते आये हैं और इस बार जब दुलारी देवी निर्विरोध जिला परिषद् सदस्य चुनी गईं तभी से स्पष्ट हो गया था कि इस बार जिला परिषद् अध्यक्ष के रूप में उनका मजबूत दावेदारी होगा। पिछली बार भी गुड्डू यादव की पत्नी दुलारी देवी जिला परिषद् अध्यक्ष के रूप में मजबूत दावेदार थी पर पिछले बार जयप्रकाश नारायण यादव के भाई और जमुई विधायक विजय



राकेश पासवान
उपाध्यक्ष



सोनो प्रमुख और संतोष सिंह
की भाभी शीला देवी



संतोष सिंह

प्रकाश की पत्नी विनिता प्रकाश को अध्यक्ष बनाने के चाल में गुडडू यादव को झुकना पड़ा था। एन वक्त पर जयप्रकाश नारायण यादव और विजय प्रकाश दोना भाई गुडडू यादव के सिकन्दरा स्थित आवास पर पहुँच कर गुडडू यादव को मनाया था और विनिता प्रकाश जमुई जिला परिषद् अध्यक्ष चुनी गई थी। वे लगातार पाँच वर्षों तक जिला परिषद् अध्यक्ष पद को सुशोभीत करती रहीं और इस बार जिला परिषद् का चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया। वर्तमान में जयप्रकाश नारायण यादव के परिवार में सभी सांसद, विधायक, जिला परिषद् आदि पदों में अब पूर्व लग चुका है। लोगों को माने तो यह राजनीति के अतिमहत्वकांक्षा का ही परिणाम है कि आज जिले का एक मजबूत धुरी पूरी तरह से धरासयी हो चुका है। ऐसे में गुडडू यादव की पत्नी दुलारी देवी का जिला परिषद् अध्यक्ष के रूप में चुना जाना यादवों के एक मजबूत नेता के रूप में ला खड़ा कर दिया है। जैसे गुडडू यादव पूर्व में क्या थे और उनकी छवि क्या थी यह अब लोगों के बीच ये मायने नहीं रखता वर्तमान में गुडडू यादव के दुश्मन भी गुडडू यादव के बढ़ाई में कसीदे गढ़ते दिखाई देते हैं।

गुडडू यादव सिकन्दरा विधानसभा क्षेत्र के बेताज बादशाह रहे हैं। सिकन्दरा विधानसभा क्षेत्र में गुडडू यादव के बिना पर राजनीति का कोई महत्व नहीं रह जाता है। गुडडू यादव यादवों का क्षेत्र का सर्वमान्य नेता पिछले कई वर्षों से बने हुए हैं। इस बार गुडडू यादव अपनी पत्नी दुलारी देवी को निर्विरोध जीत दिलाकर यह साबित कर दिया था कि इस बार के जिला परिषद्

अध्यक्ष भी निर्विरोध दुलारी देवी ही बनेगी। गुडडू यादव इस दिशा में उसी दिन से तैयारी भी कर दिया था जिसमें शुरूआत से ही गुडडू यादव का शतरंज का चाल बिछनी शुरू हो गई और फिर शतरंज के सभी चाल सही निशाने पर बैठी और फिर चकाई के निर्दलीय विधायक और बिहार सरकार के मंत्री सुमित सिंह को भी गुडडू का सहयोग करना मजबूरी बन गया या फिर कहें एक मजबूत यादव नेता को अपने पाले में करना था। गुडडू यादव पंचायत चुनाव के शुरूआत से ही हर उस सख्त से बातचीत करते रहे और सहयोग तक करते रहे जो जिला परिषद् अध्यक्ष बनने में थोड़ा सा भी रोड़ा बन सकते थे। सुमित अपने हिसाब से उपाध्यक्ष के रूप में चकाई से जीत कर आये चिराग पासवान के सहयोगी रहे राकेश पासवान को निर्विरोध बनाने में कामयाब रहे।

आपको बता दूँ कि इस बार मानो निर्विरोध का बाढ़ देखा गया है जमुई जिले में। इस बार न सिर्फ जिला परिषद् अध्यक्ष-उपाध्यक्ष अपितु जिले के दसो प्रखंडों में हुए प्रखंड प्रमुख



रुबेन सिंह
बरहट प्रखंड प्रमुख

के चुनाव में जब किसी भी राजनेताओं का प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं रहा तो दस में से पाँच प्रखंड के प्रमुख भी निर्विरोध चुन कर आये हैं जो जिले के विकास को गति दे सकता है। निर्विरोध प्रखंड प्रमुख और जिला परिषद् अध्यक्ष बनना एक स्वस्थ राजनीति और जिले के विकास के लिए शुभ संकेत माना जा सकता है। इस बार जिले के दसो प्रखंडों में से कहीं भी विधायक या फिर बड़े नेताओं का खुले तौर पर हस्तक्षेप नहीं देखा गया। इसका दूसरा पहलू भी देखा जा सकता है जो यह है कि जिला परिषद् अध्यक्ष दुलारी देवी के पति गुडडू यादव कभी सिकन्दरा क्षेत्र के कुख्यात रहे थे तो वहीं लक्ष्मीपुर से प्रखंड प्रमुख बने बिंदु देवी के पति गुलाबी यादव भी कभी मोस्ट वांटेड रहे हैं तो वहीं सोनो से प्रखंड प्रमुख बने शीला देवी के देवर संतोष सिंह भी क्षेत्र के डॉन के रूप में पहचान बनाया था। यह दीगर बात है कि पिछले 10 वर्षों से ये तीनों अपने-अपने क्षेत्रों के प्रमुख समाजसेवी के रूप में पहचान बनाने में कामयाब रहे हैं। जिला परिषद् अध्यक्ष पति गुडडू यादव पिता बिशुनदेव यादव उर्फ मच्छड यादव साकिन सिकन्दरा का आपराधिक इतिहास में करीब 25 केश जिले के विभिन्न थानों में दर्ज है तो वहीं गुलाबी यादव पिता नारायण यादव उर्फ श्री यादव साकिन जिनहरा थाना लक्ष्मीपुर पर लक्ष्मीपुर, खडगपुर थानों में करीब 30 मामले तो वहीं संतोष सिंह पेसर सत्य नारायण सिंह सा10 मडरो थाना सोनो पर करीब 12 मामले अकेले सोना थाना में दर्ज है। सिकन्दरा, बरहट और जमुई में भी निर्विरोध प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख चुने गये हैं। चकाई एक मात्र ऐसा प्रखंड रहा है जहाँ

सुमित की पत्नी हो सकती है एमएलसी प्रत्यासी

सूत्र बता रहे हैं कि इतने सारे निर्विरोध जीत कर आने के पीछे का सच बिहार सरकार के सूचना प्रधोगिकि मंत्री और नरेन्द्र सिंह के बेटे निर्दलीय चकाई विधायक सुमित सिंह का पत्नी का एमएलसी चुनाव लड़ाने की मंशा है। हालांकि इस बात को सुमित भले ही नकार रहे हों पर सच्चाई यही है कि आने वाले एमएलसी चुनाव में सुमित मजबूत दावेदारी पेश कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चकाई से विधानसभा चुनाव में एमएलसी संजय प्रसाद जदयू के प्रत्याशी थे। संजय सिंह इस बार भी एमएलसी के दौड़ में शामिल हो सकते हैं। एमएलसी संजय प्रसाद से सुमित का 36 का रिस्ता रहा है। जबकि संजय प्रसाद का ललन सिंह से कॉफी नजदीकी रिस्ता है। सुमित यह साबित कर सकते हैं कि एमएलसी प्रत्यासी हमारे मनमुताबिक हो। यह कारण हो सकता है कि सुमित जमुई में जिला परिषद् अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख, उप मुखिया चुनाव में कॉफी दिलचस्पी लेते देखे गये हैं।



टॉस द्वारा प्रमुख चुना गया। चकाई 28 पंचायत समिति वाला प्रखंड है और जीत हार का अन्तर शून्य रहने के कारण टॉस से चकाई के प्रखंड प्रमुख बने हैं। जमुई प्रखंड से भी यही हुआ और

अंत-अंत में मात्र एक प्रत्यासी ही प्रखंड प्रमुख के लिए आवेदनकर्ता बनकर रह गये और निर्विरोध जीत दर्ज कर प्रखंड प्रमुख बने। बरहट प्रखंड से रूवेन सिंह चौथी बार प्रखंड प्रमुख बनने का

रिकार्ड बनाया है रूवेन सिंह पूर्व विधायक सुशील कुमार सिंह उर्फ हीरा जी के सुपुत्र हैं। अब देखना यह होगा कि निर्विरोध जीतने के बाद प्रखंड और जिले के विकास की गति कितना रंग लाता है। ●

ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठ से भगवान के कतार में हो गये आईपीएस लांडे

● के.एम. राज

कि

सी ने ठीक ही कहा है आशां है भगवान बनना मुरत में मन भर कर, मुश्किल है इंसान बनना और बनकर जीने में लेकिन आश्चर्य तो तब होता है जब जीते जी अपने कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से कोई शख्स भगवान के कतार में खड़े हो जाए और देखते ही देखते लोग में उसकी तस्वीर खरीदने की होड़ दिखने लगे यही वाक्या आज लौहनगरी के सदर बाजार के फोटो फ्रेम की एक दुकान में देखने को मिली। जहां एक अनार सौ बीमार वाली कहावत को चरितार्थ

वाले ने देश के चर्चित आईपीएस ववन राव शिवदीप लांडे की एक स्केच विरन के पास फोटो फ्रेम के लिए दिया लांडे के व्यक्तित्व से



अनभिज्ञ दुकानदार ने स्केच को फ्रेम कर भगवान की कतार में खड़ा कर दिया जो उसके लिए सिरदर्द बन गया क्योंकि उस तस्वीर को खरीदने

और देखने के लिए दुकान के पास 2 दिनों से युवाओं की भीड़ जमा होने लगी और लोग मोलतोल करने लगे इस बाबत जब दुकानदार से बात हुई तो उन्होंने बताया कि मैं नहीं जानता था कि ये कौन है लेकिन दर्जनों युवक दो दिनों से रोज आते हैं और कहते हैं लांडे साहब की तस्वीर कितनी की है मेरे मना करने पर कि यह विक्री की नहीं है तो कोई पंद्रह सौ कोई दो हजार कोई तीन हजार दे तस्वीर देने की जिद करते हैं जिससे परेशान मैंने आज इस तस्वीर को हटाने का फैसला कर लिया था लेकिन फिर सोचा कि अगर इनकी तस्वीर मुझ गरीब को कोई दे दे और मैं फ्रेम से सजा कर इन्हें बेचू तो मेरे घर में भी मेरे बच्चे दो जून की रोटी आराम से खा सकेंगे और मैं भी अपने बच्चो इनके जैसा बना सकूंगा। ●